हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 जून, 2005

खण्ड 2, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 17 जून, 2005

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1
वाक-आउट	9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	9
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	13
मुख्य मन्त्री द्वारा घोषणा	26
वाक-आउट	30
ध्यानाकर्ष प्रस्ताव	31
सरसों की फसल तथा अन्य खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति सम्बन्धी वक्तव्य	32
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा विधान कार्य—	36
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2005	
बैठक का समय बढ़ाना	68
विधान कार्य—	68
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2005 (पुनरारम्भ)	
बैठक का समय बढ़ाना	75
विधान कार्य—	75
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2005 (पुनरारम्भ)	

मूल्य : 100

MVS/Wib (4)

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 17 जून, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस०चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Number of Pensioners of Municipal Committees

***30. Sh. Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) whether pensioners of Municipal Committees in Haryana State are getting their pension regularly; and

(b) if not, the reasons thereof togetherwith the total strength of such pensioners at present in the State?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) : (a) & (b) Retired employees of Municipalities are paid pension from the Pension Fund established in 1993. State Government does not make any contribution to this Fund. The Municipalities which have to make regular monthly contribution to the Fund, are unable to do so, due to their poor financial health. Also, the liability towards payment of pension to the 3977 pensioners as on date is more than Rs. one crore per month, whereas the total monthly contribution from municipalities is only around Rs. 30 lakhs. Due to these reasons, payment of pension to retired municipal employees often gets disrupted. However, the Government has taken measures to clear the pension dues of retired employees upto 30-4-2005.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि टोटल इम्पलोईज जो रिटायर हुए हैं या जो पैशनर्ज हैं उनकी संख्या 3977 है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह पैंशन सभी म्यूनिसिपिल कमेटियों के पैंशनर्ज को दे दी गई है और यह पैंशन कब तक दी गई है ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि किस-किस म्यूनिसिपिल कमेटी में यह पैंशन दी गई है और कब तक की पैंशन दी गई है। क्या किसी म्यूनिसिपिल कमेटी में कोई ऐरियर बकाया है और यदि बकाया है तो वह कहां का और कितना ऐरियर बकाया है ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो सप्लीमैंट्री पूछी है उसका जवाब तो मैंने अपने रिप्लाई में पहले ही दे दिया है कि अप्रैल, 2005 तक सारी पेमैंट हो चुकी है और कोई ऐरियर बकाया नहीं है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: स्पीकर सर, मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया, इनके रिटन रिप्लाई में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, मैंने इनका अंग्रेजी में जो रिप्लाई दिया है वह पढ़ा है इसमें लिखा है कि 30 अप्रैल, 2005 तक ऐरियरज को पूरा कर दिया जाएगा लेकिन यह नहीं आया है कि कब तक कर दिया है।

श्री लछमन दास अरोड़ा : मलिक साहब, आप अपने पास हिन्दी वाला रिप्लाई पढ़ें उसमें दिया हुआ है कि 30 अप्रैल, 2005 तक का भुगतान कर दिया गया है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, अंग्रेजी के रिप्लाई में ऐसा नहीं दिया हुआ है। स्पीकर सर, मन्त्री जी का जो जवाब आया है उसके मुताबिक ऐरियर का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि सभी नगरपालिकाओं की डयूटी लोगों की सेहत बनाने की है लेकिन उनकी अपनी आर्थिक सेहत खराब हो रही है। बाहर से हम पैसा नहीं ले सकते हैं और म्यूनिसिपिल कमेटियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपना काम चला सकें। उनके पास केवल 30 लाख रुपये तक का प्रावधान है जबकि पैंशन की राशि करीब एक करोड़ रुपये बनती है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के जो सोर्स ऑफ इन्कम हैं वे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स हैं क्या इसके अलावा उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इन्कम है या नहीं ? इसके साथ ही साथ मन्त्री महोदय, इस बात का भी जवाब देने की कृपा करें कि कितनी नगरपालिकाओं की जमीन पर नाजायज कब्जे हैं । पिछली सरकार के दौरान सरकार ने अपने चहेतों को नगरपालिकाओं की जमीनें Throw away prices पर बेच दी थी या उनके नाम ऑक्शन की गई दिखाई हैं। क्या सरकार की इस किस्म की कोई सोच है कि सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जाए ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय साथी मलिक साहब ने जो सवाल पूछा है उसका इस मेन सवाल से कोई वास्ता नहीं है। इनका यह सवाल म्यूनिसिपिल कमेटीज़ की इन्कम और उनकी फाईनैंशियल पोजीशन के बारे में है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम साधन जुटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त भी हमारे साधन जुटाने का काम सही हो जाएगा उस वक्त हम सारी स्थिति एक्सप्लेन कर देंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी म्यूनिसिपिल कमेटी के आफिसर्ज को सख्त हिदायत देंगे कि पैंशन देने में उनका कन्ट्रीब्यूशन का शेयर बनता है वह वे जमा करवायें। स्पीकर सर, करनाल जैसी म्यूनिसिपिल कमेटी में पैसे की कमी नहीं है। उनके पास बहुत हाउस टैक्स आता है। वे बाकी के काम करने को तो तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनको कमिशन मिलता है लेकिन वे एम्पलाई की पैंशन के शेयर को भेजते नहीं है। स्पीकर सर, करनाल म्यूनिसिपिल कमेटी के रिटायर लोगों को पिछले चार-पांच महीने से पैंशन नहीं मिली है। इस बारे में मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मैंने अपने जवाब में पहले ही बता दिया है कि 30 अप्रैल, 2005 तक सभी की पैंशनज़ क्लीयर कर दी गई है और दूसरे पैसा जमा करवाने वाली जो बात इन्होंने कही है तो ऐसी कोई हिदायत नहीं है।

वित्त मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्यों को सदन में यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बजट के कैपिटल हैड में और हैल्थ के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया है। यह प्रावधान पिछले 40 सालों में जब से हरियाणा बना है पहली बार हमारी सरकार ने ही किया है।

Sarv Shiksha Abhiyan

*74. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the yearwise and headwise budget allocated and actual expenditure incurred on the Sarv Shiksha Abhiyan Project since its inception till March, 2005 ; and

(b) whether any complaint regarding misappropriation or embezzlement in funds of the Sarv Shiksha Abhiyan Project referred to in part (a) above was received by the Government; if so, action taken thereon?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) :

(a) A statement is placed on the table of the House.

(b) Yes Sir, a statement showing the complaints received and the action taken thereon is placed on the table of the House.

Statement 'A'

Yearwise & Headwise Budget Allocation & Actual Expenditure incurred on Sarv Shiksha Abhiyan Project

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Name of Activity	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		Budget	Expenditure	Budget	Expenditure	Budget	Expenditure
1.	Teacher Salary	515.70	317.78	1095.36	630.84	2490.26	1855.01
2.	Block Resource Center	1037.84	3.63	1212.62	149.18	1811.73	580.65
3.	Cluster Resource Center	114.73	0.00	143.58	14.25	154.18	37.19
4.	Civil Works	1464.24	511.59	4396.83	3480.69	6654.75	3907.90
5.	Intervations for out of school children	174.41	0.00	317.04	0.00	3315.40	80.59
6.	Free Text Books	734.78	816.81	1687.83	1044.48	2251.44	1170.68
7.	Innovative Activities	749.91	217.39	1229.57	803.98	950.00	689.01
8.	Intervation for disabled Children	170.38	8.30	342.58	77.46	341.32	122.18
9.	Intervations for girl children (NPEGEL)	0.00	0.00	115.59	53.83	524.12	269.73
10.	Maintenance Grants	420.20	415.79	610.60	611.85	639.05	626.07
11.	Management	233.72	8.33	719.20	231.98	1069.94	484.60
12.	Research and evaluation	177.17	0.00	191.10	6.80	183.13	11.38
13.	School Grant	124.62	92.27	273.06	244.51	261.58	256.74
14.	Teachers Grants	245.41	144.13	331.23	283.86	389.95	301.24
15.	TLE	1409.30	23.82	1462.01	1090.43	537.93	216.08
16.	Teacher Training	546.01	176.51	932.06	386.93	1126.45	738.69
17.	Community Mobilization	19.98	1.00	33.55	7.35	32.46	11.37
	Total	**8138.40**	**2737.35**	**15093.81**	**9118.42**	**22683.69**	**11359.11**

Statement 'B'

Sr. No.	Against whom	Main allegations in regard to SSA funds	Action taken
1	2	3	4
1.	Sh. Satpal Singh Malik DEO cum DPC SSA Jind (Now retired)	i. Regarding purchase of Computers ii. Embezzlement of SSA funds	On preliminary inquiry it was found that the computers are purchased through HARTRON-Charges could not be substantiated-hence no action taken.
2.	Sh. Taqdeer Singh Block Education Officer Bawani Khera	i. Asking for commissions for release of SSA funds.	On preliminary inquiry charges were not proved; hence no action was taken.
3.	Sh. Bijender Singh Principal GSSS Buddin Mahender-garh holding the charge of Block Education Officer ——Satnali	i. Teacher grant of Rs. 500/- given in the form of school kit costing about Rs. 70/- to Rs. 80/-, instead of Rs. 500/- in cash as provided in the guidelines.	On preliminary inquiry charge was proved. The charge sheet under Rule 7 to be served to the officer is being vetted by L.R.
4.	Sh. Jai Singh Head Master GHS Chitrauli (Mahendergarh) holding the charge of Block Education Officer-Kanina	i. Teacher grant of Rs. 500/- given in the form of school kit costing about Rs. 70/- to Rs. 80/-, instead of Rs. 500/- in cash as provided in the guidelines.	On preliminary inquiry charge was proved. The officer has been charge sheeted under Rule 8.
5.	Sh. S.S. Makkar Head Master Sh. Ramesh Kumar Maths Master & Sh. Ashish Kumar Drawing Teacher, GHS Bahadurpur (Yamuna Nagar)	i. Theft, misuse of computers and change of part	On inquiry charges proved were (i) unauthorised use of computers (ii) repairs got done during warranty period. Further inquiry into the allegations is in progress.

1	2	3	4
6.	Sh. R.C. Dahiya DEO cum DPC SSA Faridabad	i. Misutilisation of school grant of Rs. 2000/- and Teacher grant of Rs. 500/- per teacher. ii. 125 bogus AIE centres have been established. iii. Purchase of Computers worth Rs. 40 lacs. iv. Purchase of Air Conditioners for office use v. Purchase of durries/black board, steel almirah, chairs and stationery items of low quality. vi. Supplying of first-aid kit at a cost of Rs. 1400/- which actually costs Rs. 140/- vii. Purchase of geometry box at a cost of Rs. 2500/- which costs only Rs. 260/- viii. Purchase of Bhagon Rs. 1850/- though the market value is only Rs. 500/-	On preliminary inquiry allegation No. i, iv, v, vi, vii, viii have been proved. The material has been purchased from unapproved sources and the quality is poor. As regards allegations No. ii the opening of centres in excess, procuring material from Faridabad Consumer Co-operative Store, Faridabad and selection/salary paid to the volunteers was not in order. Sh. R.C. Dahiya DEO-cum-DPC SSA Faridabad has been placed under suspension. Charge Sheet is under preparation.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो जवाब इन्होंने सदन की पटल पर रखा है अगर उसमें मंत्री जी देखेंगे तो ये पाएंगे कि इतना बड़ा बजट सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इनके विभाग के लोगों तक पहुंचाया जाता है और जिसका पूरा उपयोग पिछले कई सालों से इनका विभाग नहीं कर पाया है। क्या आने वाले समय में मंत्री जी ऐसा आश्वासन सदन में देंगे कि जिस हैड में जितना पैसा दिया जाता है उसका पूरा-पूरा प्रयोग किया जाएगा। स्पीकर सर, सामान की खरीददारी जिन फर्मों से की जाती है, उन फर्मों से सामान खरीदने की एप्रूवल किस ने दी और उन फर्मों को एप्रूवल देने के लिए क्या क्या मान्यताएं थीं। इसके साथ ही स्पीकर सर, मंत्री जी ने जवाब में जो एम्बैजलमैंट के बारे में बताया है तो क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि सर्व शिक्षा अभियान का पैसा पिछली सरकार के वक्त में चौधरी देवी लाल ट्रस्ट को दिया गया था।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने सप्लीमैंटरी पूछी है कि सर्व शिक्षा अभियान के हैड में जो पैसा था वह पूरा प्रयोग नहीं हुआ था। स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को यह

[श्री फूलचन्द मुलाना]

बताना चाहूंगा कि यह योजना 2002-03 में प्रारम्भ हुई थी और इस योजना के तहत सरकार को 81 करोड़ रुपया मिला था। इसमें 75 प्रतिशत अमाउन्ट केन्द्र की सरकार का था और 25 प्रतिशत अमाउन्ट हरियाणा गवर्नमैंट का था। मुझे सदन में खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने उस पैसे का पूरा प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने टोटल अमाउन्ट में से सिर्फ 27 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। इसके लिए पिछली सरकार ही कसूरवार है कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के काम में कोई हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर सर, भविष्य के लिए हमारी सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी चिन्तित हैं कि पिछले पांच सालों में हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसको कैसे ऊपर उठाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान इसलिए है कि जब बच्चे स्कूल में जाएं तो वहां पर उनके लिए कमरों का, पीने के पानी का और शौचालयों का प्रबन्ध हो। दूसरे जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का पैसा चौधरी देवी लाल ट्रस्ट पर खर्च किया गया है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास इस विषय में कोई पार्टिकुलर शिकायत है तो ये हमें उस बारे में लिखकर दे दें, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। स्पीकर सर, इसके अलावा स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राईमरी स्कूलों को मिडिल तक अपग्रेड करने के लिए कंडीशंज होती हैं और हम उन कंडीशंज को पूरा करके सर्व शिक्षा अभियान के इस पैसे का पूरा प्रयोग करेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने रिटन रिप्लाई के पार्ट ए में चार्ट दर्शाया है, उस चार्ट की स्टेटमैंट में Yearwise & Headwise Budget Allocation & Actual Expenditure incurred on Sarv Shiksha Abhiyan Project लिखा है। इस स्टेटमैंट में इतना ज्यादा डिस्मल है कि जिसकी वजह से बेहताशा नुक्सान हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे मद हैं जैसे कि फ्री टैक्स्ट बुक्स का मद है इसमें पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ है। ऐसे ही Innovative Activities का मद है। पिछली सरकार को इस बारे में पता ही नहीं था। Dishonesty की Innovative Activities तो उन्होंने बहुत इजाद की, उनका इसी तरफ ही ध्यान था। शिक्षा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप देखेंगे कि पिछली सरकार द्वारा 2002-2003 में Interventions for disabled children के मद में 170.38 लाख रुपये में केवल 8 लाख 3 हजार रुपये ही खर्च किये गये हैं और अगले सालों में तो इससे भी बुरा हाल है। इसके बाद Interventions for girl children के मद में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2003-2004 में 115.59 लाख रुपये में से केवल 53.83 लाख रुपये ही खर्च किये गये और 2004-05 में 524.12 लाख रुपये में से भी बहुत कम पैसा खर्च किय गया है। इसी प्रकार से टीचर्ज की ग्रांटस हो या चाहे स्कूलों की ग्रांटस हो, इनमें भी बहुत भारी नुक्सान किया गया है, पूरा पैसा प्रयोग नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि जो रुपया खर्च नहीं हुआ है क्या उसके बारे में हमारी सरकार फिर से गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को कोई रिप्रैजेंटेशन देकर उस पैसे को रिट्रीव करवा सकती है ? क्या हम उनको दोबारा से कह सकते हैं कि इसमें जो पैसा उस वक्त की सरकार ने खर्च नहीं किया था उस पैसे को अब दोबारा से और ज्यादा पैसा इन मदों में एलोकेट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रिप्लाई के पार्ट बी में शिकायतों के बारे में कहा गया है। वे शिकायतें बहुत गंभीर हैं। मैं केवल लास्ट शिकायत जो श्री आर०सी०दहिया, डी०ई०ओ०-कम-डी०पी०सी०, एस०एस०ए०, फरीदाबाद के बारे में हैं, कहना चाहूंगा। यह तो इसमें कमाल ही है। इससे on preliminary inquiry misutilisation of school grant of

Rs. 2000/- and teacher's grant of Rs. 500/- per teacher, 125 bogus AIE centers have been established, purchase of Computers worth Rs. 40 lacs, Purchase of Air Conditioners for office use, purchase of durries/black board, steel almirah, chairs and stationery items of low qualities, supply of first-aid kits, purchase of geometry boxes and purchase of Bhagon etc. इन सब चीजों में घोटाला है। On preliminary inquiry allegations No. I, IV,V, VI, VII, VIII have been proved. The material has been purchased from unapproved sources and the quality is poor. As regards allegation No. II, the opening of centres in excess, procuring material from Faridabad Consumer Co operative Store is not in order. मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह सारा घोटाला अकेला डी०ई०ओ० नहीं कर सकता। पूरे हरियाणा में जो और डी०ई०ओज० या दूसरे इसके इंचार्ज थे और उनके साथ राजनैतिक लोग जो उस समय पावर में थे, वे सब भी इस घोटाले में मिले हुए थे। क्या सरकार इस सबकी इंक्वायरी करवाएगी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और इन सालों में कितना कितना रुपया किस किस ने खाया ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य बहुत सीनियर हैं और उन्होंने बहुत ही रैलेवैन्ट सवाल पूछा कि जो पैसा आया उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में तो मैंने पहले ही अपने उत्तर में बताया है कि पिछली सरकार की जो इंटैशन थी वह शिक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं थी Education was a neglected factor. इसलिए उस वक्त सुजैशन पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब हमने योजनाएं बनायी हैं और जो परपज इस योजना का है उसको पूरा किया जाएगा तथा पैसे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे इन्होंने कहा कि जो पैसा लैप्स हो गया उसके लिए क्या दोबारा से उस पैसे को वापस लाने की चेष्टा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सारा पैसा लैप्स नहीं होता है कुछ पैसा कैरी फारवर्ड हो जाता है और कुछ पैसा लैप्स हो जाता है। कैरी फारवर्ड वाला पैसा हमारे पास है और लैप्स वाले पैसे के लिए हम योजना में डालकर दोबारा से प्रयोग करने की पूरी चेष्टा करेंगे। तीसरी बात इन्होंने यह कही कि कुछ अधिकारी बहुत ही गंभीर आरोपों में संलिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है मि० आर०सी० दहिया, डी०ई०ओ० ने काफी सारी अनियमितताएं की हैं इसलिए उनको सस्पैंड कर दिया गया है उनके खिलाफ चार्जशीट भी फ्रेम हो रही है और जल्दी ही उनको चार्जशीट इश्यू की जाएगी क्योंकि इस बारे में बाकायदा इंक्वायरी हो चुकी है । इसी तरह से दूसरे अधिकारियों की अनियमितताओं के जो केस हमारे नोटिस में आये हैं उनको भी हम देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दो और अधिकारियों को ससपैंड किया गया है। मैं इस बारे में सदन में कहना चाहूंगा कि जिन-जिन के खिलाफ आरोप लगे हैं उनके बारे में सारी नियमित जांच की जाएंगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं इसके साथ ही मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ में चौधरी देवी लाल ऐक्सीलैंस सैंटर खोला गया है। उसमें ईंट और अन्य मैटीरियल जैसे रारिया, लोहा, सीमेन्ट आदि जितना भी लगा है उस पर वह पैसा सर्वशिक्षा अभियान के पैसे में से लगा है जबकि वह पैसा गरीब लोगों पर खर्च होना था। पिछली सरकार ने वह पैसा ऐक्सीलैंस सैंटर पर खर्च किया है, अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के नाम से सरकार के पास एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि गांवों में या शहरों में जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, इस अभियान के तहत 25 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक की नियुक्ति की जा सकती है जिसके लिए पैसा गवर्नमैंट इस अभियान के तहत देती है। हमारे यहां गांवों में और शहरों में बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

नौजवान बैठे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गांवों में और उन 25 बच्चों के ऊपर उन बेरोजगार युवकों को पढ़ाने का काम देंगे और उन्हें एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार या 3 हजार रुपये का मासिक वेतन उस सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत देने का आश्वासन देंगे ? अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जैसा मैंने इनसे पहले भी पूछा था कि जो खरीददारी इनका विभाग करता है जैसे साबुन, तेल पैंसिल, साइकिल और न जाने किन-किन चीजों की खरीद जिन-जिन फर्मों से की जाती है उन फर्मों को कैसे अप्रूव करते हैं कि कौन सा सामान कहां से खरीदा जाएगा ?

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन सवाल पूछे हैं एक तो यह कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके ऊपर पढ़े लिखे बेरोजगार टीचर रखे जाएं। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह योजना हमारी है और हम आल्टरनेटिव इन्नोवेटिव ऐजूकेशन सैंटर और ऐजूकेशन ग्रांट स्कीम में हम कुछ अध्यापक रखते हैं ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको शिक्षा दी जा सके यही इस योजना का उद्देश्य भी है । जहां तक उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है, तो यह प्रावधान इस योजना में नहीं है। यह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो नीतियां उनकी होंगी उसके मुताबिक ही किया जाएगा। तीसरी जो बात खरीददारी की कही है, तो इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह हमारे अप्रूव्ड सोर्सिज हैं उनसे ही सामान परचेज करते हैं। उनके बाहर के सोर्स से जो कोई भी सामान खरीदता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी सुरजेवाला साहब ने इस बारे में कहा था कि इसमें कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ भी है तो इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि वह हाथ अगर साबित होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कुछ नॉन गवर्नमैंट आर्गेनाइजेशंज काम करती है। क्या उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। क्या इन एन०जी०ओज० को भी इस फंड में से कोई पैसा दिया जाता है क्योंकि उनकी बहुत सी शिकायतें हैं कि वे सब पैसा खा जाते हैं और किसी अन्य प्रोजैक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एन०जी०ओज० को भी गवर्नमैंट किसी प्रकार की ग्रांट देती है।

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान में एन०जी०ओज० का कोई रोल नहीं है और न ही उनको यह सैंटर चलाने के लिए ऐसोसिएट किया जा सकता है। कई और प्रोग्राम्ज हैं जो एन०जी०ओज० चलाते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जो भी कोई इस तरह के प्रोग्राम्ज चलाना चाहे, उसको मंजूरी दी जाती है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ में चौधरी देवी लाल ऐक्सीलैंस सैंटर में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा लगाने की लोगों की शिकायत है और लोगों में चर्चा है क्या आप उसकी जांच कराएंगे कि चंडीगढ़ में उस अभियान से देवी लाल ऐक्सीलैंस सैंटर में सर्व शिक्षा अभियान का कितना पैसा लगा है ?

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पैसिफिक ऐलीगेशन लगाया है। ये बताएं कि फलां व्यक्ति ने फलां जगह से इतना पैसा निकाला है और फलां जगह लगाया है तो हम उसकी पूरी जांच करवाएंगे।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य है कि चौधरी देवी लाल ऐक्सीलैंस सैंटर में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा लगा है।

Mr. Speaker : That is not the case. He is asking a supplementary, question.

वाक-आऊट

श्री बलवंत सिंह सढौरा : स्पीकर सर, ****

Mr. Speaker : Mr. Balwant Singh, you must know the rules, Nothing to be recorded. (Interruption)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, **** (Interruption)

Mr. Speaker : Do not try to please your Boss by raising the slogans here. I will not allow it. It is Questions Hour, let the question to proceed. If you like, you may walk out.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देते तो हम हाउस से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गये।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Construction of Road from Bass to Petwar Road

***Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to complete the construction work of the incomplete road from Bass to Petwar in Narnaund Constituency ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Yes, Sir.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पेटवाड़ से बास तक की सड़क पिछले 10-15 सालों से अण्डर कन्सट्रक्शन है । यह सड़क तीन किलोमीटर तक बनी भी हुई है कृपया मुख्य मंत्री जी बताएं कि यह सड़क कब तक बन जायेगी, 10-15 साल बाद बनेगी या जल्दी ही बन जायेगी।

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि यह सड़क 10-15 साल से लम्बित पड़ी है इनकी यह बात ठीक है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * **

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Please take your seat. Mr. Indora, I will not permit it.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह मामला काफी समय से लम्बित पड़ा था इस पर कुल खर्चा 89.67 करोड़ रुपए का आयेगा और यह बजट हमने एप्रूव कर दिया है और यह सड़क इस साल के अन्दर-अन्दर पूरी कर दी जायेगी। नारनौंद का हम पूरा ख्याल रखेंगे। इस सड़क को बनाने के लिए 500 मीटर के करीब जमीन भी शायद एक्वायर करनी पड़े, वह भी हम करेंगे।

Mr. Speaker : Gautam Ji, I think the entire question is over now.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, perhaps he wants to ask supplementary.

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसे बना देने का वायदा किया है। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु जो बाकी की सड़कें हैं जैसे ब्याना खेड़ा से डाटा खेड़ा है। उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि उनको भी जल्दी बनायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, श्री गौतम जी हमारे मित्र हैं और नारनौंद का हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि नारनौंद की मेरी मामी है और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की चाची है। नारनौंद की जो दूसरी 20 सड़कें और हैं उन पर दो करोड़ रुपये लगेंगे। इन सड़कों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और एक साल में उन सड़कों को बनवा दिया जायेगा। बाकी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या उस सड़क को इस साल के अन्दर-अन्दर बनवा दिया जायेगा, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि इस सड़क को इस साल के अन्दर बनवा दिया जाएगा।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा सवाल इस सवाल से हट कर है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नावा जो महेन्द्रगढ़ में है वहां से नांगलभलाल जो सड़क जाती है उस पर कार्य शुरू हो गया था लेकिन बीच में ही बन्द हो गया । क्या मंत्री जी उस सड़क का काम दोबारा से चालू करवायेंगे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, कनीना से अटेली जो सड़क जाती है वह आगे जाकर नेशनल हाईवे पर बहरोड़ के पास मिलती है।

Mr. Speaker : Listen, be relevant. No one is a computer. No one can reply regarding the entire State. Whenever there is a question, you should be relevant to that particular question. Next question, please.

Check the Migration of Villagers

*91. **Shri Ranbir Singh Mahindra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) steps being contemplated by the Government to check the migration of villagers to the urban areas; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide basic urban facilities to the villages at the State expenses; if so, the details thereof ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): (a) & (b) Sir, a statement is placed on the table of the House.

Statement

The primary reason of migration of rural people to the urban areas is in search of job opportunities because the urban areas offer more employment opportunities as compared to the rural areas. The second reason of migration is the better health and sanitation facilities because in urban areas the qualified Doctors are available to cater to the medical needs of the people. The better schooling as compared to the rural areas is another major factor for migration from rural areas to the urban areas. The adequate supply of drinking water, the pucca roads, the availability of power and better sanitation facilities are some other factors which attract rural people to the urban areas. The inhabitants of the village feel the upgradation of their status by enjoying these facilities in the urban areas and hence the migration.

In order to arrest the rural migration, the State Govt. has announced a new Industrial Policy in which it is proposed to set up Small Scale and Cottage Industries in the rural area which would provide ample opportunities of employment to the rural people. The Government also has a proposal to implement the Mukhya Mantri Grameen Rozgar Yojana to boost industrialist in the rural areas so as to provide employment to the rural youth. All the villages in the State are well connected with the pucca roads and adequate supply of electricity is available in the rural sector. In order to cater to the medical needs, the Health Sub Centers and PHCs are functioning with highly qualified Doctors with the result that the rural people have not to rush to the urban areas for ailments. In the rural areas, adequate drinking water supply is being made available and that too through the taps. Every village has got the primary school and in many cases even the High/Higher Secondary

Schools and the Govt. is taking steps to fill up the vacant posts of the teachers and impart the teaching of English right from the First class. In many rural areas of the State even the Post Graduate Colleges/ Vocational Training Centres are running which prepare the rural youth for better employment. These facilities will go a long way to arrest the migration of the rural people to the urban areas.

Shri Ranbir Singh Mahendra : Mr. Speaker Sir, I would like to know from the Chief Minister as to what steps Government has taken to check the migration of villagers from rural areas to urban areas and whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide facilities to the villages such as drinking water and is there any plan to provide fresh connections to each and every house in the villages ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : यस सर, इस बारे में जो श्री महेन्द्रा जी ने पूछा है के बारे में हमारा प्लान है और हम इस पर चल रहे हैं। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट यह कार्य करता है । अध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में Provision of drinking water for rural areas के लिए 212 करोड़ रुपया रखा गया है। और Augmentation of water supplies के लिए 43 करोड़ रुपये रखा गया है।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जब से सैशन आरम्भ हुआ है तब से पब्लिक हैल्थ, पी०डब्ल्यू०डी०, शोर्टेज आफ स्टाफ इन स्कूल, इन सब के बारे में इफैक्टिव स्टैप लिए जा रहे हैं and effective steps have been taken to provide Doctors in the hopitals and PHCs जैसा कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद कहा था कि बहुत सी पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० ऐसी हैं जहां पर डाक्टर्ज नहीं हैं। क्या वहां पर डाक्टर्ज की कमी को पूरा करने बारे सरकार विचार कर रही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि डाक्टर गांव में जाएं सरकार डाक्टरों को और स्पैशलिस्टस को पी०एच० सीज० और सी०एच०सीज० में लगा रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचें।

Setting up of New Power Projects

*105. **Shri Susbil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up new power project in the State in near future; and

(b) if so, details thereof ?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

The Government is planning to take up or facilitate the following power projects in the State :—

Sr. No.	Name of Gas Based Power Project	Capacity	Tentative year of Commissioning.	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Yamuna Nagar Coal Based Thermal Power Project.	2X300 MW	2007-08	The Project is being implemented with an estimated cost of Rs. 2338 Crore on turnkey basis.
2.	Faridabad Gas Based Power Station Stage-II	432MW	2007-08	This will be an extension of the existing Faridabad Gas Based Power Station. NTPC would execute this. Matter has been taken up with Government of India.
3.	Hisar Gas Based Thermal Project	500 MW-1000 MW	2009-10	Land is already acquired. Joint venture partnership with private party would be considered. It may be noted that in case firm supply of gas cannot be arranged, this project would be preferred as an imported coal based project.
4.	Yamuna Nagar Gas Based Thermal Power Project Stage-II	500 MW-1000 MW	2008-09	Planned next to the proposed Coal Based Thermal Power in Yamuna Nagar. Dedicated gas pipeline would be required . Stage-I could be 500 MW with Stage-II at 1000 MW.
5.	Gas Based Power Project in Jhhajjar District located closed to Gurgaon.	1000 MW	2007-08	This is being promoted by Tata Power Co. /North Delhi Power Ltd. (NDPL). Consultants for the project have been appointed. Action for infrastructure development is being taken. Possibility of equity participation by Government is being considered.

1	2	3	4	5
6.	Gas Based Power Project Faridabad	1060 MW	2007-08	This project is being promoted by Aban Liyod Ltd. based in Chennai. Land and water source Located near have been identified and village Chhainsa enhanced gas fuel tie up is being attempted.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 6 प्रोजैक्ट ऐसे हैं जो कि 2007,2008 या 2009 से शुरू होने हैं। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के अभिभाषण में कहा था कि बिजली आर्थिक संरचना का मजबूत ढांचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज वर्तमान में हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है और क्षमता के अलावा जो लागत है वह कितनी है। अगर क्षमता कम है, लागत ज्यादा है तो किन-किन साधनों से उस आपूर्ति को पूरा करेंगे।

Mr. Speaker : Every body knows it. You, put the supplementary please. This question is regarding new projects. पिछले कितने हैं, It is not possible to explain इसलिए नए प्रोजैक्ट के बारे में ही पूछें।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली क्षमता की ही बात कर रहा हूं कि नए प्रोजैक्ट जो लगाए जा रहे हैं उनकी बिजली की क्षमता क्या है, उनकी लागत क्या है, ये प्रोजैक्ट कब तक पूरे कर लिए जाएंगे और किन साधनों से पूरे किए जाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने 2008-2009 से इन प्रोजैक्ट्स के शुरूआत होने की बात की है डा० साहब, आप जवाब में देखें कि उसमें शुरूआत करने की नहीं बल्कि टैन्टेटिव कमीशनिंग का टाईम बताया गया है कि उस समय तक अगर योजना ठीक से चलती रही तो ये प्रौजेक्ट कमीशन हो जाएंगें। ये 6 प्रोजैक्ट जो हमने दिए हैं वे हैं यमुनानगर, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर फेस 2, झज्जर और फरीदाबाद। फरीदाबाद का गैस बेस्ड प्रोजैक्ट है। इसमें जैसा कि आपने कहा कि बिजली की आज बहुत जरूरत है। उतनी बिजली आज हमारे पास नहीं है और इसकी मांग बढती ही जा रही है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये सारी स्कीमें, जैसे पावर जनरेशन किस-किस तरह हो सकता है, आपके सामने रखी हैं। बिजली की आज बहुत भारी समस्या है। आज के दिन सभी सोर्सिज से हमें 4000 मैगावाट बिजली मिल रही है तथा 1000 मैगावाट बिजली और मिलने की उम्मीद है। हम यह बिजली अलग-अलग सोर्सिज से ले रहे हैं। इसके अलिरिक्त हम हिमाचल प्रदेश से भी और बिजली लेने के लिए 30 जून को समझौता करेंगे ताकि आने वाले पैडी सीजन में किसानों की बिजली की मांग पूरी कर सकें। बिजली की कमी के कारण गांवों में भारी कट लगते थे, लेकिन आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हमने दो दिन पहले फैसला लिया है कि गांवों में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक और दिन में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजली बिना कट के दी जायेगी। पीक लौड पर कई दफा 5000-5000 मैगावाट बिजली सप्लाई करते हैं जबकि प्रदेश की बिजली जनरेशन 1587 मैगावाट है।

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, I would request the Chief Minister whether any efforts are being made towards power generation by wind mills, wherever feasible ?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Yes Sir.

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज बिजली हमारे प्रदेश में कुछ महंगी है जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। क्या सरकार ऐसे प्रोजैक्ट्स लगाने का प्रावधान कर रही है जिनमें बिजली की उत्पादन लागत कम हो ताकि हम प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली दे सकें और उनके बिजली के बिल कम आयें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि जो बिजली हम खरीद रहे हैं वह महंगी खरीदते हैं और हमारी सरकार उसमें सबसिडी देकर किसानों को सस्ती बिजली दे रही है। जहां तक ऐसे प्रोजैक्टस की बात है, जिनमें बिजली उत्पादन में कम खर्चा आये, इस तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं कि हरियाणा में नये जनरेशन प्रोजैक्टस लगायेंगे। फरीदाबाद में जो 432 मैगावाट का गैस बेस्ड प्लांट है, उसमें 75 प्रतिशत बिजली गैस से उत्पन्न होती थी और 25 प्रतिशत बिजली नेफ्था से उत्पन्न होती थी। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले हरियाणा सरकार ने उस प्लांट का फुल्ली गैस बेस्ड करने का उद्घाटन किया है। यानि अब हमने इस प्लांट से जो 100 प्रतिशत बिजली लेनी है वह पूरी की पूरी बिजली गैस उत्पादन से ही लेनी होगी। इस प्रोजैक्ट से अब हमें 108 मैगावाट अधिक बिजली मिलेगी और इसकी लागत भी कम आएगी।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाईडल प्रोजैक्टस से बनने वाली बिजली सस्ती होती है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले पांच साल में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के शू हिमाचल प्रदेश में जो हाईडल प्रोजैक्ट हैं उनमें हिस्सेदारी लेने के लिए कोई प्रयास किया या नहीं किया ?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, it is not a part of this question.

Wild Animals

*96. **Shri Arjun Singh :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that the crops are badly affected by the wild animals like wild pig and antelope (Roz) in the State ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to catch and send the aforesaid animals in a protected area ?

Excise & Taxation and Forest Minister (Shri Venod Kumar Sharma) :

(a) Sir, there is some damage to crops by wild animals like wild pig and antelope (ROZ) in the State although exact data is not available with regard to extent of damage.

(b) No Sir.

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी समझ में ही नहीं आया कि मन्त्री जी ने जवाब में क्या कहा है। दूसरी बात यह है कि क्या हमारी किस्मत में नो सर ही सुनना रह गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली और सड़क का सवाल किया तो जवाब मिला नो सर, स्कूल कॉलेजों के बारे में सवाल किया तो जवाब मिला नो सर । अब जंगली जानवरों के बारे में सवाल पूछा है तो यहां पर जवाब मिला नो सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे नाम पर केवल नो सर ही लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है और वहां पर लोग एक या डेढ़ किल्ले की जमीन से ही गुजारा कर रहे हैं और वे लोग इन रोजों की वजह से बहुत परेशान हैं। क्या मन्त्री जी हिन्दी में बताएंगे कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में क्या कहा है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, मेरी समझ में यह बात नहीं आई की मेरे रिप्लाई में से इनको क्या समझ में नहीं आया, मेरे विचार से यह नो सर का मतलब तो समझते ही होंगे।

चौ० अर्जन सिंह : स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है कि इनकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। इन्होंने कहा है नहीं, श्रीमान जी (विघ्न)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, रोज की समस्या वाईल्ड लाईफ डिपार्टमैंट के लिए बहुत भारी समस्या है। दरिया के साथ जो बैल्ट है यह जानवर केवल वहीं पर नहीं रहता है बल्कि सारे हरियाणा में ही यह जानवर एक गम्भीर समस्या बना हुआ है। रोज केवल फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि कई बार बच्चों और आदमियों पर भी यह हमला कर देते हैं। मेरे अपने हल्के में रोज ने एक बूढ़े आदमी पर हमला करके उसको मार दिया था। स्पीकर सर, फोरेस्ट डिपार्टमैंट के पास केजिज़ तथा मोबाईल केजिज हैं। कई दफा इन केजिज में जंगली गायों तथा बन्दरों को पकड़ कर कहीं किसी सैंचुरी में ले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि इनकी थिनिंग कर दी जाए ? स्पीकर साहब, मैं माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारे इलाके में यह रोज एक गम्भीर समस्या का रूप ले लेंगे। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कोई कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि पलवल से हमारे साथी जो उस वक्त मन्त्री थे उन्होंने एक बार कोशिश की थी, कि इन रोजों को पकड़ कर जंगल में ले जाएं और इस काम पर उन्होंने एक लाख चौरासी हजार रुपये खर्च किए थे तथा चार रोज़ पकड़े गए थे। ये चारों रोज़ पकड़ने के बाद दूसरे दिन मर गए थे। यह जानवर बहुत ही सैंसिटिव है और जब इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो यह मर जाता है इसलिए इसको पकड़ कर कहीं बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे हमें साधन उपलब्ध करवा दें तो हम इनको पकड़ कर इनके पास भिजवा देंगे। यदि हम इनको पकड़ कर इनके पास भिजवा दें तो क्या ये उन जानवरों को रखने के लिए तैयार हैं ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री अर्जन सिंह जी को यह आश्वासन देता हूं कि जितने भी जानवर पकड़ कर ये भिजवाएंगे हम उनको रखने के लिए तैयार हैं। (विघ्न)

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, नो सर कहना तो बड़ा आसान है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस जानवर को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता ? दूसरी बात यह है कि हजारों रोज़ जंगल के अन्दर 500-1000 की संख्या में इकट्ठे झुण्ड बना कर रहते हैं। पिंजरों की बजाय अगर उस जंगल की चार-दिवारी करके उनको वहीं पर रोक दिया जाए तो उससे न तो रोज़ मरेंगे और न ही वे फसलों का नुकसान करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं क्या वे ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदन में पहले ही बताया है कि इनकी पॉपुलेशन वर्ष 1993 से ले कर 2005 तक डबल हो गई है और आज हरियाणा में करीब 38000 रोज हैं। सबसे ज्यादा रोज हिसार जिले में हैं और सबसे कम रोहतक जिले में है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि इनको पकड़ा क्यों नहीं जा सकता है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसकी कोशिश की गई थी लेकिन वह कोशिश नाकामयाब रही थी। वर्ष 1996 में सरकार ने एक आदेश दिया था कि जहां पर इस जानवर के कारण फसल को नुकसान होता है वहां की पंचायत लिख कर वाईल्ड लाईफ डिपार्टमैंट को देगी तो विद कन्सलटेशन ऑफ डिप्टी कमिशनर कंसर्ड पंचायत को उन जानवरों को मारने का परमिट ईशू कर सकते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो परमिट ईशु हुए हैं। उनका ब्यौरा भी मैं यहां पर बता देता हूं। वर्ष 1997 में 14 परमिट ईशु हुए थे और 91 रोजों को मारने की इजाजत दी गई थी लेकिन 5 रोज मारे गए थे। 1997 से लेकर 2005 तक 39 परमिट ईशु हुए थे और 212 जानवरों को मारने की इजाजत दी गई थी लेकिन छः सालों में केवल 16 रोज़ पंचायतों की तरफ से मारे गए। स्पीकर सर, सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। अगर कोई पंचायत लिखकर यह देती है कि वहां पर रोज के कारण से फसलें डैमेज होती हैं तो उस डैमेज को कण्ट्रोल करने के लिए परमिट देने का प्रावधान है और कोई भी पंचायत परमिट लेकर रोज़ों को मार सकती है।

वित्त मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि रोहतक में जानवर कम हैं और हिसार जिले में सबसे ज्यादा हैं। यह फिगर उन्होंने दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ये जानवर चीफ मिनिस्टर के हिसाब से बदलते हैं। पहले चौटाला साहब रोहतक भेज देते थे और अब रोहतक वाले हिसार भेज रहे हैं। (हंसी)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने 1996 में जिस मन्त्री का जिक्र किया है मैं इनको बताना चाहता हूं कि वह मन्त्री मैं था जिसने रोज़ पकड़वाने की प्रक्रिया शुरू की थी तथा चौटाला सरकार ने उसके लिए मेरे खिलाफ एक इन्क्वायरी बिठाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगर ये इस बात

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

से सहमत हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था तो क्या वे इस इन्क्वायरी को बन्द करवाने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, इस बारे में कागजों को पूरी तरह से चैक करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि रोज काफी संख्या में जंगलों में जाकर बैठ जाता है तो क्या मंत्री जी वहां पर चार दीवारी बनाकर उनको वहीं तक सीमित करने का प्रावधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, वे जंगल में नहीं जाते वे तो ईख के खेत में बैठते हैं। उनको जब खेतों में खाने को नहीं मिलता, तब ही वे जंगलों में जाते हैं।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : स्पीकर सर, रोज हमारी सारी फसल खराब कर देते हैं और सरकार की तरफ से इस बारे में जरूर कोई प्रावधान होना चाहिए।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि रोज बहुत ही ताकतवार जानवर होता है और आप सभी जानते हैं कि वह 6 फुट की छलांग मार कर भाग जाता है। जहां वे इक्ट्ठे होते हैं अगर वहां पर चार दीवारी बना भी दी जाए तो वे वहां से भाग जाएंगे। इसके अलावा स्पीकर सर, एक रात में चार दिवारी बनाकर उनको एनक्लोज करना संभव नहीं है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर रोज किसी की फसल को खराब कर देता है तो वह पहले डिपार्टमैंट के पास आएगा और उसकी कम्पलेंट करके रोज को मारने का परमिट लेकर जाएगा। क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान करेगी कि वह आदमी रोज को वहीं खेत में मार दे और उसको उसके लिए परमिट लेने की आवश्यकता न पड़े। मुख्यमंत्री जी, आज किसान इतने लफड़े में नहीं पड़ता है कि पहले वह जाए, शिकायत करे और फिर रोज को मारने के लिए परमिट लेकर आए। क्या आप कानून में ऐसा कोई बदलाव करने की चेष्टा करेंगे कि जहां पर फसल लगी हुई हैं वहीं पर रोज को खत्म कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने सदन में जो बात कही है, वह बिल्कुल ठीक कही है कि रोज पूरी की पूरी फसल दो बर्बाद कर देता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि इसके लिए पंजाब सरकार ने कानून के तहत एक स्कीम बनाई हुई है और हमने उस स्कीम को उनसे मंगवाया हुआ है। पंजाब में ग्राम पंचायतों को ही अथोरिटी दी हुई है और ग्राम पंचायत एक दिन में दो रोज मार सकती है। वहां पर लोगों को जाकर परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उस स्कीम को एग्जामिन करके यहां पर लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री खरैती लाल शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब नील गाय फसल खराब कर देती है तो उसको मारने के लिए परमिट दिया जाता है मैं मन्त्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर सुअर बहुत आ गए हैं। क्या मंत्री जी उनको भी मारने के लिए परमिट देने का प्रावधान करेंगे।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कानून के तहत अगर संभव होगा तो हम उनको मारने का परमिट देने का प्रावधान करेंगे।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रोज़ एक ताकतवर जानवर होता है और जिस तरह से हम घोड़े और गाय को सुधारने का काम करते हैं उसी तरह से क्या सरकार ऐसी कोई स्कीम बनाएगी जिसके तहत रोज़ को सुधारने का काम किया जा सके।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त में इनके लीडर इनको सुधारने का काम किया करते थे, वे तो अब यहां पर नहीं है। वे ही उनको सुधारने का काम कर सकते हैं। (हंसी)

Shri Ram Kumar Gautam: Speaker Sir, ...

Mr. Speaker : I will not permit you to speak. This is against the rules. (Interruptions)

श्री राम कुमार गौतम : सर, मेरा क्वैश्चन सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

Mr. Speaker : Not as a Speaker but as a brother, I am saying, please sit down.

श्री विनोद कुमार शर्मा : माननीय स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो सवाल रोज़ के बारे में पूछा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह हिरन की प्रजाति से संबंधित है। इसको जो नील गाय का नाम दिया गया है यह उससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी जानवर होने के नाते लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

New Sorkhi /Depal Minors

*107. **Shri Amir Chand Makkar:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that water has not been reaching up to the tails of the following distributaries of the Hansi Constituency for the last six months:—

1. New Sorkhi Minor,
2. Depal Minor,
3. New Sultanpur Minor; and
4. Hansi Mahindera Minor ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to provide the water up to the tails of the aforesaid minors ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) No Sir. However it is a fact that partial supply has been reaching at tails of two minors namely Deepal Minor and New Sultanpur Minor during last six months.

(b) Internal clearance of the minors wherever required is being done to restore the full supply at tails.

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने दो माईनर्ज के बारे में अपने जवाब में माना है कि उनकी टेल तक पानी नहीं जा रहा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हकीकत यह है कि हांसी के जितने माईनर्ज हैं, जैसे हाजमपुर या दूसरे माईनर्ज हैं उनकी किसी की भी टेल पर पानी नहीं जा रहा है। आज किसान परेशान हैं क्योंकि टेल तक पानी न पहुंचने की वजह से उनकी फसलें सूख रही हैं। हमने वहां के इरीगेशन महकमें से बात की थी। उन्होंने हमें बताया कि अब तक उनको साल में माईनर्ज की एक बार सफाई करने के आदेश हैं। उनकी मांग है कि उनको माईनर्ज की साल में दो बार सफाई करने की इजाजत दी जाए ताकि वे इनकी पूरी सफाई कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हांसी एरिया ऐसा है जहां के माईनर्ज के पानी में काफी सिल्ट आती है। वहां पर पानी की कमी नहीं है लेकिन माईनर्ज साफ न होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इन नहरों की सफाई करवाकर इनकी टेल तक पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हांसी के बारे में हमारे पास पिछले तीन साल की एवरेज है वह तकरीबन 150 परसैंट इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है। यह बात सही है कि वहां के पानी में काफी सिल्ट आती है। इन्होंने दीपल माईनर का जिक्र किया । इसमें सिल्ट आ गयी थी लेकिन उसकी हमने क्लीयरैन्स कर दी है। इस पर करीबन 33564 रुपये लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो माईनर्ज का जिक्र किया है। न्यू सुलतानपुर माईनर की भी हम इंटरनल क्लीयरैन्स इस महीने के अंत तक कर देंगे। इसके साथ साथ इन्होंने हांसी महिन्द्रा माईनर का भी जिक्र किया मैं इनको बताना चाहूंगा कि वह हांसी महिन्द्रा माईनर नहीं बल्कि हांसी सब-माईनर है। इस पर पिछले दिनों थोड़ी बहुत दिक्कत थी क्योंकि वहां पर पैरेंट चैनल से पानी नहीं आ पाया था लेकिन अब पूरा पानी आ रहा है। इसी तरह से इन्होंने रैस्टोरेशन ऑफ सोरखी माईनर का भी जिक्र किया। हम इस माईनर की भी जून के अंत तक सफाई करवा देंगे और इसमें भी पानी टेल तक पहुंचाएंगे। इनके यहां का एक और आई०आर० सोरखी माईनर है इसमें तो पूरा पानी आ रहा है। लेकिन इन सारे कामों पर अढ़ाई लाख रुपये लगेंगे। यह सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। इनका यह कहना कि इनके यहां के किसी भी माईनर की टेल तक पानी नहीं जा रहा है, ठीक नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं जाता है तो वह हांसी के एरिया में जाता है। वहां की 150 परसैंट इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है जबकि जे०एल०एन० कैनाल में कहीं कहीं पर केवल एक परसैंट ही इंटेंसिटी है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है। कलायत हल्का जोकि काफी समय से अनदेखा रहा है, में पानी की बहुत कमी है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि बाला और तोशाला माईनर्ज की इस समय कैपेसिटी बहुत कम है, तो कब तक इन माईनर्ज की कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य करवाया जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमैन्टरी का तारांकित सवाल से कोई लिंक नहीं है और जहां तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था तो इसके लिए कैरियर कैनाल हांसी बुटाना ब्रांच बन रही है इस पर 260 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इसके बनने में दो वर्ष का समय लगेगा। जिन माईनर्ज का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में लिखकर दे दें तो उनके बारे में हम देख लेंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के बवानी खेड़ा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है और हमारे यहां पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमने पिछली सरकार से पीने के लिए पानी मांगा तो 200 किसानों को जेल में डाल दिया गया था मैं भी विधायक होते हुए उसमें शामिल था। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़सी, बुटानी, लोशाग, हिल्स माईनर, खानक माईनर, धमाना माईनर और उमरा माईनर इन माईनर्ज में अभी तक पानी क्यों नहीं पहुंच पाया है। मेरे हल्के में खानक में हर रोज 20 हजार रुपये का पीने का पानी आता है तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कब तक पानी पहुंचायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सप्लीमैन्टरी का भी मेन सवाल से कोई लिंक नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगले दो-तीन महीने के अंदर चाहे लोहारु कैनाल है या सुन्दर ब्रांच है उन सबके हैड की सफाई के बारे में कार्य चल रहा है, अभी जे०एल०एन० में भी काम चल रहा है उसके बाद हम सभी माईनर्ज की टेल एंड पर पानी पहुंचाएंगे। जिन माईनर्ज का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में लिखकर दे दें तो उनके बारे में भी देख लेंगे।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, गुहला हल्के में कम से कम 10-11 टेल्ज पड़ते हैं, गुहला पैडी एरिया है। वहां पर नहरों में कम से कम 10-15 किलोमीटर तक पिछले 10-12 सालों से टेल पर पानी नहीं गया है। जब वे नहरें कच्ची थीं तब तो कुछ पानी मिल भी जाता था, पक्की होने के बाद तो पानी नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन्होंने वायदा किया था कि सभी नहरों में टेल एंड तक पानी पहुंचाएंगे। तो ये कब तक नहरों के टेल एंड तक पानी पहुंचा देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बी०एम०एल० हांसी, बुटाना ब्रांच की जो लिंक ब्रांच बन रही है यह खासकर गुहला एरिया से निकल कर जाएगी। जब आपका राइस का सीजन होगा उस वक्त आपको उससे काफी पानी मिलेगा। उसके बावजूद भी जो अवेलेबल वाटर है उस बारे में मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा और जो आपने बाल सदन में रखी है उसके बारे में हम कार्यवाही करेंगे। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जसराना माईनर लगती है। मेरे हल्के में 10-12 गांव ऐसे हैं जहां टेल एण्ड पर पानी नहीं जाता है। मैंने उस माईनर की री-मौडलिंग के लिए विभाग को लिखकर दिया हुआ है, मंत्री जी यह बताएं कि उस बारे में कब तक कार्यवाही करेंगे ?

Mr. Speaker : It is not possible to reply all questions. Please put the question about a particular minor.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सप्लीमैंट्री का तारांकित प्रश्न से कोई लिंक नहीं है फिर भी जिन माईनर्ज का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में लिखकर दे दें तो उसे देख लेंगे।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में नाडा, सुरधुरा और राजली ऐसी माईनर्ज हैं जहां पिछले छह साल से पानी नहीं पहुंचा है। इसके अलावा दो मललोड़ा और खेडी जालब माईनर्ज नई मंजूर हुई हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कब तक बनेगी।

Mr. Speaker : It is not possible to reply.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सप्लीमैन्टरी भी मेन प्रश्न का हिस्सा नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर कोई स्पैशल केस है तो वे हमें लिखित में दे दें हम चैक करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसराना माईनर की कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य चल रहा है। The work is already in progress. हम हर संभव कोशिश करके टेल तक पानी पहुंचायेंगे।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न बहुत अहम है कि टेल तक पानी पहुंचे। जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि सभी माईनर्ज की डि-सिलटिंग का कार्य चल रहा है। मैं यहां उनको बताना चाहूंगा कि एक भी माईनर की डि-सिलटिंग का कार्य सारे हरियाणा में नहीं चल रहा है सिर्फ उनकी घास की सफाई का कार्य किया जा रहा है, माईनर्ज से रेत नहीं निकाला जा रहा है। हमारे प्रदेश में यह बहुत भारी समस्या है पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं कि डि-सिल्टिंग का कार्य हो रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने डि-सिल्टिंग की बड़ी कैनाल की बात की थी जैसे जे०एन०एल० और महेन्द्रगढ़ कैनाल व सुन्दर ब्रान्च है। छोटी नहरों की डि-सिलटिंग का कार्य फार्मर्ज की सोसाइटी होती है वह खुद करवाती है और जैसा कि आपको पता है कि हमारे विभाग में बेलदारों की कमी है क्योंकि पिछली सरकार के समय काफी पोस्टें बेलदारों की खत्म कर दी थीं, यह काम बेलदार ही करवाते हैं फिर भी हम इस बारे में जल्दी ही कार्यवाही करेंगे।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर जून तक सारे हिन्दुस्तान की कैनाल्ज में पानी की मात्रा कम होती है। कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिवानी और जूई नहर पर हमारे एरिया में स्प्रिंकलर सैट्स लगाये गये थे। लेकिन अब वे स्प्रिंकलर सैट्स बेकार पड़े हैं और उनको जंग लग चुका है। क्या मंत्री जी उनको दोबारा से चालू करवायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न मेन प्रश्न का हिस्सा नहीं है लेकिन इस बारे में मैं अधिकारियों से पता करके माननीय सदस्य को जवाब दे दूंगा।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में एक नहर बनाने जा रहे हैं जिस पर 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह नहर कब तक बनकर तैयार हो जायेगी और कौन सी एजैन्सी इस नहर को बनायेगी ?

Mr. Speaker : Yadav ji, this is not possible for a Minister to reply it. Minister is also a human being.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सप्लीमेन्टरी भी मेन प्रश्न का हिस्सा नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब इस नहर का कार्य शुरू होगा

तो उसके बाद इस नहर को बनाने में दो साल और लग जायेंगे। इस नहर पर 207 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इस नहर की कैपेसिटी 2000 क्यूसिक की होगी।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे हल्के साल्हावास के अनेकों गांव टेल एण्ड पर पड़ते हैं जिनको धिड़िया माईनर और जे०एन०एल० कैनाल से पानी लगता है । क्या मंत्री जी उन गांवों के टेल एण्ड तक पानी पहुंचवाने की कृपा करेंगे, अगर पहुंचवायेंगे तो कब तक पहुंचवायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सप्लीमेन्टरी भी मेन सवाल से हटकर है फिर भी मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमें अभी एस०वाई०एल० का पानी नहीं मिला है। इस पानी को लाने के लिए मैंने बताया कि एक कैनाल बनाने जा रहे हैं जो नई कैनाल बनेगी उससे यह समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हर गांव के टेल एण्ड तक पानी पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी, आप अपनी सप्लीमेन्टरी जल्दी से पूछ लें क्योंकि क्वैश्चन आवर समाप्त होने जा रहा है।

श्री दान सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब समान पानी के बंटवारे की बात हुई थी तो उसकी वजह से आज सभी लोगों में उत्सुकता है। मेरे हल्के के गांव बसई जोकि दस हजार की आबादी वाला गांव है, वहां पर 15 साल पहले एक जोहड़ में पानी आया था लेकिन आज जो बसई माईनर है वह खुर्द-बुर्द हालत के अन्दर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उसकी रिपेयर करके मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, माफ करना, आपके सवाल का जवाब आना मुश्किल है क्योंकि अब सवालों का समय समाप्त हो गया है। (शोर)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन आवर समाप्त हो जाता है। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please sit down .

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रश्नकाल में जो सवाल रखे जाते हैं उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के प्रश्नकाल में 16 सवाल रखे गए हैं और रोज की यह प्रैक्टिस है कि उनमें से तकरीबन 6 सवाल छूट जाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम एक क्वैश्चन पर 5 मिनट या 10 मिनट का ही समय रखा जाए। आज मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुसूचित जाति के लोगों को फ्री आफ कास्ट प्लाट देने के बारे में था। वह प्रश्नकाल का समय समाप्त होने की वजह से पूछना रह गया।

Mr. Speaker : This is not possible. This depends upon the importance of question.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, गौतम जी उस समय विधान सभा के सदस्य नहीं थे, जब ये साथी इस तरफ बैठा करते थे तो एक सवाल में ही पूरा प्रश्न काल का समय निकल जाता था। (शोर)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, जो अन्याय करता है वह दोबारा कभी नहीं आता, अगर आप भी इसी लाइन पर चलेंगे तो दोबारा कभी नहीं आएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of a Stadium in Samalkha Constituency

***87. Shri Bharat Singh Chhokar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Stadium in Samalkha Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Construction of a Housing Board Colony, Matlodha

***85. Smt. Raj Rani Poonam :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Housing Board Colony in Matlodha, district Panipat ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(ए) जी हां ।

(बी) निर्माण कार्य भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत से मिलने के उपरान्त 2 वर्ष में हो जाएगा।

Haryana State Industrial Security Force

***75. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the object and purpose for raising the Haryana State Industrial Security Force alongwith the projected budget estimates since its inception;

(b) the name of the places of training center where the person of the HSISF were imparted training alongwith the training module qualifications and experience of the Master trainers who imparted training ;

(c) the name of public sector or private sector industrial or commercial units alongwith their intake who made indented since inception of HSISF till 31st May, 2005;

(d) the name of the Budget Head from which the expenses of this force is being met with ; and

(e) whether there is any proposal under the consideration of the Government to disband this force ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बिल 2003 हरियाणा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों तथा कारणों के साथ पास किया गया था :—

"इस समय पुलिस बल का बड़ा भाग स्वायत्त निकायों, स्थापनाओं, औद्योगिक उपक्रमों संस्थाओं और ऐसे औद्योगिक उपक्रमों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए लगा हुआ है। हरियाणा राज्य सुरक्षा औद्योगिक बल के बन जाने पर कानून एवं व्यवस्था के लिए दबाव समाप्त हो जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के बन जाने पर यह बल सुरक्षा उद्देश्य के लिए उपलब्ध होगा तथा पुलिस विभाग कानून एवं व्यवस्था कार्यों को दक्षतापूर्वक तथा सुचारू रूप से कर सकेगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती का खर्चा सेवा प्राप्त करने वाले बैंकों, सार्वजनिक सैक्टर उपक्रमों, बोर्ड/कारपोरेशन तथा निजी संस्थाओं इत्यादि के खाते में उनकी मांग अनुसार डाला जाएगा।"

बल पर 31-3-2005 तक 8,09,42,695/- रुपये खर्च हुआ था। इसका वार्षिक खर्च 47.48 करोड़ रुपये आने पर अनुमान है।

(ख) हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्त कर्मचारियों को बेसिक प्रशिक्षण हरियाणा पुलिस अकैडमी, मधुबन अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र प्रथम वाहिनी हरियाणा सशस्त्र पुलिस अम्बाला शहर, तृतीय हरियाणा सशस्त्र पुलिस हिसार कमांडों नेवल करनाल, इण्डियन रिजर्व बटालियन भौंडसी, गुड़गावां और पुलिस लाईन कुरुक्षेत्र में दी जा रही है।

प्रशिक्षकों की योग्यता तथा अनुभव :--

बाहरी कथायद तथा आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा हरियाणा पुलिस के अनुभवी निरीक्षक तथा मुख्य सिपाहियों द्वारा दिया जा रहा है।

(ग) हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती बारे कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए अलग से बजट हैड अभी तक नहीं बनाया गया है। इस बल का खर्च हरियाणा पुलिस के हैड "2055-पुलिस-104 स्पैशल पुलिस"।

(ङ) हां ! एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है और एक बिल वर्तमान विधान सभा स्तर में हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एक्ट-2003 निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

Installation of Petrol Pump, Hansi

***108. Shri Amir Chand Makkar :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any unauthorized petrol pump has been installed on public land of Municipal Committee in Yati Nagar, Hansi City during the period from 2000 to 2005 ; if so, the name and address of the owner of the said petrol pump;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct any enquiry in this regard ; and

(c) whether Government intends to take any action against those officers who have issued NOC for the installation of aforesaid petrol pumps?

उप-मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन) :

(क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत, प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर के परिपेक्ष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही विधाराधीन नहीं है।

Transfer Policy

***18. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to formulate a permanent transfer policy for each department; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जी, नहीं।

Providing of Residential Plots to Scheduled Castes

***69. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to provide plots for construction of houses free of cost to the persons belonging to Scheduled Castes in the State ?

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्तियों को 100 वर्ग गज़ के मुफ्त प्लाट आबंटित किये जाते हैं जिसका गांव में अपना प्लाट या मकान न हो और जिसकी वार्षिक आय 3600/-रुपये से कम हो।

---

24 Hours Supply of Electricity

***106. Shri Sushil Kumar Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme of the Government to supply electricity 24 hours to the villages of Haryana State; if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं श्रीमान् वर्तमान् समय में नहीं ।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्यों और सारे हरियाणा के लोगों का बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा है उसके बारे में कहना चाहूंगा। इस मुद्दे ने हमारे कई लोगों की जान ली और जो कई वर्षों से हर गांव में हर घर में परेशानी का

कारण बना हुआ था। एक एक व्यक्ति पर लाखों रुपये बिजली के बिल बकाया हो गए थे जो उसके साधनों से दे पाने मुश्किल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी। आज ऐतिहासिक फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है जो कि मैं समझता हूं आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश की सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा और न आगे लेगी। अपनी सरकार का यह फैसला मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, मैं समझता हूं कि इस फैसले के बाद आज हरियाणा के विकास की गति इस तेजी से हो जाएगी कि हरियाणा का हर नागरिक सुख से रहेगा और विकास करेगा और हरियाणा का विकास हिन्दुस्तान में अगले 5 सालों में पहले नम्बर पर होगा। आप सबको यह बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि हर व्यक्ति इससे कंसर्ड है। हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के घरों और ट्यूबवैल्ज के बिजली के बिलों का आज तक 1600 करोड़ से अधिक बकाया है। पिछले एक दशक के दौरान हरियाणा के सीधे साधे किसान वर्ग को अफसरवादी राजनीतिज्ञ ने मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली देने का वायदा किया और बिजली के बिल न भरने के लिए बरगलाते रहे। वैसे देखा जाए तो इनैलो सरकार ने 2002 का विधानसभा का चुनाव मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के गलत वायदे के आधार पर लड़ा था, लेकिन कुल मिलाकर किसान को अन्त में गोलियां, क्रूरता और निर्दयता और निष्ठुरता ही मिली। जिसके परिणाम को व्यान करना आज भी रोंगटें खड़े कर देता है। कंडेला से कुलकरी तक के किसानों के आन्दोलन की कहानी बेकसूरों की लाशों और खून के छींटों से लिखी जाएगी। राजनैतिक स्वार्थ के लिए किसान व खेतों में काम करने वाले अनेक श्रमिकों पर बहुत जुल्म हुए। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर किसान का आंसू पोंछने का और जाति वर्ग का पक्षपात किए बिना ग्रामीण वर्ग के हर सदस्य के हाथ को पकड़ साथ साथ चलकर हमेशा उनके दुखों को दूर करने का प्रयास किया है। जींद में किसान पर हुए नरसंहार, अत्याचार के बाद मेरी ऐतिहासिक पदयात्रा जो 21 जून, 2002 को रामलीला मैदान से अपनी समाप्ति के वक्त एक विशाल जन समूह का रूप धारण कर चुकी थी, इस दिशा में एक कदम था। समस्त ग्रामीण वर्गों के प्रति वचनबद्धता हमारी राजनैतिक प्रतिबद्धता ही नहीं है बल्कि दिल से निकलने वाली आवाज है। मुझे वह वक्त याद है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी हरियाणा में आई और लाखों पुरुषों व स्त्रियों के दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने उनके जीवन में नई रोशनी लाने का वायदा किया था। श्रीमती गांधी का वही वचन है जो आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिजली के बिलों को लेकर कोई गलत वायदा नहीं किया था लेकिन फिर भी इस विषय में हम एक ऐसा समाधान चाहते थे जिससे न केवल समूचे किसान वर्ग को राहत की सांस मिले बल्कि उन्हें बिजली के बिलों को समय पर भरने पर प्रोत्साहन के साथ-साथ बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की वित्तीय सेहत भी ठीक बनी रहे। जो यह फैसला हमारी सरकार ने किया है उसके लिए मैं अपने मंत्रियों, साथियों और जो अधिकारी हैं उनका आभारी हूं। इस बारे में हमने वित्तमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया हुआ है। सभी ने मिलकर, जब से यह सरकार बनी है दिन रात मेहनत करके, गांवों में जाकर किसानों से बात करके, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके से बात करके चाहे वह भारतीय किसान यूनियन है या कोई और यूनियन है, सब से बात करके ही हम आज इस फैसले पर पहुंचे हैं। यह जो मैं अब घोषणा करने जा रहा हूं यह घोषणा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हर किसी के फायदे के लिए बिजली के बकाया बिलों के संदर्भ में एक नवोदित समाधान निकाला है। दो माह में बिलिंग साईकल के अनुसार

[मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)]

किसानों का व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल हर दो महीने में आता है और किसानों व ग्रामीणों के बकाया बिजली के बिलों को माफ कर पूर्ण मुक्ति दिलाने का फैसला हमने किया है (इस समय मेजें थप-थपाई गई) । अध्यक्ष महोदय, हर किस्म के दबाव के बावजूद हमने यह फैसला किया है। आपको भी इसकी पूरी जानकारी है और सारी नीतियों का भी पता है। यह फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है, यह 1600 करोड़ रुपये का मामला है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला होने से हरियाणा की ग्रामीण जनता का मुकद्दर बदलेगा। हरियाणा की ग्रामीण जनता से गलत वायदा किया तो किसी और ने था और इस वायदे को पूरा करने का साहस तथा हिम्मत किसी ने की है तो वह आज हमारी हरियाणा सरकार ने की है। हमने यह साहस हरियाणा की जनता के भरोसे पर किया है। हमारे को हरियाणा के किसान पर, ग्रामीण वर्ग पर यानि हर वर्ग पर पूरा भरोसा है कि जो आज फैसला हुआ है इस पर हम और वे मिलजुलकर चलेंगे और एक दूसरे के पूरे सहयोग से हम हरियाणा को सबसे आगे ले जायेंगे। इसमें हर व्यक्ति के अब तक के बकाया बिल की 10 किस्तें बना दी जायेंगी। जैसा मैने कहा कि बिल देने का दो-दो महीने का सर्कल है तो 20 महीने के अंदर-अंदर हर किसान और ग्रामीण जिनके बकाया बिल हैं उनसे मुक्त हो जायेंगे। बकाया बिजली के बिलों की दस किस्तें बनाई गई हैं और उन्हें 20 महीने में विभाजित कर दिया गया है। मौजूदा हर बिल के भुगतान के साथ बकाया बिल की 10 प्रतिशत राशि अपने आप छोड़ दी जायेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि 17 जून यानि कि आज से लगातार मौजूदा बिल की 10 किस्तों का भुगतान करने पर किसान भाईयों का पूरा बकाया जो भी बिल है, चाहे वह सरचार्ज है उससे मुक्ति मिल जायेगी। इस तरह से गरीब किसान व ग्रामीण बकाया बिलों के बोझ से पूरी तरह से मुक्त हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त जो भाई अपने बिजली के बिलों का लगातार भुगतान करते हैं जिनकी बड़ी संख्या है उनकी भावनाओं का भी हम पूरा आदर करते हैं। उनके लाभ को भी हम भूले नहीं हैं। बिलों का निरन्तर भुगतान करने वाले निष्ठावान नागरिकों के लिए हम एक अनूठी योजना लेकर आए हैं। अपने पिछले पांच बिलों मतलब कि 10 महीने का नियमित तौर पर भुगतान करने वाले किसानों व ग्रामीण बन्धुओं को आने वाले 20 माह तक निर्विवादित 10 बिलों में 5% की छूट दी जाएगी। (**इस समय मेजें थपथपाई गई**) जो रैगुलर बिल भरते रहे उनके लिए भी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करने के लिए हमारी यह अनूठी शैली है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिजली उपलब्ध करवाने वाली कम्पनियों की वित्तीय सेहत को बनाए रखने के लिए हम सभी के पक्ष में है। हम वित्तीय क्षेत्र में और थोड़ी सी दूरी को मूल और संरचना में सुधार, ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन दिलाने और एकीकरण के कार्य को सुसंगठन से जरूर करेंगे ताकि फैसलों को तय करने के उद्देश्य से बकाया को पूरे के पूरे कर्जों की किश्तों की अदायगी करने के लिए सरकार भी इन कम्पनियों को सहायता उपलब्ध करवा सके। इन कम्पनियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर कार्यकुशलता के प्रति सरकार वचनबद्ध है। संक्षिप्त में पैकेज इस प्रकार है- (1) हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण भाईयों के बिजली के बिलों की बकायों से मुक्ति दी जा सके। इससे राज्य में आज तक 1600 करोड़ रुपये से अधिक ग्रामीण भाईयों के बिजली के बिल के समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा बिजली के बिलों को नियमित और समय पर भुगतान करने वाले नागरिकों को फायदा होगा। बिजली उपलब्ध करवाने वाली कम्पनियों की वित्तीय सेहत में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की मूल संरचना में सुधार के लिए अनुदान में अभुमोदन, गांवों में बिजली की निरन्तर आपूर्ति का प्रयास और नवोदित

पैकेज की संरचना आदि बातें हैं। तब से लेकर मेरी सरकार ने जनसाधारण और हर वर्ग के व्यक्ति से बात की। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमे कृषक वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, मैं इस सदन में खड़े हो कर राज्य में इतिहास के नये दौर की शुरूआत के संदर्भ में पूर्ण ज्ञान के साथ सदन के माननीय सदस्यों और हरियाणा की जनता से उनके सहयोग, समर्थन और सदभावना के लिए निवेदन करता हूं। खासतौर पर मेरे जो साथी विपक्ष में बैठे हुए हैं इनसे भी निवेदन करता हूं क्योंकि इनकी पार्टी की पिछली सरकार ने हरियाणा के किसानों का बहुत नुकसान करवा दिया। अब सब को साथ लेकर एक हो कर चलना है। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा दोहराता हूं कि हरियाणा की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। (विघ्न)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण लोगों के लिए आज सुनहरी दिन है। मैं हरियाणा कृषक समाज के अध्यक्ष के नाते भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार को पूर्ण रूप से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : No Supplementary. Indora ji, please take your seat. This is an announcement by the Chief Minister. You can otherwise, refer in your speech (Interruptions). You can speak on Appropriation Bill. (Interruptions) Indora ji, please take your seat. Senior most Member of the House Surjewala ji, is on his legs. Let him say, please sit down Indora ji.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, शायद लोक दल के लोगों को यह बात भायी नहीं है इसलिए इससे इनके पेट में कोई पीड़ा है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। आमतौर पर यह शिकायत मिलती थी कि अगर बच्चे कहीं स्कूल में दाखिले के लिए जाते थे तो एप्लीकेशन के साथ बिजली के बिल का एन०ओ०सी० मांगते थे। आज की इस घोषणा के बाद हरियाणा में किसी से बिजली के बिल के बारे में एन०ओ०सी० नहीं मांगी जाएगी। (विघ्न एवं शोर)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, I want to say something

Mr. Speaker : Please take your seat, Indora Ji.

Dr. Sushil Indora : Sir, I want to say .....

Mr. Speaker : Indora ji, seniormost Member of the House is on his legs and you have no respect for him.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मुझे आप मेरी बात कहने का मौका तो दें।

Mr. Speaker : On the statement, there is no supplementary. No discussion is allowed. (Interruptions) This is what the rule says. Now I am taking up your Calling Attention Notice.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, इन्होंने हमारे बारे में कहा है। मुझे उस बारे में कहने का मौका तो दें।

Mr. Speaker : I would not permit anybody to speak. I will not permit to the Members of this side or that side to speak. (Interruptions). Now, I am taking next item. (Interruptions)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपकी इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस सरकार ने वह काम करके दिखा दिया है। जिसके बारे में किसान ने कभी सपना भी नहीं लिया होगा। स्पीकर सर, पिछली सरकार की गलतियों की वजह से उनकी गलत राजनीति की वजह से उनकी गलत सोच की वजह से किसानों पर बिजली के बिलों का बहुत भारी बोझ पड़ गया था। पिछली सरकार ने यह कहा था कि अगर आप हमें वोट दोगे और हरियाणा में हमारी सरकार आ गई तो हम आपके बिजली के बिल माफ कर देंगे। (विघ्न) इस सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और स्त्रियों के लिए कई अन्य सुविधाएं देने की घोषणाएं की हैं। उसके साथ ही इस सरकार ने श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में यह जो घोषणा की हैं, इस घोषणा ने एक मील के पत्थर का काम किया है। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इस सरकार की घोषणाओं से इस सरकार के आचरण का पता चलता है और इस सरकार के आचरण में और पिछली सरकार के आचरण में कितना फर्क थां, का भी पता चलता है। इस सरकार ने किसानों के लिए जो किया है और पिछली सरकार के वक्त में ओमप्रकाश चौटाला ने जो किया था उसके लिए वे हरियाणा की जनता से और हरियाणा के किसानों से माफी मांगें। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ..... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat. (Interruptions) Listen, would you please allow me to say. There is no issue. (Interruptions) Listen Mr. Indora, on the statement there is no supplementary and discussion. This is what the Rules say. I am bringing your Call Attention Motion. (Interruptions)

डा० सीता राम : स्पीकर सर, आप इन्दौरा जी का जो दूसरा मुद्दा है, उसे तो सुनें । (शोर)

Mr. Speaker : No-No, absolutely not. I would not permit any body. I would not permit this side as well as that side. I am sorry to say. (Interruptions)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरा दूसरा मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No absolutely not. I am taking the next item. (Interruptions)

डा० सीता राम : स्पीकर सर, यदि आप इन्दौरा जी की बात नहीं सुनेंगे तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करेंगे। (शोर)

Mr. Speaker : I am taking the next item. The next item is a Calling Attention Notice given by Shri Sushil Indora, and 7 other MLAs regarding procurement of mustard crops and other food grains. (Interruptions)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, आपकी परमिशन से मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि विपक्ष अपनी काल अटैंशन मोशन पर ही वाक-आउट करके सदन से बाहर जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आपने इन्दौरा जी की काल अटैंशन मोशन एडमिट कर ली और इन्दौरा जी की काल अटैंशन मोशन पर ही इनके साथी वाक-आउट करके जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : A concession to the entire State has been given. It is a big concession to the State and unfortunately, there is a walk out from your side.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हमारे साथी काल अटैंशन मोशन पर वाक-आउट नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा रिवाड़ी में जो लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं उनके बारे में है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह न्यूज पेपर में आया है।

Mr. Speaker : Please take your seat.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, * * * * *।

Mr. Speaker : Indora ji, please take your seat. यह मुद्दा इससे रिलेट नहीं करता है। इन्दौरा जी जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्दौरा जी ने काल अटैंशन मोशन दी है और ये उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का काल अटैंशन मोशन है और विपक्ष उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि विपक्ष अपनी काल अटैंशन मोशन पर ही वाक-आउट करके सदन से बाहर जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आपने इन्दौरा जी की काल अटैंशन एडमिट कर ली और इन्दौरा जी की काल अटैंशन मोशन पर ही इनके साथी वाक-आउट करके जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इनको तो इस बात की तकलीफ है कि इस सरकार ने किसानों की भलाई वाली घोषणा क्यों कर दी। ये तो किसानों की भलाई का काम होते हुए देख नहीं सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यह घोषणा करके हरियाणा में एक मील का पत्थर रखने का काम किया है और हमारी सरकार किसानों की भलाई का काम करने के लिए कटिबद्ध है।

डा० सीता राम : स्पीकर सर, आप इन्दौरा जी की बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम एज़ ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय डॉ० सुशील इन्दौरा को छोड़ कर इण्डियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सरसों की फसल तथा अन्य खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति संबंधी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Sushil Indora, and 7 other MLAs regarding procurement of mustard crops and other food grains. I admit it. Now, Shri Sushil Indora may read his notice.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

@ **डा० सुशील इन्दौरा, ईश्वर सिंह पलाका, ज्ञान चंद, सीताराम, बलवन्त सिंह, रामफल चिड़ाना सहीदा खां तथा श्रीमती रेखा राणा एम०एल०एज़०** : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन का मैं ध्यान एक अत्यधिक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में सरसों की फसल की अधिप्राप्ति सरकार की नीति के अनुसार नहीं थी, इस के कारण हरियाणा के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पहले सरकारी एजेन्सियों को पंजीकृत आढ़तियों के माध्यम से सरसों तथा अन्य खाद्यान्नों जैसे कि गेहूं तथा धान की अधिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था तथा किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए कोई समस्या नहीं होती थी। सरसों की अधिप्राप्ति की यह प्रक्रिया अब रोक दी गई है परन्तु धान तथा गेहूं के लिए यह अभी जारी है। सरसों की अधिप्राप्ति के मामले में खरीद केवल ग्राम समिति/मार्केट समिति के माध्यम से की जाती है जोकि इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। किसान अन्य समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पटवारियों से फर्द गिरदावरी प्रस्तुत करने को कहा जाता है जिसका अर्थ है भ्रष्टाचार बढ़ाना। इस प्रक्रिया में कुछ किसान इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में भी सफल नहीं हो सके। मैंने आगे कहा कि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि किसान अपनी फसलों को ट्रेड मार्किट में दुकानदारों तथा आढ़तियों को औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ बेईमान आढ़ती भूमि उपयोग के जाली दस्तावेज प्राप्त करके कम दामों/सरकारी दामों पर खरीद करके सरसों की फसल को समितियों को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसलिए, इस प्रक्रिया से किसान करोड़ों रुपये से वंचित हो गये हैं तथा कुछ आढ़ती किसानों की कीमत पर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह लोक महत्व का बहुत गम्भीर विषय है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दें। (विघ्न)

Mr. Speaker : It is not the way. Listen to me Mr. Indora. Please take your seat. Notice of this Calling Attention Motion has been read. Before the statement is made by the Chief Minister, I may inform that seven members have signed the notice. Only one supplementary can be put by every signatory and the member who has read the notice, he can put two supplementaries.

Now, the Chief Minister may make a statement.

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Mustard is purchased under the Price Support Scheme of the Government of India, The Minimum Support Price (MSP) of Mustard is fixed by the Government of India every season. Nafed is the Nodal Agency of the Government of India for the Price Support Operations of oilseeds and pulses. Nafed procures the produce through the State Cooperative Marketing Federations. For the Rabi season 2004-05, the Government of India fixed the MSP of Mustard at Rs. 1700/- per quintal against Rs. 1600/- during the previous season. It was specified in the Action Plan of Nafed that the purchase will be made through the State Cooperative Marketing Federations and State Oilseeds Growers Cooperative Federations. For the State of Haryana, Hafed was designated as the State agency to make the procurement of mustard. It was, therefore, mandated

@ Read by Dr. Sushil Kumar Indora.

in the scheme itself that Hafed would procure mustard through its cooperative marketing societies directly from the farmers.

It is also stated that Nafed reimburses the PSS price of mustard along with other taxes/ mandi levies, transporation and labour charges to Hafed. No amount is paid by Nafed on account of commission (Dami) of 2.5% for the commission agents or arhatias which is allowed to them by FCI in case of procurement of wheat and paddy. But there is no such provision under the Price Support Scheme of Mustard. Therefore, mustard was purchased through the State Cooperative Marketing Societies in the State as per the policy of the Government of India.

No mustard was purchased by the State Government agencies during the previous Rabi seasons of 2002-03 and 2003-04 and the farmers were left to the vagaries of market fluctuations. This Government in the initial days of its taking over decided to purchase the mustard at the MSP rate, so that the farmers are not forced to resort to distress sale. Hafed started the procurement of mustard w.e.f. 23-3-2005 in the mandis of 12 mustard growing districts of the State. I am happy to inform that an all time record procurement of 3.06 lacs MTs of mustard has been made by Hafed at the support price of Rs. 1700/- per quintal. The market price of mustard during this period ranged between Rs. 1500/- to Rs. 1600/- per quintal. An amount of more than Rs. 520.00 crores has been paid to the farmers for their produce. Thus, the farmers have been immensely benefited because of the purchase of the mustard by Hafed.

In order to ensure that mustard of farmers only is purchased and the benefit goes to the genuine farmers, the verification of the copies of revenue record viz 'fard girdawari' etc. was made compulsory at the time of purchase. It was done because there were some complaints that some traders/ middlemen were trying to exploit the situation. Also, in order to ensure that the farmers get the full price of their mustard, the payment was made through account payee cheques/ order cheques in the name of the farmers themselves.

I may also state that the system of purchase through the Cooperative Marketing Societies has financially helped these Societies which are also the farmers' organizations. These Societies have been paid a commission of 1% and this way they have earned an income of more than Rs. 5.00 crores which otherwise would have gone to the commission agents.This has strengthened their financial position and a number of the Marketing Societies have come out of red.This would also help the empowerment of the farmers through these cooperative organizations. The infrastructure of these Societies is further being strengthened to ensure smooth procurement of agricultural produce in the future.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट में कहा है कि कोऑपरेटिव मार्किटिंग सोसायटी किसान से संबंधित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से व्हीट प्रिक्योरमैंट में और पैडी प्रिक्योरमैंट में गिरदावरी और फर्द की मांग नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि जब व्हीट और पैडी में गिरदावरी की जरूरत नहीं होती और स्मूथली परचेज होती है तो सरसों के मामलों में क्या जरूरी है कि फर्द और गिरदावरी हो ? ये भी बताएं कि कितने मामले ऐसे आये जिसमें किसान ने सरसों की खरीद के मामले में प्रदर्शन किया है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो व्हीट और पैडी की चर्चा की गई है। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां एफ०सी०आई० खरीदती है। 520 करोड़ रुपया नैफेड ने देने की बात की है उसमें से 200 करोड़ रुपया ही मिला है, नैफेड से 320 करोड़ रुपया और लेना है क्योंकि किसानों को दिक्कत है और जब माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी सरसों नहीं बिक रही है उसी दिन से हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि सरसों की फसल को 1700 रुपये के हिसाब से सरकार खरीदेगी। माननीय सदस्य कोऑपरेटिव मार्किटिंग सोसायटियों की बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी की सरकार थी इनके समय में 2001-02 में जो पैदावार हुई थी वह 324 मीट्रिक टन हुई थी और खरीद मात्र 36 हजार मीट्रिक टन की हुई। (शेम शेम)

2001-02 में पैदावार 2 लाख 53 हजार 732 मीट्रिक टन हुई और खरीद 75361 एम०टी० हुई और 2002-03 और 2003-04 में खरीद की ही नहीं गई। वर्ष 2004-05 में कुल ऐराइवल 3,12,685 मीट्रिक टन हुई और जो खरीदी है वह 3 लाख 6 हजार 275 मीट्रिक टन खरीदी है। यह ऑल टाइम रिकार्ड है। यह भी माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी 2001-02 में तब न के बराबर खरीद की गई। आपने भी मार्किट सोसायटी और कोऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से खरीद की थी यह नैफेड और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की कंडीशन है।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बड़े प्यार से बता रहे थे कि पिछली सरकार ने सरसों की खरीद कितनी की और कितनी नहीं की। मैंने सवाल फर्द, गिरदावरी और प्रदर्शन के बारे में किया था। जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक शब्द भी नहीं कहा गया है। सवाल का जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी सप्लीमैंटरी यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि इस खरीद में बड़े आदमियों का जो सरकार के नजदीकी है जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उन लोगों की भूमिका रही हो। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण थे कि सरकार को सरसों की खरीद बीच में रोकनी पड़ी ? अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा से सरसों की खरीद चालू कर दी गई है जो अभी भी जारी है इसके क्या कारण हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सभी सवालों का जवाब देता हूं। पहला सवाल इन्होंने फर्द और जमाबन्दी का किया। इसके लेने के कारण यह थे कि राजस्थान में किसानों को सरसों की खरीद की पेमेंट आज तक नहीं मिली है और यहां पर परचेज होने की बजाये कुछ ट्रेडर्ज वहां से सरसों लाकर यहां हमारी मण्डियों में बेचने का प्रयास कर रहे थे। हमने उसी समय यह फैसला लिया कि जो हरियाणा का किसान है हम उसी की सरसों खरीदेंगे इसी कारण हमने किसानों की फर्द और जमाबन्दी देखने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, नैफेड ने एक लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद का कोटा फिक्स किया था लेकिन हरियाणा सरकार ने वह कोटा बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन किया है। हमारे यहां अढाई लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। जब नैफेड ने सरसों की खरीद करने में असमर्थता दिखाई थी तो उस समय कुछ किसान मुझ से मिले थे और उन्होंने यह कहा था कि अभी भी किसानों की जो सरसों है वह बकाया है इसलिए हमने दोबारा से खरीद शुरू की थी।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य-मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों की सरसों जो बिचोलियों ने सरकार को औने-पौने दामों में बेची क्या सरकार इस बारे में कोई इन्कवायरी करवायेगी ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि पिछली सरकार के वक्त में कुछ व्यक्ति यही काम करते थे। जब हमें इस बारे में शिकायत मिली हमने तभी यह फर्द और गिरदावरी देखकर सरसों की खरीद शुरू की थी।

डा० सीता राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सरसों की खरीद की गई है और वह खरीद आज तक जारी है उसके अन्दर जो फर्द और जमाबन्दी की बात की गई है उसमें क्या हुआ कि पटवारियों ने किसानों से पैसा ले लेकर फर्द और जमाबन्दी उपलब्ध करवाई इसकी वजह से किसानों का शोषण हुआ क्योंकि कुछ किसान लम्बे समय तक अपनी फसल को अपने पास रखने में सक्षम नहीं है इसलिए व्यापारियों ने उनकी फसल को खरीद लिया।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो हमारे सामने बैठे हैं, यह सच है कि इनकी हालत तो ऐसी है जैसे छाज तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिसमें हजारों छेद होते हैं । (शोर)

Mr. Speaker : Everybody to take the seat. Sahida Khan Ji, please put the supplementary.

श्री शाहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर तावडू में सरसों की सबसे बड़ी मंडी है वहां पर 4-4 दिन तक किसान किराए पर ट्रैक्टर लेकर लाइन में लगे रहते हैं क्योंकि किसान इतने धनवान तो होते नहीं कि वे अपने ट्रैक्टर ले सकें। 4-4 दिन तक वे किराए के ट्रैक्टर लेकर लाइन में नहीं खड़े हो सकते। वहां के हैफेड का जो मैनेजर था अगर उसने धांधली न की हो तो दिक्कत न आती। आप चाहे किसी भी एजैंसी से इन्कवायरी करवा सकते हैं कि उसने 50 रुपये बोरी के हिसाब से मिली भगत की है मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जाए। पैसे वाले जो आढ़ती थे उन्होंने नकद पैसे दिए हैं। क्योंकि पिछली योजना में मैं मंडी का चेयरमैन था इसलिए मुझे पूरा ज्ञान है और मैं किसान भी हूं। जब मैंने मंडी में जाकर उस मैनेजर से कहा तो वह कहने लगा कि सरकार में मेरा भी हाथ है आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लेना। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस मैनेजर की जरूर इन्कवायरी करवाई जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, तावडू की जो यहां पर चर्चा की गई है, वहां पर हमने 9403 मीट्रिक टन सरसों परचेज की है। जो माननीय सदस्य ने चर्चा की है, मैं समझता हूं कि आप वहां के विधायक हैं इसलिए यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसी कोई बात आपके नोटिस में आए तो उसी समय बताना चाहिए था क्योंकि मैंने पहले ही कहा हुआ है कि ऐसी बात आए तो तुरंत बताया जाए। आगे से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कोई भी ऐसी बात किसी के नोटिस में आए तो हमारे नोटिस में लाए ताकि उस पर फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके बावजूद अगर कोई भी केस हो तो वे लिखित में भेज दें हम उसकी जांच करेंगे।

विधान कार्य—

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (3) 2005. बिल

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मोशन मूव करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शुद्ध हिन्दी में किसानों की मजबूरी को समझकर उनके बिल माफ करने का ऐलान किया । हिन्दी कष्टदायक है, इतनी मुश्किल है कि इसको अंग्रेजी से भी ज्यादा सोचना और समझना पड़ता है। अगर हरियाणवी भाषा में मैं दो शब्द कहूं कि हरियाणा के लोगों का जो गांव में बसने वाले हैं, चाहे किसान हैं, चाहे गरीब हैं, अगले 10 बिल भर दो और पिछले जो 2 लाख खड़े हैं सब माफ । पहले जो लोन बिल ठीक होते थे उनके भी 5 परसैंट हर बिल के माफ होंगे। इससे बढ़िया फैसला कोई हो नहीं सकता। 5 प्रतिशत का मतलब है 20 महीनों में 2 महीने का बिल माफ । तो इस प्रकार यह 10 प्रतिशत हो गया, एक महीने का बिल होगा तो उसमें 5 प्रतिशत हो गया।

Mr. Speaker : Please move the motion, Ch. Birender Singh Ji.

Finance Minister (Sh. Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move--

> That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

जो सम्मानित सदस्यगण बजट और डिमांड्स पर बोल चुके हैं, कृपया करके वे खड़े होने का कष्ट न करें। जिनको बजट और डिमांड्स पर बोलने का समय नहीं मिला पहले उन्हें बुलाया जायेगा। दूसरों के बारे में बाद में विचार किया जायेगा।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गरिमामय सदन में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने जो बिल रखा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जिस बजट के बारे में हमने विचार विमर्श किया और जो बजट हमने पास किया तथा जिन डिमांड्स के बारे में विचार विमर्श करके सदन ने उनको पास किया है लेकिन अगर उनके बारे में मैं कोई बात नहीं कहूंगा तो इस बिल के बारे में कोई भी बात कहना अपने आप में पूर्ण नहीं हो पायेगी। अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए बहुत अच्छी तरह से माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में पैसे का प्रावधान किया है। उनको बधाई देने के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा और मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में अंदर नारनौल में 70 गांव ऐसे हैं जिनके यहां पिछले 30 साल से नहरों की सफाई के नाम पर एक कस्सी तक नहीं लगी है। इस बारे में मेरा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या उन नहरों की सफाई के लिए प्रायरटी के आधार पर बजट से

पैसा दिया जायेगा ताकि राजस्थान के साथ हरियाणा के आखिरी गांवों में रहने वाले लोग भी इस बजट के बारे में सबके साथ मिलकर खुशी मना सकें ? **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, बजट में एस०वाई०एल० का जिक्र किया गया और मेरे सामने सदन में दो पार्टियों के सदस्य बैठे हुए हैं। इधर हमारी रूलिंग पार्टी कांग्रेस है जिनका केन्द्र में जब से हम आजाद हुए हैं तब से अब तक ज्यादातर शासन रहा है। यहां हरियाणा में भी और पंजाब में भी अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। दूसरी तरफ लोकदल के साथी बैठे हुए हैं इनका हरियाणा में राज रहा और केन्द्र में भी इनकी भागीदारी रही और हरियाणा में भाजपा वाले भी इनके साथ थे। एस०वाई०एल० कैनाल के नाम पर ये भोली भाली जनता से वोट लूटते रहे और बीस साल हो गए आज तक एस०वाई०एल० कैनाल का पानी नहीं आया है । उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने हरियाणा जनता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि यह मसला हल हो गया तो इनको वोट लेने का मुद्दा नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब 1995 से हमने राजनीति की शुरूआत की तो हमारा पहला भाषण यह था कि हम एस०वाई०एल० कैनाल का पानी नहीं ला सकते, जो ला सकते हैं उनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं। हमने अपने हल्के की जनता को कहा कि हमारा तो एक ही निशाना है कि हम अपने यहां बाढ़ के पानी को लेकर आयें। हमने जनता को कहा कि दक्षिणी हरियाणा में कोई पानी हमको नहीं देगा। सब आयेंगे और हमारे वोट लेकर चले जायेंगे। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि मारूति उद्योग जैसे जो बड़े उद्योग हैं उनको ज्यादा बिजली बनाने की अनुमति दी जाये और उनसे बिजली खरीदी जाये जो हमें सस्ती पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में बाढ़ का पानी ले जाने की बात और मारूति उद्योग में अधिक बिजली के उत्पादन की बात जब हमने पिछले मुख्यमंत्रियों को कही, जिनके हम साथ थे उन्होंने हमें पागल कहा और मजाक उड़ाया कि इनको तो अक्ल है ही नहीं। लेकिन जब हमने मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात की, वित्तमंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से मिले, सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी, परिवहन मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हैल्थ मंत्री बहन करतार देवी जी से मिले और इन बातों की चर्चा की तो इन्होंने हमारी बात पर विचार किया इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं। आज हमारी बात की सुनवाई हो रही है और सभी के सामने है कि जो लोग हमें पागल कहते थे वे शायद आज अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं या इस तरह से बातें सुनने से पहले अपने कान बंद कर लेते होंगे। मौजूदा सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बन्दोबस्त दक्षिणी हरियाणा में बाढ़ का पानी पहुंचाने के लिए किया है। इसके लिए मैं हमारी सरकार को बधाई देता हूं और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चाहता हूं जिन्होंने उस समय की सरकार की हां में हां मिलाई और कहा कि दक्षिणी हरियाणा में बाढ़ का पानी नहीं जा सकता। उन अधिकारियों के बारे में जानकारी लेकर सरकार को उनकी खबर अवश्य लेनी चाहिए ताकि भविष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को कोई भी अधिकारी बाधित करने की हिम्मत न करे और गरीब लोगों का शोषण न हो पाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री महोदय से लोक कल्याण की बात कहना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग में लोक कल्याण के लिए पैसा रखा गया है यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। गरीब आदमी को मकान के निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है। गरीब आदमी को रहने के लिए एक कमरे का मकान इन्दिरा आवास योजना के तहत बना कर दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि एक परिवार में बाप है, उसकी पत्नी है, लड़की है, उसका लड़का है कहने का मतलब यह है कि एक परिवार में 5-7 सदस्य हो जाते हैं। क्या एक ही परिवार के 5 या 7 सदस्य एक कमरे के मकान

[श्री राधे श्याम शर्मा]

में रह सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक छोटा सा कमरा देकर इन्दिरा गांधी का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है ? सरकार से मेरा यह निवेदन है कि हमारे पास 4-4 बैड रूम्ज़ होते हैं फिर भी हम कहते हैं कि मकान छोटा है। आप सोचिए कि एक आदमी अपने बीवी-बच्चों के साथ एक ही कमरे के अन्दर कैसे रह सकता है ? इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि एक कमरे का मकान न दे कर कम से कम उसे तीन कमरे का मकान बना कर दें। श्रीमति इन्दिरा गान्धी बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नेता थीं और उनका नाम इस योजना के साथ जोड़ा गया है तो तीन कमरे का मकान बनाकर गरीब आदमी को दें जिससे कम से कम वह सरकार का शुक्रगुजार हो सके। डिप्टी स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि इस एक कमरे का मकान देने में भी गरीब आदमी को यह कहते हैं कि ईंट हम देंगे, जंगला हम देंगे बाकी का मलबा और सामान भी हम देंगे और नक्शा भी हम बनवाकर देंगे। इससे तो वह गरीब आदमी अपने पुराने मकान के साथ इस नए कमरे को एडजस्ट भी नहीं कर सकता है। जंगला और सीमैंट कैसा देते हैं यह भी आपको पता ही हैं। पिछली सरकार के हमारे भाई चले गए हैं लेकिन पता नहीं वहां पर इन्होंने लोगों पर क्या -क्या जुल्म किए हैं क्योंकि उनको ऐसी कच्ची ईंटें देते थे कि अगर थोड़ी सी ऊंचाई से डाल दो तो नीचे गिरते ही टूट जाएं। इन कच्ची ईंटों से बने हुए मकानों में अगर गरीब लोगों को रहना पड़ेगा और यदि किसी का मकान गिर जाए तो उनके बच्चे मरेंगे, उसकी बीवी मरेगी या वह खुद मरेगा। इस तरह से उन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है इसलिए इसके बारे में ख्याल करना बहुत आवश्यक है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि व्यवस्था बदलने में चेहरों की कोई बात नहीं लेकिन डिप्टी स्पीकर सर, जो चेहरे इतने दागदार हो गए हैं कि बार-बार ड्राईक्लीन करने के बावजूद भी वे साफ नहीं हो सकते हैं। ऐसे चेहरे अगर आगे आएंगे तो सरकार की छवि पर उनका असर जरूर होगा इसलिए डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे भांगल चौधरी के अन्दर एक ही रैस्ट हाउस है। इस रैस्ट हाउस का दरवाजा 10 फुट चौड़ा है, उस दरवाजे पर छत डाल कर वहां के डी०सी० ने मुख्यमन्त्री से कम्प्यूटर सैंटर का उद्घाटन करवा दिया और वहां पर कम्प्यूटर सैंटर बना दिया। वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने अपनी सी०आई०डी० और गुप्तचरों से यह जानकारी ली कि उसमें क्या बना है तो पता लगा कि जो कम्प्यूटर सैंटर वहां बना था दो महीने चल कर वह कम्प्यूटर सैंटर बन्द हो गया। उसके बारे में अखबारों में छापा गया । वहां पर आज भी मुख्य मन्त्री जी का उद्घाटन पत्थर लगा हुआ है। उस तरफ से रैस्ट हाउस का गेट बन्द हो गया है। हम जैसे जन-प्रतिनिधियों का रैस्ट हाउस में जाना बन्द हो गया है और वह रैस्ट हाउस भी बर्बाद हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसे-ऐसे काम पिछली सरकार के लोगों ने किये और वह रैस्ट हाउस बन्द करवा दिया। जिन लोगों ने ऐसे-ऐसे काम किये हैं उन लोगों को आगे लाने से व्यवस्था बदल नहीं सकती है। दूसरे मुझे एक बात और याद आ गई। एक ऐसे अधिकारी जिसके बीवी बच्चों ने जाना था और उसकी रेलगाड़ी छूट गई तो उसने गल्त टैलीफोन कर दिया कि रेल के अन्दर बम रखा है। रेलगाड़ी को रोका गया और वहां अफरा-तफरी मच गई। एक तरफ तो रेलगाड़ी से उतर कर लोग भाग रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की रैड लाईट की गाड़ी वहां पर जाती है तो उस गाड़ी से उतर कर लोग रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए भाग रहे हैं। लोगों ने वहां पर देखा कि यह उल्टा क्या हो रहा है। एक तरफ लोग डर कर रेलगाड़ी से उतर कर भाग रहे हैं और दूसरी तरफ लोग रेलगाडी में चढ़ने के लिए भाग रहे हैं। वहां पर लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको पीटा गया। इस प्रकार के कामों से सरकार की बदनामी हुई। ऐसे मुख्यमन्त्री सता में बैठे थे जिनके अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम हुई थी। साहब की बीवी की ट्रेन

छूट गई थी इसलिए फोन कर दिया था कि रेलगाडी में बम रखा है। डिप्टी स्पीकर सर, जब तक हमारी व्यवस्था नहीं सुधरती तब तक प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि व्यवस्था सुधारने के लिए इतने दागदार चेहरों को प्रशासन से दूर ही रखना पड़ेगा। (विघ्न)

एक आवाज : वह कौन सा अधिकारी है और उसका नाम क्या है ?

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : उसके नाम की आप बात कर रहे हैं पानीपत के डिप्टी कमिश्नर का नाम आप पढ़ ले कि वह कौन है, इतना तो आप सबको पता ही होगा। इसी तरह से अधिकारियों की मनमानी की एक और बात का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। डिप्टी कमिश्नर ने मेवात में आने का टाईम दे दिया, हमारे गरीब आदमी वहां पर बैठ कर उनका इन्तजार करते रहे। मेवात के अन्दर बहुत धूप पड़ती है और बहुत धूल उड़ती है। छः घण्टे तक औरतें वहां पर बैठी रही और डी०सी० का इन्तजार करती रहीं लेकिन डी०सी० वहां पर आई नहीं और न ही उन्होंने वहां न पहुंचने के बारे में कोई सूचना भेजी। डिप्टी स्पीकर साहब, क्या इस तरह के अधिकारी इस बजट को इम्पलीमैंट करेंगे ? इतना बढ़िया बजट सरकार ने दिया है क्या वे लोग सरकार की मन्शा को सफल होने देंगे। इस बजट की जितनी तारीफ की जाए वह कम है । इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक अधिकारियों के ऊपर जो इम्पलीमैंटिंग एजैंसियां हैं, उनको काबू नहीं किया जाएगा तब तक हमारा बजट और हमारी नीतियां कामयाब होने वाली नहीं हैं। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे यह कहूंगा कि उनकी भावना बहुत ही अच्छी है लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को जेलों के अन्दर ठूंस दिया, निर्दोष लोगों को सजा दी, इस तरह के बेईमान लोग पिछली सरकार में थे। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हमारी जो नीतियां हैं जो आप प्रदेश की भलाई के लिए करना चाहते हैं ये लोग उसको समाप्त कर देंगे अगर उन लोगों को हम ठीक ढंग से कण्ट्रोल नहीं करेंगे तो वे इन नीतियों को सही ढंग से इम्पलीमैंट नहीं करने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा बजट रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज आप किसी भी अच्छे से अच्छे सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो आप वहां से उल्टी किए बगैर बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसी तो वहां पर सफाई की व्यवस्था है। वहां पर बहुत ही बदबू होती है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने स्वास्थ्य के लिए जो इतना बढ़िया बजट रखवाया उसका कोई फायदा नहीं होगा । आपको इस बारे में गौर करना चाहिए और वहां पर अच्छे इन्तजाम करने चाहिएं ताकि आपने जो इतना अच्छा बजट स्वास्थ्य के बारे में पेश करवाने के लिए मेहनत की है, वह बेकार न जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से जिक्र किया था कि किसी डाक्टर ने कोई गड़बड़ कर दी थी, उस बारे में मंत्री जी, आपने किया क्या है। बहन जी ने मुझे बताया कि नारनौल से बहुत से आदमी आए हुए थे उन्होंने बहन जी से कहा कि प्राईवेट डाक्टरों के माध्यम से सरकारी डाक्टर ने यह कर दिया। अब आप सब जानने के लिए उत्सुक होंगे कि उस डाक्टर ने क्या किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि वह महिला, डाक्टर के पास पथरी का आप्रेशन करवाने के लिए गई थी और डाक्टर ने उसका यूट्रस ही बाहर निकाल दिया।

श्रीमती अनिता यादव : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगी कि जब मैं इस विषय में सदन में कह रही थी तो मेरी बात को पकड़ कर यहां पर मजाक उड़ाया गया था।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : बहन जी, हम आपकी बात का आदर करते हैं। इस बात का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा प्रजा का पालन पोषण करता है और राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसे लोगों को सरकार का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा तो हमारी सरकार ने जो इतना बढ़िया बजट पेश करके अपनी बढ़िया नीतियों को दर्शाया है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 40 सालों में ऐसा बढ़िया बजट पेश नहीं हुआ है। हमारी सरकार को बढ़िया नीतियों को अमल में लाने के लिए उन लोगों पर रोक लगानी पड़ेगी, लगाम खींचनी पड़ेगी जो सरकार की नीतियों के साथ खिलवाड़ करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शर्मा जी, आप वाइन्ड-अप करें।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया था। अब मैं दो मिनट में ही कन्कलूड करता हूं। मुझे बजट पर भी बोलने का मौका नहीं दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बाजरे की फसल के बारे में बोलना चाहता हूं और सदन में बाजरे के बारे में डिस्कशन हो और दक्षिणी हरियाणा वाला इस बारे में न बोले ऐसा हो नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में हमारे यहां से 2100 मीट्रिक टन बाजरे में से 1160 मीट्रिक टन बाजरा ही खरीदा गया था। लगभग 840 मीट्रिक टन बाजरा किसानों को वापिस ले जाना पड़ा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने किसानों के बाजरे को खरीदने के बारे में बजट में पैसा रखा है ताकि किसानों को मण्डियों से बाजरा और सरसों वापिस नहीं ले जाना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने नांगलदुर्ग में पानी पहुंचा दिया है इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उसके आस-पास के गांव है वहां के घरों में बैठे बच्चे क्या नांगलदुर्ग में पड़ी बाल्टी से पानी पी सकते हैं। आपको उन गांवों में भी पानी पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। नांगलदुर्ग में पानी पहुंचाया, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन नांगलदुर्ग से दस किलोमीटर दूर तक के गांवों वाले पानी नहीं पी सकते। इसलिए मेरी मांग है कि जल्द से जल्द नांगलदुर्ग की हमारी 15 गांवों की इस स्कीम को पाईप लाईन से जोड़ा जाए। इसी तरह से हमारा निजामपुर क्षेत्र है जिसको नलवाटी क्षेत्र कहते हैं। मेरी वित्त मंत्री जी से गुजारिश है कि जब बजट में आपने अलग अलग मदों में करोड़ों रुपये रखे हैं तो इस योजना के लिए भी तीन करोड़ रुपये अलग से रखे जाएं जिससे उन गांवों के भाईयों को पानी मिल सके। इसी तरह से हमारी जो भाखरी और जाखनी की दो योजनाएं पैसे के अभाव की वजह से अधूरी पड़ी हैं उनके लिए भी दो या तीन करोड़ रुपये रखे जाएं जिससे कि ये योजनाएं पूरी हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे यहां के 65 गांवों के लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों की गरिमा की बात भी यहां पर माननीय सदस्यों ने कही है। लेकिन विधायकों की गरिमा कहां रहेगी क्योंकि जब हम अपने हल्के के गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक नाली बना दो लेकिन हमारे पास तो विकास फंडज के दो पैसे भी नहीं होते तो हम कहां से उनकी यह नाली बनावाएं ? जब हम लोगों के इतने छोटे से काम को नहीं करवा सकते तो फिर विधायकों की गरिमा कहां से रहेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, बाकी हिन्दुस्तान की विधान सभाओं का तो मुझे पता नहीं यह मैं बाद में पता करके बताऊंगा लेकिन दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के अंदर हर विधायक को विकास फंड्ज के रूप में 50 लाख रुपये, एक करोड़ रुपये

या 40 लाख रुपये दी ग्रांट दी जा रही है। मुझे तो यह भी बताया गया है कि दिल्ली के विधायकों को विकास फंड्ज के दो करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक-एक करोड़ रुपये की ग्रांट हम विधायकों को भी विकास फंड्ज के रूप में दी जाए जिससे हम भी अपने-अपने हल्कों के छोटे-छोटे काम करवा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिए वित्त मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जो विधायकों के आवास हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। इनको ठीक करने के लिए केवल 50 लाख रुपये की ही बात है। 50 लाख रुपये में हमारे सारे विधायकों के निवास बहुत बढ़िया हो सकते हैं। जब गांवों से लोग हमसे मिलने के लिए यहां पर आते हैं, देहात से आते हैं तो वे क्या सोचेंगे ? अगर ये निवास ठीक करवा दिए जाएंगे तो वे भी सोचेंगे कि इनकी भी चण्डीगढ़ में कुछ इज्जत है। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद हाउस कमेटी के चेयरमैन हैं आप इनको ठीक करवाने के लिए वित्त मंत्री जी से चालीस लाख या 50 लाख रुपये की सैंक्शन करवा दें जो विधायकों के आवास हैं इनमें आप भी रहे हैं इसलिए आपको पता ही है कि इनकी दशा अच्छी नहीं है। इनकी दशा अच्छी करने के लिए इनमें एक ए०सी० एवं दो कूलर लग सकते हैं और बढ़िया फर्नीचर लग सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हबीबउर रहमान (नूंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। मैं जनाब का तहेदिल से शुक्रिया करता हूं। हमारी हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है। उसके ऊपर हमारे इस माननीय सदन के अनेक सदस्यों ने लम्बी चौड़ी चर्चाएं की। यह जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का वाकई तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि वाकई एक काबिले तारीफ बजट उन्होंने पेश किया है। मैं समझता हूं कि यह बजट अच्छा होता भी क्यूं नहीं क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जनाब भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब का दिल, उनका मन और हमारे आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का दिमाग जब इतना काबिल होगा तो बजट तो अच्छा पेश होगा ही। इन दोनों का दिल दिमाग इस पर लगा है। हरियाणा की जनता की भावनाओं के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपना बजट बनाया है और उसी का नतीजा है कि चारों तरफ बजट की तारीफ हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं मैं समझता हूं कि हमारे बी०जे०पी० के भाई, हम दस निर्दलीय विधायक भी और मेरे बसपा के भाई भी इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको आदेश दिए जाते हैं कि तुम्हें हर उस बात की जो विधान सभा में हो रही है, मुखालफत करनी है। ये बेचारे छोटे मन से यहां मुखालफत करते हैं हालांकि मन इनका भी मानता है कि हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। मैं इनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय वित्तमंत्री जी यहां बैठे है, मुख्यमंत्री जी यहां नहीं हैं, वे जहां बैठे होंगे सुन रहे होंगे। मैं अपने इलाके से संबंधित थोड़ी बहुत मांग रखना चाहता हूं सबसे पहले मैं सिंचाई के क्षेत्र को लेता हूं । ये सही है कि हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने और सरकार ने कहा है कि हरियाणा में पानी का समान वितरण किया जाएगा। यह फैसला तो बहुत ही अच्छा है लेकिन मैं मेवात की बात करता हूं। इस वक्त हमारे पूरे मेवात क्षेत्र में केवल 30 क्यूसिक पानी छोड़ा हुआ है एक छोटी सी माईनर में पानी है और बाकी कहीं पर भी पानी नहीं है। गर्मियों में अगर इस तरह के हालात रहे तो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं समझता हूं कि पानी के समान वितरण की बात मेवात में लागू नहीं हुई है, इस ओर इरीगेशन मिनिस्टर साहब ध्यान दें। मेवात भी दक्षिणी हरियाणा में आता है। संबंधित अफसरान को हिदायत दी जाए कि मेवात का ख्याल रखा जाए । मैं मेवात में

[श्री हबीबउर रहमान]

सिंचाई की समस्या के हल के लिए दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। बरसात के समय में फालतू रेनी वाटर ड्रेन्स के थ्रू, व यमुना के थ्रू, समुन्द्र में जा मिलता है मेहरबानी करके उस पानी को रोककर कोटला ड्रेन के थ्रू आकेड़ा झील में स्टोर किया जाए। उसमें जो पानी इक्टठा हो उसको फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूट्री उस झील में लगी हुई हैं उसके माध्यम से उस पानी को सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे ही इरीगेशन का काम शुरू हो जाएगा पानी की स्तर भी ऊंचा आ जाएगा। इससे पीने के पानी की समस्या का भी कुछ हल होगा। मैं जनाब से गुजारिश करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। डिप्टी स्पीकर साहब, पूरे हरियाणा के मुकाबले में हमारे यहां मेवात में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। मैं आपके माध्यम से एजूकेशन मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वहां टीचर्स नहीं हैं हमारे वहां पर टीचर्स की वैकेन्सीज को भरा जाए। वहां 400-500 बच्चों पर एक या दो टीचर हैं। इसके साथ ही अस्पतालों का यह हाल है कि वहां मरीजों का इलाज न करके केवल एम०एल०आर० काटी जाती है इस पर चैक एण्ड बैलेंस किया जाए और वहां पर डाक्टरों की पूर्ति की जाए और लेडी डाक्टर्स भी लगाएं। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा सुन रही हैं वे इस ओर ध्यान दें, वहां का दौरा करें और देखें कि मेवात के अस्पतालों की क्या हालत हो रही है जैसा राधेश्याम जी ने बोलते हुए बताया कि अस्पतालों की हालत यह है कि सही सलामत आदमी चला जाए तो उसको भी उल्टी हो जाती है जब तंदुरुस्त आदमी की यह हालत होती है तो जब आदमी वहां बीमार जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा आप खुद लगा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वाटर सप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं। पीने के पानी की समस्या जितनी मेवात ऐरिया में है उतनी शायद हरियाणा में कहीं नहीं होगी। हमारे यहां पर 6-6 और 8-8 महीने पानी नहीं आता है। जब हम इस बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है कि बिजली नहीं है, लाईन नहीं है और बजट नहीं है। आज हालत यह है कि लोग टैंकरों से पानी मंगवाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं । मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि इस मामले को भलीभान्ति देखा जाये। इसके बाद हमारे मेवात क्षेत्र में पहले ही पानी की कमी है बल्कि मेवात का क्षेत्र रेगिस्तान जैसा इलाका बना हुआ है। वहां पर आज तक कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन भी नहीं है केवल नाम मात्र का मौजूद है। पीछे 6 तारीख को वहां एक गांव में आग लग गई उस समय कोई बुझाने नहीं आया सरकार की तरफ से वहां मौके पर केवल एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी वह भी अढ़ाई घण्टे बाद वहां पहुंची और जब तक उसने आग बुझाई तब तक 60-70 घर जलकर राख हो चुके थे। मैं मेवात के नगीना में एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन खोलने की गुजारिश करूंगा। जैसा कि मेरे से पहले कई भाईयों ने बहुत कुछ कहा है। जो प्रैक्टीकली समस्याएं हैं जैसे ओल्ड ऐज पैंशन की, बी०पी०एल० कार्ड की है। इन सब का लाभ असरदार लोग और वही परिवार उठा रहे हैं जिनकी माली हालत अच्छी है वही लोग अपना बी०पी०एल० का कार्ड बना लेते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए दोबारा से सर्वे करवाना चाहिए और जो पात्र लोग है उन्हीं को आईडैंटिफाई किया जाये और उन्हीं को इसका फायदा दिया जाये जिन्होंने नाजायज तौर पर बी०पी०एल० कार्डज बनाये हुए हैं उनसे रिकवरी की जाए, ऐसी मेरी सबमिशन है। इसी प्रकार बिजली का मामला है। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेवात में बिजली बहुत कम आती है। शायद 1970-71 में बिजली गांवों में शुरू हुई थी। जो लाईन वहां उस समय खींची गई थी, तारों के लिए खम्बे लगाये गये थे, मैं समझता हूं उसके बाद नाम मात्र की ही उनमें वृद्धि की गई है। मैं समझता हूं कि रेशो के हिसाब से वहां बिजली का विस्तार किया जाए क्योंकि उसके बाद

आबादी बढ़ गई है। नई आबादी को सरकार की नई पोलिसी का फायदा मिलना चाहिए। अन्त में मैं हमारे वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को तसरीक करूंगा क्योंकि उन दोनों ही ने हर फील्ड में बड़ी ही फिराखदिली दिखाई है। मेरा निवेदन है कि ये फिराखदिली यहां भी दिखायें। उपाध्यक्ष महोदय, एम०एल०ए० गांव में आता है तो कई समस्याएं सामने आती हैं लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं होता वह खाली मन से वापिस लौट आता है। इसमें भी मुख्यमंत्री जी दिल फरयादी दिखा कर एम०एल०ए० के लिए कम से कम एक करोड़ रुपये की ग्रान्ट दें इसके लिए इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सुभाष चौधरी (जगाधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया है उस पर चर्चा करते हुए मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर से कृषि क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं वैसे तो इन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सी रियायतें दी हैं। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यमुनानगर में पापुलर प्लांट की जो लकड़ी बिकती है उसका कोई मिनीमम प्राइस फिक्स नहीं है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि पिछली सरकार ने 5 सालों के अन्दर जो किसानों की दुर्दशा की है, 500 रुपये क्विंटल बिकने वाला पापुलर प्लांट 170 रुपये और 200 रुपये पर लाकर खड़ा कर दिया था और आज के किसान की हालत तो यह है कि वह बर्बादी की कगार पर खड़ा है इसलिए मेरा निवेदन है कि पापुलर प्लांट की लकड़ी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन्क्लयूड किया जाए ताकि किसान को उसका फिक्स रेट मिल सके। सरकार इसका मिनीमम प्राइस फिक्स करे ताकि किसान के साथ आढ़ती और व्यापारी धोखा न कर सकें। आज स्थिति यह है कि किसान अपना माल मंडी में बेचने के लिए लेकर जाता है तो उससे 6 प्रतिशत आढ़ती खा जाता है। उसके बाद जो व्यापारी है वह भी उससे तरह-तरह की काट कर किसान को नुक्सान पहुंचाता है **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पापुलर प्लांट की लकड़ी के लिए मिनीमम स्पोर्ट प्राइस फिक्स की जाए और इसको एग्रीकल्चर प्रोडयूस में इन्क्लयूड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो इंडस्ट्री पोलिसी बनाई है वह काबिले तारीफ है। मेरी कंस्टीच्यूंसी जगाधरी जो कि कभी मैटल इंडस्ट्री के नाम पर पूरे हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर मशहूर थी आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि यह इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बन्द होने के कगार पर खड़ी है। उसका मूल कारण यह है कि जयपुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मैटल इंडस्ट्रीज का बहुत फैलाव हो चुका है। दूसरी स्टेट्स तरह-तरह की सहूलियतें मैटल इंडस्ट्रीज को दे रही हैं। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी इस उजड़ती हुई इंडस्ट्रीज के लिए खास रियायत दे। जो वैट प्रणाली सरकार ने लगाई है उससे भी इसे मुक्त रखा जाए और इस इंडस्ट्री को शिडयूल-सी में रखकर रियायतें दी जाएं, दूसरा तरीका यह है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को वैट से छूट दी गई है उसी आधार पर कंसीडर करके जगाधरी की मैटल इंडस्ट्री को बचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छा कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय ने 600 मेगावाट थर्मल प्लांट यमुनानगर में लगाने की मंशा जाहिर की है। थर्मल प्लांट की जो पुरानी टैक्नोलोजी है वह ओबसुलीट टैक्नोलोजी है, इस मामले में मेरा निवेदन है कि सरकार इसके ऊपर पुन: विचार करके इसको गैस बेस्ड करके बिजली सप्लाई करेगी तो किसानों और दूसरे लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। मैं सरकार का ध्यान कुछ और समस्याओं की ओर भी दिलाना चाहूंगा। मेरे शहर के अन्दर 100 साल पुराना PWD रैस्ट हाउस था जो कि पुराना होने की वजह से खत्म हो चुका है। चौ० बंसी

[श्री सुभाष चौधरी]

लाल की सरकार में कर्ण सिंह दलाल जी PWD मिनिस्टर होते थे उस समय PWD रैस्ट हाऊस फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और उसके लिए 22 लाख रुपये मंजूर किये गए थे और उसमें से साढ़े 4 लाख रुपये खर्च किए गए लेकिन चौटाला साहब की सरकार आई सो उस रैस्ट हाउस को बन्द कर दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस रैस्ट हाउस को जल्दी कम्पलीट कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि म्यूनिसिपल कमेटियों की हालत खराब है इसमें कोई शक नहीं है । इनके लिए पैसा भी बहुत अलाट किया है । मेरा वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जगाधरी म्यूनिसिपल कमेटी में बहुत बड़ा पुलिस कम्पलैक्स बना हुआ है जिसके कारण होम विभाग की तरफ कमेटी का 1.82 करोड रुपये डिवैल्पमैंट चार्जिज का बकाया है। जगाधरी नगर पालिका की माली हालत भी बहुत खराब है इसलिए यह पैसा नगर पालिका को सरकार की तरफ से दिया जाये ताकि शहर में कुछ विकास कार्य हो सकें। इसी तरह से 90 लाख रुपये इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट, जगाधरी के बकाया पड़े हैं। वह पैसा भी नगर पालिका जगाधरी को ट्रांसफर किया जाये ताकि शहर की तरक्की हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जगाधरी शहर की आबादी सवा लाख है और वहां पर 30 बैड का हास्पिटल है। अध्यक्ष महोदय, जगाधरी इण्डस्ट्रियल टाउन है और दूसरे छोटे-छोटे शहरों में भी 100-150 बैडों के हास्पिटल हैं इसलिए जगाधरी में भी कम से कम 60 बैड का हास्पिटल बनाने का प्रावधान किया जाये। यमुनानगर जिला है और वहां पर सिर्फ 50 बैड का ही हास्पिटल है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसको 50 बैड से बढ़ाकर 100 या 150 बैड का हास्पिटल बनाया जाये ताकि वहां की जनता को सुविधा हो सके। अध्यक्ष महोदय, मुस्तफाबाद छोटा टाऊन है। 1998 में वहां पर सरकार ने अनाज मण्डी बनाने की घोषणा की थी और उसके लिए 78 लाख रुपये का प्रावधान भी हो गया था। यह केस आज भी मार्केटिंग बोर्ड के पास पैंडिंग है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस मण्डी को जल्दी से जल्दी पूरा करवाये जाये ताकि वहां के जमीदारों को और आढ़तियों को परेशानी न हो। मुस्तफाबाद में जगाधरी से डेढ़ गुना ज्यादा अनाज आता है इसलिए उस अनाज मण्डी को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी मुस्तफाबाद बहुत बैकवर्ड एरिया है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर आई०टी०आई० सैंटर बनाने का प्रबन्ध किया जाये। मुस्तफाबाद के चारों तरफ काफी गांव हैं जिनमें गरीब तबके के लोग रहते हैं। मुस्तफाबाद में आई०टी०आई० बनने से गरीबों के बच्चे भी टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल पोलिसी के बारे में सरकार ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। स्पीकर सर, आप भी जानते हैं कि यमुनानगर जिले में फ्रूट बहुत होते हैं, चाहे आम है, लीची है, अंगूर है या चिकू आदि यानि हर किस्म के फ्रूट होते हैं तथा हरियाणा के साथ लगते यू०पी० के सहारनपुर और देहरादून में भी काफी फ्रूट होते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुभाष जी, प्लीज आप वाईड-अप करें। इसके अतिरिक्त जो सदस्य पहले बजट पर बोल चुके हैं कृपा करके वे उठने की तकलीफ न करें।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं फ्रूटस की बात कर रहा था कि यमुनानगर में फ्रूटस बहुत होते हैं इसलिए वहां पर फ्रूट प्रोसैसिंग यूनिट सरकार की तरफ से खोलनी चाहिए ताकि वहां के किसान उसका फायदा उठा सकें। इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यमुनानगर जिले में से यमुना नदी

गुजरती है और हरियाणा के किसानों की जमीन यमुना पार भी है। उस जमीन पर किसी तरह का डिस्प्यूट भी नहीं है लेकिन उसमें सरकार की तरफ से किसानों को ट्यूबवैल के कनैक्शन नहीं दिए जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस जमीन पर यमुना पार डिस्प्यूट नहीं है, वहां किसानों को ट्यूबवैलों के कनैक्शन दिए जायें ताकि वे अपनी फसलों की सिंचाई सही ढंग से कर सकें। धन्यवाद ।

श्री सुखबीर सिंह सोहना : अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Sukhbir Singh Ji, is there any provision. You are wise enough. There is no provision. Please take your seat. Bhardwaj Ji please proceed. (Interruptions) This is not the way. Let the House proceed. कुछ तो सिद्धांत रहने दो। You want double time.

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट के बारे में मैं सिर्फ एक लाईन कहूंगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं बजट के प्रति एक ही लाईन में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहूंगा। The Budget was beautiful because the receipt has increased and there is no added tax. इसके बाद में सीधे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, भिवानी एक बहुत पुराना जिला है। हरियाणा के बाकी जितने भी जिले हैं पिछले 30 सालों में जितनी तरक्की उन्होंने की है उतनी तरक्की भिवानी जिले ने नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष भिवानी जिले की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी समस्या जो मेरे क्षेत्र में है वह पेयजल की समस्या है चाहे वह शहर के क्षेत्र हैं और चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी जगहों पर पेयजल की समस्या है। शहरी क्षेत्र में 41 कॉलोनियां अभी सरकार द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं। लेकिन वहां पर पानी और सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। मैं जब भी वहां पर जाता हूं तो उन कॉलोनियों के लोग कहते हैं कि हमारी हालत तो गांवों से भी ज्यादा बुरी है। गांव में कम से कम कूंए तो थे और यहां पर पानी के लिए कई कई बार हैंड पम्प पर जाना पड़ता है। हमारे भिवानी के अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पानी खारा है। इस समय सदन में पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर बैठे हुए नहीं हैं लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि पब्लिक हैल्थ के मद से कुछ पैसा भिवानी जिले के लिए दिया जाए ताकि जो बाहर की कॉलोनियां है उनको पानी की सप्लाई समुचित रूप से की जा सके। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा है। मेरे क्षेत्र में प्रहलादगढ़ गांव है। राव दान सिंह जी अभी बैठे हुए नहीं हैं यह उनका भी गांव है। पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब से मेरी यह प्रार्थना है कि वहां पर वाटर वर्क्स बनाया जाए। मैं जब भी वहां पर जाता हूं तो ग्रामीण महिलाएं लाईन में लगी होती हैं और उनके सिर पर टोकनियां और मटकियां लदी होती हैं और उन लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत होती है। पेयजल के अलावा सिंचाई का जो पानी है उसकी भी हमारे क्षेत्र में काफी कमी है। मेरे क्षेत्र में आठ गांव ऐसे हैं जोकि बिल्कुल टेल पर लगते हैं। एक बहुत पुराना पम्प हाउस वहां पर माईनर पर बना हुआ है और उससे उमरावत में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। वहां के ग्रामीणों की मांग है कि इस पम्प हाउस को हटाया जाए और एक आल्टरनेटिव चैनल वहां पर बनाई जाए ताकि कम से कम ग्रेविटी से बहाव से जो पानी आता है वह तो उनको मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यह पम्प हाउस कम से कम 30 साल पुराना है और उसकी केपिसिटी 30% से भी कम है और बिजली की हालत यह है कि कभी होती है और कभी होती ही नहीं जिसके कारण उनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिल पाता

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

है। यहां पर तालाब भी सूखे रहते हैं और उनके जलघर भी सूखे रहते हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि इस पम्प हाउस को यहां से हटा दिया जाए और एक आल्टरनेटिव चैनल बना दी जाए ताकि उन ग्रामीणों को कुछ न कुछ पानी मिल जाए। उमरावत के साथ पूर्णपुरा, नांगल, ढाणा लादनपुर, ढाणा नसान, गौरीपुर किंतलाना आदि गांव और हैं यदि इस पम्प हाउस को हटा दिया जाए और नया चैनल बना दिया जाए तो इन गांवों को कुछ न कुछ पानी ठीक प्रकार से मिल सकेगा। इसी तरह से इरिगेशन डिपार्टमैंट की बात कहना चाहता हूं। रूपगढ़ माईनर पर आर०डी० 7000 बुर्जी पर लिफ्ट लगवाने के लिए मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को लिखित रूप में भी दिया हुआ है। मेरे हल्के की यह भी बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं चाहता हूं कि इसे जल्दी पूरा कर दिया जाए। इसी तरह से अहीरवाल का कुछ इलाका मेरे क्षेत्र में पड़ता है। उन भाईयों को भी बहुत आशाएं हैं कि कांग्रेस की सरकार आई है और वहां पर भी यह पानी दे सकेगी। इसके साथ ही सीवरेज का भी हाल हमारे क्षेत्र में बहुत खराब है। मुझे लगता है कि सारी डिगनेटरीज not only from Haryana but from all over India, they have visited Bhiwani in recent past. चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी के निधन पर आप सब लोगों ने वहां पर देखा होगा कि हमारी सीवरेज खराब होने की वजह से वहां की सभी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। माननीय गवर्नर साहब जब वहां पर गए तो भी इतना टार्चुअल रास्ता बना हुआ था। सीवरेज की रिपेयर के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। मंत्री महोदय, सबसे पहले हमारी सड़कों के लिए वहां पर पैसा दिया जाए। जहां तक उद्योगों का सवाल है, हमारे यहां उद्योगों की हालत ठीक नहीं है। पिछले तीस सालों में उद्योगों के क्षेत्र में जहां इस जिले को कुछ ऊपर जाना चाहिए था वह निरन्तर नीचे की ओर जा रहा है। वहां पर मोसा फैक्टरी थी वह बन्द हो गई, सैंचुरी ट्यूब की फैक्टरी थी वह बन्द हो गई। एक रामा फाईबर की फैक्टरी थी वह भी बंद हो गई और टी०आई०टी० में किसी जमाने में सारे हिन्दुस्तान में एक ही ऐसी मिल थी जहां टैक्सटाईल का विश्व स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस मिल में किसी समय पांच हजार श्रमिक काम करते थे और आज वहां पर पांच सौ श्रमिक भी काम नहीं कर रहे हैं। स्पीकर सर, उद्योगों के मामले में भिवानी बहुत पिछड़ा हुआ है और बी०टी० मिल भी वहां पर है। मैं चाहता था कि कपड़े का हब जो कलस्टर पानीपत में बनाया गया है। कम से कम उसका कुछ हिस्सा बड़ी आसानी से भिवानी में दिया जा सकता था। मेरी इंडस्ट्री मिनिस्टर जी से रिक्वैस्ट है कि वे भिवानी में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। मेरा शिक्षा मंत्री महोदय जी से भी निवेदन है कि भिवानी में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सभी नार्मज पूरे करते हैं, उनको अपग्रेड करने का कष्ट करें। मैंने एक प्रश्न रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के बारे में किया था, उस बारे में मिनिस्टर महोदय जी ने एक पत्र का जिक्र किया था, वह पत्र 1970 का है। आज बायो टैक्नोलोजी और नैनो टैक्नोलोजी की हम बात करते हैं और दिल्ली में देखा गया है कि एक-एक पिल्लर पर पुल बनाया गया है। क्या वैसे ही तरीके से भिवानी में भी पुल बनाने के बारे में कार्यवाही की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस सिस्टम से पूल वहां पर बनाया जाएगा तो अनाथालय की एक भी ईंट नहीं उखाड़नी पड़ेगी। नई टैक्नोलोजी से यह ओवर ब्रिज अच्छी तरह से बन सकता है इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे किसी अच्छी कन्सलटैंसी से फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले लें ताकि इस ओवर ब्रिज को बनाने की प्रक्रिया को आगे जारी रखा जा सके।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी कालोनिज में बरसाती पानी इक्ट्ठा हो जाता है और मंत्री जी ने इस बारे में मुझे लिखित में दिया था कि 25 प्रतिशत भिवानी के लिए पैसा

अलॉट किया है ताकि वहां से पानी निकाला जा सके। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि हमारा जो 75 प्रतिशत भिवानी का क्षेत्र रह गया है उसके बारे में भी ये सोचें ताकि वहां से भी बरसाती पानी की निकासी का इन्तजाम किया जा सके।

मैंने सरकार को पहले भी कहा है कि सरकार को भिवानी में मैडिकल कालेज शुरू करने में काफी सहूलियत होगी क्योंकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। वहां पर 300 बैड का हास्पिटल आलरेडी फंक्शनिंग में है। स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठी हुई हैं और वे मेरी बात सुन भी रही हैं। इन्होंने जो जमीन की प्रोब्लम के बारे में कहा था तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां पर 21 एकड़ जमीन आलरेडी एग्जिस्ट करती है और 21 एकड़ जमीन कहीं और ली जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से मैडिकल कालेजिज ऐसे देखें हैं, जहां पर एकेडैमिक ब्लॉक अलग हैं, क्लीनीकल ब्लॉक अलग हैं। मंत्री जी वहां पर बहुत ही कम खर्चे में मैडिकल कालेज बन सकता है। अगर यह मैडिकल कालेज बन जाएगा तो भाई नरेश यादव जी ने जो डिमान्ड की थी वह भी पूरी हो जाएगी क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में कोई भी मैडिकल कालेज नहीं है। मंत्री जी वहां पर पेशंटस का इनफलो बहुत ज्यादा है, वहां पर सभी डिपार्टमैंट्स भी हैं। मुझे सदन में यह बताने में खुशी हो रही है कि वहां का जो आपरेशन थियेटर है वह रोहतक मैडिकल कालेज और एम्ज से भी अच्छा है। वहां पर बहुत से लेटस्ट उपकरण हैं, प्राईवेट वार्ड भी बहुत सुन्दर है अगर मंत्री जी वहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो पी०जी०आई० जैसा मैडीकल कालेज वहां पर तैयार हो जाएगा। मेरी स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी से प्रार्थना है कि वे इस ओर जरूर ध्यान देंगी और कुछ न कुछ इस बारे में करेंगी। स्पीकर सर, मैं रोहतक मैडिकल कालेज के बारे में भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले उस कालेज के स्तर का बहुत नाम था, वहां पर डाक्टर बरयाम सिंह, डाक्टर केशवाणी, डाक्टर सी० प्रकाश और डाक्टर नैणी जैसे धुरंदर थे, जिनका भारत में ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। आज उस कालेज में बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि वहां पर मैरिट और सिनियोरिटी को इग्नौर किया गया है। डायरैक्ट भर्ती के कारण जो वहां पर टीचर्ज थे वे जूनियर हो गए हैं और जो स्टूडैंटस थे वे हैड आफ दि डिपार्टमैंट हो गए हैं। मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी से, वित्तमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर सिनियोरिटी और मैरिट को हम इग्नौर करेंगे तो वह शिक्षा चाहे मैडिकल की हो या दूसरी शिक्षा हो हम उसमें प्रफैक्शन नहीं ला सकेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि सिनियोरिटी और मैरिट बिल्कुल भी इग्नौर नहीं होनी चाहिए।

स्पीकर सर, मैडिकल कालेजिज और अस्पतालों में मैंने एक अजीब सी बात देखी है कि वहां पर यू०एस० दहिया नाम की एक प्राईवेट लैब काम कर रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि जब सभी अस्पतालों में और मैडिकल कालेजिज में लैबोरेटरिज है तो प्राईवेट लैब को सरकारी संस्थानों में ठेका क्यों दिया गया है ? यह प्रथा बिल्कुल ही गलत है। स्पीकर सर, यह काम पिछली सरकार ने शुरू किया था। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रथा को तुरन्त बंद किया जाना चाहिए।

स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धर्मस्थल के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा । मैं जिस धर्मस्थल के बारे में कहने जा रहा हूं वह चौधरी रणबीर सिंह जी

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

के क्षेत्र में पड़ता है और मैं भी वहां पर जाता हूं। वहां के पुजारी हमेशा मुझे कहते हैं कि धर्मस्थल पर जो सरकार की तलवार लटकती है वह नहीं लटकनी चाहिए। वहां के पुजारी मुझसे कहते हैं कि आपकी सरकार अब आई है तो आप इस बारे में मुख्यमंत्री जी से कहें। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि यह धर्मस्थल, धनबौरी जो बरवाला क्षेत्र में पड़ता है, उस पर सरकारी तलवार नहीं लटकनी चाहिए। स्पीकर सर, जिस परम्परागत ढंग से वर्षों से वहां पर पूजा होती आई है उसी 12.00 बजे प्रकार से वहां का काम आगे भी चलना चाहिए। अंत में मैं स्वास्थ्य मंत्री से एक बात और कहना चाहता हूं कि आर०सी०एच०-II जो स्कीम है यह एक बहुत ही स्वागत योग्य स्कीम है। इसके लिए अगले पांच सालों में केन्द्र से 748 करोड़ रुपये की सहायता मिलनी है और इस साल भी इस स्कीम के तहत 124 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें यह अच्छी बात है कि जो प्रैग्नैंट लेडीज होंगी उनको जो एक वाउचर दिया जाएगा उसके लिए 500 रुपये रखे हैं जोकि बहुत ही कम है। मैं डाक्टर होने के नाते इस बारे में ठीक बता सकता हूं कि डिलीवरी के लिए 500 रुपये से ज्यादा सामान और दवाईयां लग सकती हैं इसलिए यदि इसके लिए एक हजार रुपये की राशि कर दी जाएगी तो ठीक रहेगा। तीन सौ रुपये गाइनोलोजिस्ट को और दो सो रुपये पैडीट्रिशियन को देने होंगे क्योंकि एक नवजात शिशु का भी हक है कि ये उसको देखें। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसमें एक हजार रुपये की राशि कर दें। अंत में मैं सिर्फ एक लाईन कहना चाहता हूं कि हमें क्वालिटी ऑफ लाईफ हरियाणा के लोगों की इम्प्रूव करनी चाहिए और हमें केरला का उदाहरण, माडल बनना चाहिए उसकी कॉपी करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री ए०सी०चौधरी (फरीदाबाद) : शुक्रिया स्पीकर साहब, इससे पहले कि मैं अपनी बात सरकार के लिए आपके सम्मुख रखूं, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से बजट पर बोलते वक्त आप काफी लोगों के साथ लिबरल रहे हैं उसी तरह से मुझे भी आप बोलने का पूरा मौका देंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात इस सैशन में रखूं खास तौर से जबकि इस पूरे हफ्ते में मेरी आंख की तकलीफ की वजह से मैं ऊंची आवाज सुनना भी गवारा नहीं कर पा रहा था, आज सैशन में पहली बार मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे उम्मीद हैं कि आप मुझे लिबरली समय देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुझे याद न दिलानी पड़े। स्पीकर साहब, इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए सबसे पहले मैं लोकल बॉडीज से संबंधित विषय पर अपनी बात रखूंगा। स्पीकर साहब, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं मैं आज की कांग्रेस सरकार जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रही है, उसको कामयाबी के सौ दिन पूरे होने पर मुबारिकवाद देता हूं। सौ दिन के बाद ब्याज वाले दिन किसानों के लिए बेहतरीन पैकेज लाकर देने पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि योग्य पार्टी ही सुयोग्य नेतृत्व दे सकती है और सुयोग्य नेतृत्व ही प्रान्त का और देश का भला कर सकता है। मैं उनको इसके लिए हार्दिक मुबारिकवाद देता हूं। हमारी कल्चर में बुजुर्गों ने हमारे लिए अखान छोड़ी है कि खबीश और अहसान फरामोश इन दोनों का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनका जब भी जिक्र करेंगें तो इनकी उम्र और बढ़ती है। स्पीकर साहब, मैं कोशिश करूंगा कि पिछली सरकार की कारगुजारियों को किसी शख्स से न जोड़कर, किसी का नाम लेकर अपने दुख का जिक्र करूं। फिर भी अगर कहीं जिक्र आ भी जाए तो मैं उनकी आत्माओं से भी और हाउस से भी माफी मांगूगा। स्पीकर साहब, फरीदाबाद जिसकी नुमाइन्दगी मैं करता हूं, इसी कांग्रेस की सरकार ने उसको इस तरह से बसाया कि उसका नाम हिन्दुस्तान के मानचेस्टर के तौर पर रखा गया। बार-बार इंदिरा जी ने और नेहरू जी ने वहां पर आकर ऐसी

ऐसी चीजें तोहफे के तौर पर दी जिसकी वजह से फरीदाबाद दुनिया के नक्शे पर एक औद्योगिक नगर के तौर पर स्थापित हुआ। एशिया में यह छठे नम्बर पर था और दुनिया में इसका नम्बर 12वां था लेकिन जब से पिछली सरकार का काला और मनहूस साया आया तब से फरीदाबाद तबाह होकर रह गया है और आज इसका हरियाणा में भी 12वां नम्बर नहीं है शायद इसका कहीं नम्बर ही नहीं है। आज वहां पर पानी से भीगी हुई, टूटी हुई सड़कें हैं, लाईटें नहीं हैं, पार्क उजड़े हुए हैं कोई चीज आज वहां ऐसी नहीं है जो एक शहर के लिए हो सकती है और जिससे एक शहर की पहचान हो सकती है। फरीदाबाद इन चीजों से बिल्कुल वंचित हो चुका है मैं इतना कह सकता हूं कि कोई वक्त था जब मारूति ने टयूबलैस टायर इंट्रोड्यूस किये थे तो उनकी प्रोसीडिंग्ज इस बात की गवाह है उन्होंने कहा था कि फरीदाबाद में टैस्टिंग कर दी जाए। क्योंकि इसकी सड़कें बेहतरीन थी और अब उसके बिल्कुल उलट हैं। दुर्भाग्य से आज यह देश में ही नहीं दुनिया में भी इसके उलट शहर है आज उस शहर में 500 से ज्यादा प्राइवेट टैंकर पीने का पानी गली गली में बेच रहे हैं। वहां के लोग अपनी मजबूरी से अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पी रहे हैं और वह भी पैसे खर्च करके पी रहे हैं। इससे हमारे वहां महामारी का खतरा पैदा होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसका सर्वे कराए और सबसे पहले जो पीने के पानी की समस्या है उसका निदान करे। मैंने अपने कार्यकाल में जब मैं मंत्री था रेनीवैल स्कीम बनाई थी जिसका नाम रेनीवैल स्कीम फौर एन०आई०टी० फरीदाबाद था। पिछली सरकार ने उसका सारा ढांचा बदल दिया। रेनीवैल स्कीम एन०आई०टी० फरीदाबाद वाली का 15 परसैंट पानी फरीदाबाद को मिलता है और शेष 85 परसैंट पानी बेचा जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि वह पानी भी ऐडजौइनिंग एरिया में दिया गया । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे ऐडजौइनिंग एरिया में जिसकी जरूरत एन०आई०टी० से दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है और अगर है तो वह नहर के किनारे है और उसके लिए अलग से रेनीवैल लग सकता है, उसके लिए सरकार सक्षम है और उनको अलग से पानी दे सकती है। मैं आपसे कहूंगा कि फरीदाबाद की स्थिति ग्राफिकली बड़ी अजीब है। जहां एक तरफ अरावली की पहाड़ी है जिसकी रेंज अंडरग्राउंड चलती है और अंदर पत्थर हैं। दूसरी तरफ जी०टी० रोड़ और रेलवे लाइन है जहां पानी मिलना मुमकिन नहीं है। अगर टयूबवैल बोर किए जाएं तो वहां पर दो हजार गैलन पर ऑवर पानी आता है जबकि आम टयूबवैल का पानी 25 हजार गैलन आता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि टौप प्रायोरिटी पर रखकर यहां के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाए। मैं हैरान हूं कि जहां पानी के लिए हम रोते रहे वहां पिछली सरकार ने 18 रुपये फ्लैट रेट वाले पानी को 40 रुपये पर मंथ किया था और उसके बाद सीधे 300 रुपये पर मंथ कर दिया। उस की आंख इतनी खराब थी कि वह पानी और दूध के रंग में फर्क नहीं कर सका। गरीब आदमी का तो 300 रुपये पर मंथ दूध का बिल भी नहीं आता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह * शब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने का किसी नाम नहीं लिया। फरीदाबाद से चुंगी हटा दी गई और चुंगी के बदले लोकल एरिया डवलपमैंट टैक्स लगाया गया और यह टैक्स चुंगी के मुतबातर में लगाया गया। जिस सिविक बॉडी को किसी रेवेन्यू सोर्स से वंचित किया जाता है तो उस सोर्स के अल्टरनेटिव सोर्स दिया जाता है और लोकल एरिया डवलपमैंट टैक्स उसी के बदले लगा। आप हैरान रहेंगे कि पिछले 9 साल में फरीदाबाद का हिस्सा 450 करोड़ रुपये बनता था, लेकिन

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

[श्री ए०सी० चौधरी]

उसकी जगह उन्हें 1 करोड़ 5 लाख रुपया दिया गया। इससे बड़ा भद्दा मजाक और कोई नहीं हो सकता। फरीदाबाद नगर निगम जमीन बेचकर अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें दे रहा है। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से बात की और उनकी मेहरबानी से मेरी रिक्वैस्ट पर वहां नगर निगम को कुछ पैसा दिलाया, थोड़ी सी रकम मिली तो उस बारे में मैंने कमिश्नर साहब से पूछा कि उस रकम का क्या किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह हमने तनख्वाह में बांट दी । ये हालत है वहां पर। ये दुर्दशा पिछली सरकार ने की थी। यह लोगों की ऐट्रोसिटीज का बदतरीन नमूना है। जो-जो बुराई मैं कर रहा हूं वह मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। ऑन ओथ कह रहा हूं। फरीदाबाद में झुग्गी-झोपड़ियों की बहुतायत है वहां 11000 आइडैंटिफाइड लोग उन झुग्गियों में रहते हैं जिनका पिछली सरकार ने पानी भी बंद करा दिया था मरम्मत के काम बन्द कराये गए, बिजली के बल्ब और ट्यूबलाईटस जो हमने अपने समय दिए थे, उन सभी के कनैक्शन काट दिए और एक आर्डर कर दिए कि कोई पैसा न लगाया जाए जबकि पैसा सैंटर से बतौर ग्रान्ट आता है।

Mr. Speaker : Thank you, Chaudhary Sahib, wind up your speech.

श्री ए.सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं तो पहली बार बोल रहा हूं मुझे दस मिनट और दिए जाएं।

Mr. Speaker : Please wind up your speech.

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, ठीक है मैं जल्द से जल्द पहलों में पढ़ देता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो झुग्गियों की बिजली काटी है उस आर्डर को फौरी तौर पर निरस्त करें और उन लोगों को सुविधा दें। जो मरम्मत के काम हैं वे तेजी से कराये क्योंकि वे लोग अपने बच्चों के साथ गन्दगी के किनारे बैठे हैं जहां आम आदमी शौच भी नहीं करता, वहां पर वे अपने बच्चों को लेकर सोते हैं, जागते हैं, और रोजमर्रा के काम करते हैं। इसी के साथ स्पीकर साहब, जो कालोनियां हैं वहां से पूरी सुविधाएं हटा ली है यह कहकर कि वे अन-अप्रूवड हैं जबकि उनसे डिवलैपमैंट चार्जिज लिया जा रहा है। सरकार ने यह फैसला कर दिया कि जो डिवलैपमैंट चार्जिज हैं उस पर ब्याज भी लगाया जाए ऐसा लगता है जैसे डिवलैपमैंट चार्जिज उनके घर से पैसा लेकर उधार दिए थे। आज वहां पर ब्याज वसूल किया जा रहा ह है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको फौरी तौर पर निरस्त करें और डिवलैपमैंट चार्जिज को किश्तों में लिया जाए तभी आगे चलकर फरीदाबाद फिर से विकसित हो सकता है। आज फरीदाबाद में ही नहीं सारे हरियाणा में शहरों की दुर्दशा हो चुकी है। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि चुंगी को फौरी तौर पर पंजाब पैटर्न पर दोबारा से बहाल किया जाए तभी लोकल बॉडिज और कमेटिज के पास पैसा आयेगा और वे अपने शहरों को सुन्दर बनाने में सक्षम होंगे। स्पीकर सर, आपको बखूबी पता है कि पिछली सरकार के समय में जो लोग हिनीयस क्राइम में इन्वोल्वड थे और सजा भुगत रहे थे, उनको छोड़ कर क्रिमीनल्ज की हौसला अफजाई की है। लॉ एण्ड ऑर्डर पर कन्ट्रोल पूरी तरह से नहीं आ पाया है। सरकार फौरी तौर पर इन्वेस्टीगेशन को अलहदा करे और वॉच एण्ड वार्ड में और मजबूती लाकर इसको दो हिस्सों में कर दिया जाए ताकि लॉ एण्ड ऑडर अच्छी तरह से मेनटेन हो सके। स्पीकर साहब, हमारे फरीदाबाद में एक ही बस अड्डा है उसके गिर्द 100 मीटर से 300 मीटर की रेंज में एक गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल है, 2 मन्दिर है, दो ब्वायज के सीनियर सकैण्डरी स्कूल्ज हैं और एक स्टेडियम है। अजीब बात यह है कि एक्साईज एक्ट के मुताबिक इन संस्थाओं

की एक किलोमीटर की रेंज में कोई शराब खाना नहीं खुल सकता है लेकिन वहां पर अनअप्रूवड अहाते चल रहे हैं जिनमें स्पूरियस लिकर पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको फौरी तौर पर बन्द किया जाए। एक बादशाहखान सिविल अस्पताल जिसकी बिल्डिंग 9-10 साल पहले 1/5 बन चुकी थी उसके बाद उस बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया गया। वह बिल्डिंग चार मंजिला है परन्तु वहां पर रैम्प नहीं है। अगर चौथी मंजिल से किसी पेशेंट को तकलीफ हो जाए या बिजली बंद हो जाए और उसको नीचे उतारना पड़े तो या तो उसको वहीं मरना पड़ेगा या उसको ऊपर से नीचे पटकना पड़ेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस अस्पताल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। इस अस्पताल में न तो कोई मेजर इक्विपमैंट है न कोई मशीन है न कोई टैस्टिंग मशीन है इसकी वजह से वहां पर लोग प्राईवेट प्रैक्टिशनर के हाथों लूट रहे हैं। एस्कोर्ट अस्पताल तो इतना महंगा है कि वहां बिल नहीं दे सकने की हालत में लोग लाश को वहीं छोड़ देते हैं, ऐसे बीसीयों केस वहां पर हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे 14 गांवों को एक क्लस्टर है वहां पर कोई गर्ल्ज कालेज नहीं है वे गांव इसके लिए जमीन और आधे पैसे देने के लिए तैयार है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस गर्ल्ज कालेज को बनाया जाए।

Mr. Speaker : No more time is allowed to speak. please sit down.

श्री ए०सी०चौधरी : स्पीकर साहब, थोड़ा समय और दीजिए।

Mr. Speaker : Wind up your speech, Chaudhary Sahib. आप तो सरकार में मंत्री रहे है इतने समय में तो बहुत कुछ हो जाएगा।

श्री ए०सी०चौधरी : स्पीकर साहब, आज फरीदाबाद की आबादी 12 लाख हो चुकी है। वहां सीवरेज की लाइन 4 इंच है, एक बारिश आती है तो सारी गन्दगी घरों में आ जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब फरीदाबाद की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है तो वहां सीवरेज की लाइनें नई डाली जाएं, अब तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट भी इसके लिए पैसा दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं रिहैबिलिटेशन के बारे में मांग नं० 13 पर कुछ कहना चाहूंगा, वहां पर जो पुरानी अलाटमैंट है, विडो होम दिए गए हैं, जो आजादी की जंग में मारे गए उनको जो मकान दिए गए हैं।

Mr. Speaker : Please wind up your speech, Chaudhary Sahib.

श्री ए०सी०चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विडो होम जो अलाट हुए है, जो अलाटिड मकानों के साथ एडजस्टिड लैण्ड है उसकी पहले कीमत कांग्रेस सरकार ने तय की थी, चौटाला साहब की सरकार ने आते ही वे 75 रुपये और 150 की बजाय 1250 और 5000 रुपये कर दिए गए। इसको फौरन वापिस कर दिया जाए इससे मलकियत में इजाफा हो जाएगा और सरकार को काफी पैसा मिलेगा। राशन कार्डों के मामले में कई साथियों ने कहा कि पीले और लाल कार्ड इन्कम टैक्स पेयी इस्तेमाल कर रहे हैं और वे कार्डज गरीब आदमियों को नहीं मिल रहे इसलिए इसका फौरन रिव्यू कराया जाए। मेरे हल्के में सिकरोना और फिरोजपुर माइनर हैं इनकी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chaudhary Sahib, you are a senior most Member of the House and you are disobeying the Chair. You have already been given sufficient time. Please take you seat now.

श्री ईश्वर सिंह पलाका (रादौर, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज की मेन समस्या बिजली है, बिजली मेरे हल्के में सरकार के शिड्यूल के हिसाब से नहीं चल पाती । मेरे अपने हल्के में 33 KVA का सब-स्टेशन है जहां से बिजली सप्लाई होती है, वहां से दिन में 2 घण्टे मुश्किल से और रात को भी 2 घण्टे ही पावर मिल पाती है। इस बारे में अधिकारियों से हमने बात की तो अधिकारी यह कहकर किनारा कर जाते हैं कि इसकी व्यवस्था को ठीक करने में हम लगे हुए हैं। मेरे हल्के में गन्ने की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ऐसी गर्मी में गन्ने की फसल को हफ्ते में पानी न मिल पाए तो किसान की पैदावार घट जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिजली का जो शिडयूल है उससे भी ज्यादा बिजली हमारे हल्के में उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि कई लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, गांव में रहना पसन्द नहीं करते हैं इसका मेन कारण गांव में बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ठीक न होना है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जैसी व्यवस्था शहरों में मिलती है वैसी सुविधाएं गांव में भी उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था भी गांव में ठीक तरह से नहीं मिल रही है, कई गांवों की डिस्पैंसरीज में एक डाक्टर और एक नर्स एक घण्टा बैठकर चले जाते हैं और वह भी हफ्ते में दो दिन जाते हैं। इसलिए जो गांवों में डिस्पैंसरियां बनी हुई हैं उनमें रैगुलर डाक्टरों या नर्सों का प्रबन्ध किया जाये ताकि गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है पिछली सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए बेरोजगारी भत्ता तय किया हुआ था जो इस सरकार ने बंद कर दिया है। इस बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि बेरोजगारी भत्ते को मौजूदा सरकार तर्कसंगत बनायेगी। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बेरोजगारों के लिए भत्ता सुविधा जल्दी से जल्दी शुरू की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी है कि रादौर हल्के के साथ यमुना नदी लगती है और बरसात के दिनों में जब यमुना में ज्यादा पानी आता है तो वहां भूमि कटाव की वजह से किसानों की लाखों रुपये की फसल बरबाद हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यमुना के साथ-साथ पटरी बनाकर पत्थर लगाये जायें ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके और किसानों की जो फसल हर साल नष्ट हो जाती है उससे किसानों को बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, रादौर हल्के में होस्पिटल की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसमें डाक्टरों की कमी है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उसमें डाक्टरों की कमी को पूरा किया जाये ताकि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। अंत में स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री दिल्लूराम (गुहला, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बजट के बारे में मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हरियाणा की जनता को जो बजट दिया है वह बजट गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए यानि हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतरीन बजट है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की कुछ मांगें हैं वे मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। कि मेरा हल्का 100-125 कि०मी० तक पंजाब के एरिया के साथ लगता है और इसी कारण वहां के किसान के साथ हर साल ज्यादती होती है। पंजाब के लोग क्या करते हैं कि पटियाला शहर को बरसात के दिनों में बाढ़ से बचाने के लिए रोपड़ शहर का पानी एस०वाई०एल० नहर के थू शंभू के पास उसको तोड़कर घग्गर में डाल देते हैं ।

जिसके कारण 5-6 दर्जन गांव गुहला हल्के में ऐसे हैं जिनके किसानों की फसल को भारी नुक्सान हर साल होता है। वहां का किसान इस साल भी चिंतित है कि हर साल की तरह इस बार भी उनकी फसल का नुक्सान होगा। गुहला हल्के के पास से घग्गर, टांगरी, भारकण्डा और पटियाला ये चार नदियां निकलती हैं। बरसात के दिनों में इन सभी नदियों का पानी घग्गर नदी में ही आ जाता है। यदि घग्गर नदी में 22-23 फिट तक पानी रहता है तो पानी नदी से बाहर नहीं आता लेकिन बरसात के दिनों में इसमें 22-23 फिट से ज्यादा पानी चलता है जिसके कारण वहां के किसानों के खेतों में पानी चला जाता है और जिससे उनकी फसल को भारी नुक्सान पहुंचता है। इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वे पंजाब सरकार से बात करें कि वे अपना फालतू पानी हमारी तरफ क्यों छोड़ते हैं अपने पास ही क्यों नहीं रखते। एस०वाई०एल० कैनाल के पानी की मांग हम कर रहे हैं वह तो हमें देते नहीं हैं और बरसात के दिनों में फालतू पानी हमें बाढ़ में डूबोने के लिए छोड़ देते हैं। इस बारे में पंजाब सरकार से मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए ताकि हमारे एरिया के किसानों की फसल नष्ट न हो। जिन पांच-छः दर्जन गांवों की फसल नष्ट होती है उनमें लड़को के रिश्ते भी नहीं होते क्योंकि वहां पर अपनी लड़की का रिश्ता करने कोई आता ही नहीं है और किसी से बात करते हैं तो कह देते हैं लड़की को क्या खिलावोगे आपकी फसल तो हर साल नष्ट हो जाती है अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कहते हैं कि वहां पर एक नहर खुदने वाली है वह समाना से लेकर पुण्डरी होकर आगे जाएगी। हमें कुछ ऐसा पता लगा है कि उस नहर का पानी का स्तर 2 हजार क्यूसिक है और हमें यह भी पता लगा है कि मेरे हल्के में उस नहर से कोई पानी नहीं दिया जाएगा। स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि यहां से 12-13 ड्रेनें निकलती हैं। उस नहर की चौड़ाई एकड़ की होगी इसलिए इस नहर से हमें भी पानी दिया जाए क्योंकि हमारा वह एरिया पैडी का एरिया है। इससे काफी किसानों को फायदा होगा। स्पीकर सर, पैडी के एरिया में कम से कम 4-5 महीने काफी पानी की जरूरत पड़ती है। स्पीकर साहब, आपका एरिया भी ऐसा ही पैडी का एरिया है और मेरी तथा आपकी हालत एक ही जैसी है। स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नई नहर निकलेगी उसका बैनिफिट मेरे तथा आपके हल्के के जो किसान हैं उन दोनों को मिलना चाहिए ताकि वे सारे लोग जिन की जमीन का हिस्सा इस नहर में जाएगा उन सब को पानी का हिस्सा मिलेगा तो कम से कम उनको कुछ शान्ति तो मिल जाएगी। स्पीकर सर, इसी तरह से पिछली सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो भी गांव अपनी सड़क पर मिट्टी डालेंगे उनकी सड़कें विभाग पक्की करेगा। उन लोगों ने किसानों से 400-500 रुपये प्रति किसान इकट्ठा करके वहां पर कम से कम 10 सड़कें ऐसी हैं जिन पर मिट्टी डाली है और अर्थ वर्क कर दिया है लेकिन उसके बाद उस सरकार ने उन सड़कों पर एक भी रोड़ा नहीं डाला। स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार उसके बारे में गौर करके किसानों ने जो मिट्टी डाली है उस पर सड़क बनवाए है। बरसात आने वाली है और अगर सड़क नहीं बनी तो वह मिट्टी बह जाएगी और जो कार्य हमारे लोगों ने कर रखा है उनका वह पैसा बेजा चला जाएगा। स्पीकर सर, इसी तरह से मैं आपके द्वारा सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा एरिया पैडी का एरिया है और लोग सबमर्सिबल ट्यूबवैल लगाते हैं। उन लोगों की यह मजबूरी है इसलिए वे सबमर्सिबल ट्यूबवैल लगाएंगे ही। सबमर्सिबल ट्यूबवैल लगाने के लिए डेढ़ लाख से दो लाख रुपये का खर्च आता है। सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि जो किसान सबमर्सिबल ट्यूबवैल लगवाए और जनरेटर सैट लगाए उसको कम से कम 50% सबसिडी देनी चाहिए ताकि कम से कम उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए। स्पीकर

[श्री दिल्लूराम]

सर, इसके साथ ही मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना और है। किसान 24 घण्टे खतरे से खेलते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार हो कर उनकी मौत भी हो जाती है। दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत सरकार ने किसी किसान के खेती के कार्य में दुर्घटना के कारण मौत हो जाने पर पहले 30 हजार रुपये देने का प्रावधान किया हुआ था जिसे कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया था। दुर्घटना में मौत होने पर पचास हजार रुपये की राशि काफी कम है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि यह राशि कम से कम एक लाख रुपये तो होनी चाहिए। कई केसिज ऐसे होते हैं जिनमें घर में कमाने वाला एक ही मेम्बर होता है जो कि खेत में काम करता है। अगर किसी वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है। और उस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पचास हजार रुपये मिलते हैं उसके परिवार को कम से कम एक लाख रुपये जरूर मिलने चाहिए ताकि किसान के दुर्घटना में गुजर जाने के बाद उसके परिवार का गुजारा हो सके। स्पीकर साहब, यह समस्या मेरी अकेले की समस्या नहीं है, यह सारे हरियाणा प्रदेश की समस्या है। मैंने एक दो परिवार ऐसे देखें हैं जिनकी बच्चियां जवान होती हैं और वह आदमी मौत का शिकार हो जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार की बहुत दुर्दशा होती है। ऐसे केस में एक लाख रुपये की राशि देने में कोई हर्ज नहीं है। यह पैसा मार्कीटिंग बोर्ड ने देना है। जब जमींदार अपना सारा अनाज वहां मण्डी में देता है और मार्कीटिंग बोर्ड को इतना टैक्स देता है तो मार्कीटिंग बोर्ड को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर, इसी तरह से मेरा एरिया पैडी का एरिया है और वहां पर बिजली की सप्लाई का कोई क्राईटीरिया नहीं है। बिजली दिन में आएगी या रात में आएगी इसका कोई पता नहीं होता। सारी-सारी रात किसान बिजली की इन्तजार में जागते रहते हैं। ट्रिपिंग हद से ज्यादा होती है। कांग्रेस की इस सरकार से हमें उम्मीदें है कि इस बार स्थिति में सुधार होगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमन्त्री जी बहुत ही भले आदमी हैं और लोगों ने उन से बहुत ज्यादा आशाएं लगा रखी हैं। हमारे यह भाई जो इधर बैठे हुए हैं इन लोगों ने इलैक्शन के दिनों में जनता में अफवाह फैला रखी थी कि अगर कांग्रेस की गवर्नमैंट आई तो वृद्धों की पैंशन बन्द हो जाएगी, लोगों के पीले कार्ड बन्द हो जाएंगे। इन लोगों ने इतनी अफवाह उड़ा रखी थी कि बूढ़े आदमी कांग्रेस को वोट देते हुए डरते थे। स्पीकर साहब, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बूढ़े लोगों की कौन सी पैंशन बन्द हो गई ? स्पीकर सर, पीले कार्ड की जो समस्या है वह भी इन्हीं लोगों की पैदा की हुई थी। हमारे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती होती थी। हरिजन या चाहे कोई भी गरीब आदमी थे या बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनको कहते थे कि ये कांग्रेसी हैं इनको पैंशन नहीं देनी चाहिए, इनको पैंशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। उनकी पैंशन बिल्कुल नहीं बनी और इनेलो के लोग हरे साफे बांधकर पैंशन लेने जाते हैं और लोगों ने उस पैंशन का नाम ताऊ देवी लाल पैंशन रख दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि जिन गरीब आदमियों को पैंशन मिलनी चाहिए उनको उनकी पैंशन इशू करने का काम करें। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं नाउम्मीद ही हो चुका था कि पता नहीं मुझे बोलने का समय मिलेगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार हरियाणा की प्रगति के लिए काम रही है। इन्होंने हरियाणा में 36 बिरादरी के लिए जिसमें गरीब आदमी, मजदूर, किसान, कर्मचारी और अधिकारी आते हैं सभी

के हितों के लिए काम किया है। अध्यक्ष महोदय, जब से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमारे इलाके में कामों को करने की बहार सी लगी हुई है और हमें किसी भी काम के बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हमारा हल्का हुड्डा जी के एरिया में ही आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की कुछ बातें आपके माध्यम से सदन के नेता जी से कहना चाहूंगा कि बादली और झज्जर में एक बाई पास बनना विचाराधीन है। उस बारे में सरकार से निवेदन है कि उस पर जल्दी से जल्दी काम करवाने का प्रबन्ध करें। अध्यक्ष महोदय, बादली और झज्जर दिल्ली से सटा हुआ हल्का है। इसको इन्डस्ट्री के लिए बैकवर्ड घोषित किया जाए। दिल्ली से लगते सभी एरियाज डिवैल्प हो गए हैं लेकिन हमारा एरिया अभी भी पिछड़ा हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यहां पर इन्डस्ट्रीज लगाने के बारे में भी कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय, बादली और झज्जर के कुछ गांवों में अभी तक टेलों में पानी नहीं पहुंचा है।वहां पर जो नहरें हैं वह अटी पड़ी हैं या कोई दूसरी छोटी-मोटी प्रोब्लमज़ हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन मुश्किलों को दूर करके वहां पर टेलों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जो ड्रेन नम्बर पांच है उसमें पानी डालने का काम किया जाए। अगर सरकार ऐसा कर देगी तो वहां के 10-12 गांवों को फायदा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बादली हल्का पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकार के वक्त में यहां पर 10-12 पत्थर लगा दिए गए थे लेकिन उन पर कोई काम शुरू नहीं करवाया गया था और आज भी वे पत्थर वैसे ही हैं। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ उन पत्थरों पर पेशाब कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी फोटो भी लाकर दिखा सकता हूं। पिछली सरकार के वक्त में वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर काम शुरू करवाया जाए। मैं यह जो बात कह रहा हूं इससे मेरे जो साथी पिछली सरकार के बैठे हुए हैं उनको तकलीफ़ हो रही होगी। पिछली सरकार के वक्त में नहरों में पानी नहीं था, बिजली नहीं थीं, दूसरी जो लोगों की सुविधाओं के काम होने थे वे कोई काम नहीं हुए थे उस वक्त हमारे वहां पर इनकी पार्टी का एम०एल०ए० होता था जब हम उनसे पूछते थे। कि आपकी सरकार है आप ये काम क्यों नहीं करवाते तो वे कहते थे कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी चलती नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) लोग तो यह कहने लग गए थे कि इनैलो की सरकार एक बाप और दो बेटे चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें वहां के लोग कहने लग गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेखा राणा : स्पीकर सर, मेरा आपसे यह कहना है कि इन्होंने जो अपशब्द हमारी पार्टी के नेता के बारे में कहे हैं यह कार्यवाही से निकलवाए जाएं। सदन में बार-बार उनके बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहन जी आप बैठिए, ये अब ऐसा नहीं कहेंगे। नरेश कुमार जी आप अपनी स्पीच दें। ऐसी बातें नहीं कहें। अगर आप अब ऐसा कहेंगे तो मैं दूसरे मैम्बर को बोलने के लिए कह दूंगा।

श्री नरेश कुमार : स्पीकर सर, ऐसा वहां के लोग कहने लग गए थे। यहां पर लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई बोलता था तो उनका मुंह तोड़ दिया जाता था, हाथ-पैर तोड़ दिए जाते थे और वे दो-दो तीन-तीन महीने तक ठीक नहीं हो पाते थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please wind up your speech Mr. Naresh Ji. (Interruptions) Thank you, Naresh Ji please take your seat. Next Member, Shri Sher Singh.

श्री नरेश कुमार : ठीक है स्पीकर सर, मैं अपनी सीट पर बैठता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आई०जी० शेर सिंह (जुलाना) : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि मैं पिछली दफा भी हाउस का सदस्य था और मैंने देखा था कि किस प्रकार का माहौल यहां पर बनाया गया था। उस समय पूरे हरियाणा में अव्यवस्था का माहौल था। स्पीकर साहब हम सामाजिक प्राणी हैं। हम व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार बधाई की पात्र है। सभी कांग्रेसजन, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी सभी बधाई के पात्र है। सभी साथियों ने व्यवस्था को कायम करने के लिए एक युद्ध किया था और उस युद्ध में हम कामयाब हुए हैं। यह हरियाणा की एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि कोई भी चीज व्यवस्था में ही हो सकती है। लेकिन पिछली सरकार ने एक ही काम किया था उसने उस सिस्टम को ध्वन्स किया था। स्पीकर साहब, अभी मैं सदन में दो चार बातें कहना चाहता हूं। मेरा हल्का ग्रामीण बहुल्य हल्का है। गांवों में गरीब लोग और किसान रहते हैं इसलिए गांवों में लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। न ही गांवों में स्कूल हैं और अगर स्कूल हैं भी तो उन स्कूलों का स्तर ठीक नहीं है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां के नौजवान साथी एक ही दिशा की तरफ देखते हैं। उनकी दिशा पुलिस या फौज की भर्ती की तरफ होती है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के समय में भर्ती के समय में जब कोई भी आदमी, किसान या मजदूर का बच्चा फौज में भर्ती होने के लिए या स्टेट पुलिस में भर्ती के लिए जाता था तो वह निराश होकर लौट आता था। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने एक ऐसा काम स्टेट की पुलिस की भर्ती में किया था जो ब्रिटिश टाईम में भी नहीं किया गया था। पिछली सरकार ने भर्ती में हरियाणा के निवासियों की हाईट 5 फुट 7 इंच से बढ़ाकर 5 फुट 9 इंच कर दी थी। जबकि यह सभी को पता है कि प्रपोशनेट हाईट में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि यह घटी ही है। गरीब का बच्चा ही पुलिस की भर्ती के लिए जाता है, थर्ड क्लास या सैकेंड क्लास डिवीजन लाने वाले बच्चे ही इस दिशा में जाते हैं। इसको देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा और सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि सरकार को पुरानी व्यवस्था को ही कायम रखना चाहिए और भर्ती में 5 फुट 7 इंच हाईट ही रखनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को पुलिस की भर्ती में अपनी किस्मत अजमाने का मौका मिले। इस हाईट को कम किया जाना चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार ने और व्यवाहारिक कदम उठाए हैं तो उसी तरह से यदि सरकार यह हाईट भी कम कर दे तो बेहतर रहेगा। जिस तरह का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है वह बहुत ही अच्छी बात है और जिस तरह आज 1600 करोड़ रुपये के इलैक्ट्रिसिटी बिल माफ किए गए हैं वह एक बोल्ड डिसीजन है। You can call it a bold and commendable decision. अध्यक्ष महोदय, जिनकी हाईट कम थी उनको पुलिस की भर्ती में अपनी किस्मत अजमाने का मौका नहीं मिल पाता था। जिस प्रकार से पानी के बंटवारे में पिछली सरकार ने भेदभाव किया था उसी तरह से उनका यह हाईट बढ़ाने के पीछे नजरिया एक क्षेत्र विशेष के लोगों जहां पर नौजवानों की हाईट ज्यादा पायी जाती है, को फायदा पहुंचाना था । सरकार एक पर्टीकुलर एरिया के लोगों को नौकरी देना चाहती थी इसलिए उसने पांच फुट 6 इंच के बजाय 5 फुट 9 इंच हाईट की थी। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इस हाईट को 5 फुट 7 इंच ही किया जाएगा तो बेहतर

होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा जुलाना हल्का जींद और रोहतक के बीच में पड़ता है वैसे तो जींद भी पिछड़ा हुआ एरिया है लेकिन जुलाना हल्का जींद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ा हुआ है। वहां जमीन तो है लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जो लोग गांव में रहते हैं चाहे जमीन वाले हैं या जमीन से संबंधित मजदूर हैं वे सब खेती पर निर्भर करते हैं। मेरे क्षेत्र की जमीन पर नीचे से पानी नहीं मिलता, केवल जब भगवान बरसता है तब थोड़ा पानी मिल जाता है। हमारे एरिया से सुंदर ब्रांच जाती है जब से सरकार आई है, पानी 21 दिन आना शुरू हुआ है। मेरी सरकार से एक ही विनती है कि जब सुन्दर ब्रांच में पानी चलता है तो 8 दिन पानी दिया जाता है और उन 7-8 दिनों में रजबाहों में पानी रोका जाता है वहां के लोगों की आम शिकायत है कि पानी क्यों रोका जाता है मेरी भी समझ में नहीं आता है कि पानी क्यों रोका जाता है मैं निवेदन करूंगा कि रजबाहों में भी पानी उतना ही चलना चाहिए ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। पिछली सरकार के समय में एक रामकली माईनर बनाई गई थी उससे लोगों को बहुत उम्मीद थी कि किसानों को पानी मिलेगा लेकिन अगर उस माइनर को कोई देखे, इरीगेशन के अधिकारी उसको देखें तो पाएंगे कि उसके अंदर इतने बट हैं, इतने मोड़ हैं कि शायद सांप भी बैठे तो उसके कम बट मिलेंगे। मेरा कहने का भाव यह है कि पानी के मामले में भेदभाव है।

Mr. Speaker : Please conclude your speech only three minutes are left.

I.G. Shri Sher Singh : Sir, I will finish within time. अब मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे यहां एक भी कालेज नहीं । आगे से आगे शिक्षा का आधार बढ़ा रहे हैं अगर कालेज नहीं खोला गया तो उसमें हमारे यहां के लोगों की बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं रहेगी। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसलिए वे लोग अपने बच्चों को रोहतक या जींद नहीं भेज पाएंगे इससे होनहार लड़के लड़कियों का भविष्य वहीं पर रह जाएगा। कालेज के लिए जमीन चाहे 20 एकड़ कहें तो 20 एकड़ 30 एकड़ कहें तो 30 एकड़ देने को तैयार हैं मेरी सरकार से पुन: मांग है कि जुलाना में एक कालेज अवश्य खोला जाए। जुलाना एक मंडी है वहां पहले म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी पिछली सरकार ने उसे तोड़ दिया, अब उसको बहाल करना विधाराधीन है। अगर म्युनिसिपल कमेटी बहाल हो जाती है तो काफी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मेरे एरिया में एक ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए तकरीबन 98 लाख रुपये की स्कीम तैयार हुई थी उसमें से 22-23 लाख रुपया सीवरेज पर खर्च किया गया है। स्पीकर सर, हरियाणा विकास पार्टी के शासनकाल में यह कार्य शुरू हुआ था मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस स्कीम को दोबारा से शुरू किया जाए और उस सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए। मेरे हल्के में जो मंडी है वह छोटी सी जगह पर है उसे बाहर जगह दी जाए तो बेहतर होगा। स्पीकर सर, अब मैं पानी के बारे में बात कहना चाहूंगा। कई जगह पानी की टंकियां हैं वह खुली हैं और कैनाल से बाहर जो पानी जाता है वह खुली नालियों में जाता है उसके अंदर हाथ और कपड़े भी धोये जाते हैं मैं निवेदन करूंगा कि जितनी नाली हैं और टंकियां हैं, वे कवर्ड होनी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब आप बैठिए, अब श्री नरेश मलिक जी बोलेंगे।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बजट की डिमांड पर बोलना चाहता

[श्री नरेश मलिक]

था लेकिन मुझे उस वक्त टाइम नहीं मिला। अब आपने मुझे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट पर भी मुझे बोलने का समय नहीं मिल पाया था। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि किसान आज एक घाटे का सौदा बनकर रह गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अधिकतर साथी किसान के बेटे है। वित्त मंत्री जी ने सबसे बड़ी बात कही है कि मेरे अन्दर भी एक किसान का खून है क्योंकि वे सर छोटूराम जी के नाती हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि बजट में सब कुछ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी कैसे चूक गये। पिछले सैशन में भी मैंने यह बात कही थी कि सर छोटूराम आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने में जिन्होंने पूरे प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया था। हमने एक छोटी सी मांग रखी थी जिस तरह महम में चौबीसी का चबूतरा है उसी की तर्ज पर मेरे हल्के के गांव इस्माईला में एक छोटा सा चबूतरा बनवाया जाये क्योंकि हमने सर छोटूराम जी की मूर्ति स्थापित करनी है। वहां बड़े बड़े नेता लोग आते रहते हैं इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री करने के लिए कैसे चूक गये, यह मेरी समझ से बाहर है। मैं यह काम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं करवा रहा बल्कि उस महान आदमी के लिए करवा रहा हूं जिसको प्रदेश की 36 बिरादरी आज भी पूजती है। पाकिस्तान में जाकर देखों वहां पर लोग उनके फोटो की आज भी पूजा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने सर छोटू राम के बारे में बहुत बड़ा ड्रामा किया था।

श्री अध्यक्ष : आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिए। This is not a part of the Appropriation Bill.

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने वहां पर बड़ा ड्रामा किया कि वे सर, छोटूराम की टेबल लेकर आये हैं, कुर्सी लेकर आये हैं। पिछली सरकार ने सांपला में सिर्फ वोट मांगने के लिए एक स्मारक बनाया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर । जिस तरह से माननीय मलिक साहब ने चौधरी ओमप्रकाश धौटाला का नाम लिया।

Mr. Speaker : What is your point of order.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूं। (Interruptions)

Mr. Speaker : Speech is not a point of order. Please sit down.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह सदन को गलत सूचना दे रहे हैं मैं उसको ठीक कर रहा हूं।

Mr. Speaker : You cannot speak at this stage. We are governed by the rules. Please sit down.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

Mr. Speaker : Naresh Kumar Ji, Please go ahead.

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी को शायद तकलीफ हो रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में चौधरी देवीलाल ने सर छोटूराम को काले झण्डे दिखाये थे और

उनको छोटे खां कहा था। मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को कि वे उस पर जरूर ध्यान दें और उचित कार्यवाही करें। मैंने एक रैजोल्यूशन दिया था लेकिन आपने रूल्ज के तहत उसे डिसअलाउ कर दिया। मेरे सारे साथी बैठे हैं, आज एक बहुत बड़ी किसान के सामने समस्या जो है, वह है कि पैस्टीसाइड्स और यूरिया जमीन में डाल-डाल कर जमीन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्पीकर साहब, अब मैं जैविक खाद के बारे में कहना चाहूंगा कि आज किसानों ने ज्यादा पैदावार लेने के लिए जमीन में पैस्टीसाइड और यूरिया खाद डाल-डाल कर जमीन की अन्न पैदा करने की ताकत बहुत ही कम कर दी है। आज हालत यह है कि अगर किसान जमीन में पैस्टीसाइड और यूरिया खाद नहीं डालते हैं तो पैदावार नहीं होती है, अगर पूरे प्रदेश में सोयल टैस्ट करवाया जाए तो इस बात का पता चल जाएगा। अगर कल को धरती अन्न की पैदावार बंद कर देगी तो हमारी क्या हालत होगी। मैं तो यह कहूंगा कि किसानों को जमीन में जैविक खाद डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्पीकर साहब, कुछ समय पहले पूरे देश में हरित क्रांति नाम से एक लहर चली थी उसका किसानों पर काफी असर हुआ था। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो दुनिया भर की गिद्ध और चील देखते थे लेकिन आज गिद्ध नाम की चीज नहीं है क्योंकि यह सारा कारनामा पैस्टीसाइड और यूरिया का है। कल वित्त मंत्री जी ने बताया था कि अनाज की ग्रोथ रुक चुकी है। जितनी पैदावार किसान को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। अनाज की पैदावार कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आज हम WTO के हिसाब से देखें तो कुछ समय पहले जब हम हिन्दुस्तान के किसान का गेहूं इरान और इराक भेजा गया था तो वह वापिस आ गया क्योंकि उसका कारण भी किसानों द्वारा गेहूं की पैदावार में यूरिया और पैस्टीसाइड डालना था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को किसानों को जमीन में जैविक खाद डालने के बारे में प्रेरित करना चाहिए। यदि सरकार जैविक खाद की तरफ ध्यान देगी तो इससे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सकता है क्योंकि जैविक खाद के लिए इंडस्ट्रीज विकसित हो सकती हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यह बहुत बड़ा रोजगार इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो सकता है। आज भी जैविक खाद अगर हम डालें तो 5 साल पीछे से आज तक जो यूरिया और पैस्टीसाइड्स डालते आने का असर था वह नहीं जा सकता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्योंकि 5 साल तक किसान रुक तो नहीं सकता लेकिन ग्राम पंचायतों की जमीनें जहां पड़ी है वहां आहिस्ता-आहिस्ता इस जैविक खाद को डालना सरकार शुरू कर सकती है, इससे बदलाव लाया जा सकता है। मेरे साथी कहेंगे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले का हूं, हमारे यहां कहावत है कि अच्छा हो गया तो भाग मेरी के और भुंडा हो गया तो मरियो पूत बिचोलिये के। अच्छे करेंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरे हल्के के हैं, अच्छे नहीं करेंगे तो झेलना तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पड़ेगा। पिछली सरकार में केवल वोट लेने के लिए सांपला में एक तहसील का पत्थर लगा दिया गया था। अभी मेरे साथी नरेश जी ने बताया, वह लैंग्वेज तो मैं यूज नहीं करूंगा। एक पत्थर तहसील के लिए लगा था और एक थाने के लिए लगा था और एक ITI के लिए लगा दिया था। लेकिन सांपला में जो ये पत्थर लगाए गए इनके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन चौटाला जी गए और जाकर 4 पत्थर गाड़ आए। मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी, मैंने निवेदन किया था कि पिछली सरकार ने सांपला में चौधरी छोटू राम स्मारक बनाया था, उसका काम कुछ अधूरा रह रहा है, पूरा सदन छोटू राम जी को मान देता है। चौटाला जी ने राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये पत्थर रखे थे। (शोर एवं व्यवधान) हमने 20 साल मेहनत की है, हमारा जिला रोहतक मुख्यमंत्री का गृह जिला है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम है ये वहां से विधायक हैं, मुझे मालूम है, मैं वहां से 4 बार सांसद चुन कर आ चुका हूं, मेरी कंस्टीच्यूंसी रह चुकी है, चौ० छोटू राम का मान-सम्मान कोई हरियाणा के लोग ही नहीं करते बल्कि उनका मान-सम्मान पुरे हिन्दुस्तान में है। (विघ्न)

श्री नरेश मलिक : मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा है कि पाकिस्तान में भी उनका आदर है। मुझे खुशी है कि हसनगढ़ ने पिछली बार आपको 22 हजार मतों से विजयी बनाया। स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे पाकिसमा गांव में गए थे, आपने स्वयं लोगों को कहा था कि पाकिसमा माइनर की समस्या हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। उस पर काम चल रहा है, लैवलिंग करके उसको एक फुट उंचा उठा रहे हैं लेकिन मैं दो स्कीमें मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 1999 में जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय इशू आया था, हसनगढ़ में कुछ लोग भालोट माइनर से पानी चाहते थे और कुछ लोग आसढ माइनर से पानी चाहते थे,यह तय हुआ था कि जो पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता उसके बारे में इन्जीनियर तय कर देंगे कि यहां से बनाया जाना चाहिए, वही ठीक होगा और इन्जीनियर्स ने यह तय किया था कि भालोट डिस्ट्रीब्यूट्री से पाकिसमा माईनर बनाया जायेगा। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि पाकिसमा माईनर को भालोट डिस्ट्रीब्यूट्री जीरो से लेकर 25900 बुर्जी तक बनवाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक जी, अब आप बैठें। अब श्री रमेश कौशिक जी बोलेंगे।

श्री रमेश कौशिक (राई) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ-साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और वित्तमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक संतुलित और हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला बजट पहली बार हरियाणा की जनता को दिया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से चर्चा करना चाहूंगा। इण्डस्ट्री की समस्या हमारे हल्के में सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी। हमारी सरकार ने इण्डस्ट्री के बारे में इण्डस्ट्रियल पोलिसी बनाई है, बहुत अच्छी बात है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश से इंडस्ट्रीज पलायन कर रही थी। इसी तरह से दिल्ली से जो 14 हजार इण्डस्ट्रीज बाहर निकाली गई थी वे हरियाणा में लग सकती थी लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण उनमें से हरियाणा में एक भी इण्डस्ट्री नहीं लगी क्योंकि हरियाणा में जो इण्डस्ट्री लगी हुई थी वे भी पलायन कर रही थी। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सभी सदस्य भी जानते हैं कि प्रदेश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रदेश में इंडस्ट्रीज पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सरकार के खाते में सबसे ज्यादा टैक्स इंडस्ट्रीज से ही आता है। पिछली चार योजनाओं से राई क्षेत्र से विरोधी पार्टी का सदस्य चुनाव जीतता रहा और वहां किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। वहां पर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वे भी बंद हो गई। पहले वाली सरकार के समय में वहां किसानों की जमीनें एक्वायर कर ली जाती थीं और उन्हें दो लाख रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जाता था लेकिन अब हमारी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मापदण्ड निर्धारित किए हैं। जिसके तहत वहां के किसानों को प्रति एकड़ 15 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण होने पर मिलेंगे। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्री के मामले में कुण्डली ऐसा क्षेत्र है जो फरीदाबाद और गुड़गांव का मुकाबला कर सकता

है, इसलिए वहां पूरी सुविधाएं दी जायें। इसके अतिरिक्त वहां पर बिजली की बहुत कमी है, वहां पावर कट बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए वहां पर सरकार को 132 के०वी० का नया सब स्टेशन बनवाना चाहिए। अब मैं लेबर के मिनिमम वेजिज की बात करना चाहूंगा कि उनको भी बढ़ाया जाये और कम से कम इतना जरूर किया जाये कि पति-पत्नी और दो बच्चे खाना खा सकें। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से और लेबर मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा कि लेबर की तनख्वाह हर महीने 4000 रुपये जरूर होनी चाहिए। जिस समय मैं लेबर मिनिस्टर था उस समय मैंने ही लेबर की तनख्वाह 1400 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये की थी। उसके बाद इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज महंगाई दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है इसलिए इस ओर सरकार ध्यान अवश्य दे। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने पिता के नाम पर मोतीलाल राई स्पोर्टस स्कूल बनवाया था। इस बारे में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाये और उसमें बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा बनी हुई हैं इसलिए उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाये । अध्यक्ष महोदय, अब मैं इरीगेशन की बात करना चाहूंगा । अब हमारे क्षेत्र में इरीगेशन के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है पहले तो यमुना साथ लगती थी जिसमें पानी चलता रहता था इस लिए जरुरत नहीं थी । ट्यूबवैल के लिए जमीन में पानी ऊपर था और सिंचाई हो जाती थी । लेकिन अब यमुना में वहां पानी नहीं चलता जिसके कारण वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है । इसलिए वहां पर जिन गांवों में पानी की समस्या है उनके लिए नये माईनर बनाये जायें और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाये। हमारे वहां पिछले कई सालों से बिलकुल पानी नहीं आ रहा था जब से मुख्यमंत्री महोदय ने पानी के समान बंटवारे का फैसला लिया है तब से पानी आने लगा है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं लेकिन वहां पर न होस्पिटल है, न आई०टी०आई० है, न वोकेशनल एजूकेशन सैंटर है। जहां इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं वहां एक वोकेशनल एजूकेशन सैंटर या आई०टी०आई० जरूर होनी चाहिए। जिस समय मैं लेबर मिनिस्टर था उस समय मेरे पास आई०टी०आई० विभाग भी था तब मैंने सोनीपत जिले में तीन आई०टी०आई० खोली थीं लेकिन बाद की सरकारों ने उन तीनों को वापिस ले लिया और इस तरह से हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता रहा। इसलिए वहां भी एक आई०टी०आई० या वोकेशनल एजूकेशन सैंटर अवश्य खोला जाये। जहां तक मैट्रो का सवाल है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि मैट्रो को कुण्डली तक मंजूर करवाया है और मैं चाहूंगा कि आने वाले दो-तीन साल में बजट में प्रोवीजन 13.00 बजे करके मैट्रो को सोनीपत तक बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर हरिजनों के लिए प्लॉटों के बारे में बहुत गम्भीर और बड़ी भारी समस्या है। सर, अब पंचायतों की जमीन तो बहुत कम ही बची है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिसमें जमीन ऐक्वायर करके प्लॉट काटे जाएं। सरकार अपने लैवल पर जमीन ऐक्वायर करे और जहां पर लाल डोरे के अन्दर जमीन नहीं है वहां पर लाल डोरे की सीमा को बढ़ाया जाए। लाल डोरे का बढाया जाना जरूरी है क्योंकि आज हर जगह पर आबादी बढ़ गई है। लेकिन लाल डोरा आज तक नहीं बढाया गया है। इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है कि इस लाल डोरे को जरूर बढ़ाया जाये। स्पीकर सर, अब मैं पब्लिक हैल्थ तथा पीने के पानी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में पानी का लैवल पहले काफी अच्छा था और ज्यादा गहरा नहीं था लेकिन आजकल वाटर लैवल ठीक नहीं है और पानी का लैवल बहुत नीचे जा चुका है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में भी उचित प्रबन्ध करने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

[श्री रमेश कौशिक]

हमारे मुरथल में एक मण्डी होनी चाहिए आज भी वहां पर तीन लाख क्विंटल गेहूं बोरियों में भर कर वहां पर बिकने के लिए आई है इससे पहले भी वहां पर काफी अनाज आता रहा है। लेकिन वहां पर मार्किटिंग कमेटी की मण्डी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर मार्किटिंग बोर्ड की मण्डी जरूर बनाई जानी चाहिए। स्पीकर सर, इसी तरह से इण्डस्ट्रीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो बजट रखा है उसमें नये प्लान में इण्डस्ट्रीज के लिए पैसा रखा है मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके को भी इस इंडस्ट्रीयल पॉलिसी का फायदा होना चाहिए। हमारे हरियाणा के अन्दर इस पॉलिसी को लागू करने के लिए हमें भी शामिल किया जाना चाहिए इससे हमारे इलाके के नौजवानों को भी नौकरियां मिल सकती हैं और इससे बेरोजगारी को खत्म करने के बारे में बहुत काम हो सकता है। इसके साथ ही हमारे इलाके में राई में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सैंटर बनना था लेकिन पिछली सरकार ने उस प्लान को बदल दिया था। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने भी इसे बनाने की घोषणा की थी इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्पोर्ट्स सैंटर जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द भक्कड़ (हांसी) : स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले मैं इस ऐतिसाहिक बजट को पेश करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने और आदरणीय मुख्यमन्त्री जी से सलाह करके जो बजट पेश किया है वह बजट बहुत ही काबिले तारीफ है और उसकी जितनी भी तारीफ करूं वह थोड़ी है। स्पीकर सर, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है इसलिए सबसे पहले मैं अपने हल्के की कई डिमाण्डज यहां पर रखना चाहता हूं। हांसी एक ऐतिहासिक शहर है। आप सभी जानते हैं कि वह शहीदों की धरती है। हांसी शहर के लोगों ने 1857 की क्रान्ति के समय क्रान्तिकारियों के साथ मिल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज जब दोबारा पावर में आ गए तो वहां के लोगों से बदला लेने के लिए वहां के नौजवानों को सड़क पर लिटा कर गिरड़ी फिरा दी थी जिससे वह सारी सड़क खून से लाल हो गई थी और आज भी उस सड़क का नाम लाल सड़क के नाम से मशहूर है। हांसी की धरती शहीदों की धरती है। पुट्ठी गांव, रौन्नाट गांव जहां के नौजवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था वहां के लोगों को दरख्तों के साथ लटका कर फांसी दी गई थी। उस गांव को अंग्रेज सरकार ने बेच दिया था आज भी वहां के किसान यह मांग करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जो जमीन थी जिसे अंग्रेजों ने बेच दिया था वह जमीन हमें वापिस दी जाए। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। सबसे पहले सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हांसी शहर एक ऐतिहासिक शहर है और सन् 1994-95 में शहरों के सौन्दर्यीकरण में हांसी का नाम भी दिया गया था। वही हांसी आज इस हालत में है कि वहां पर न सफाई है, न नाली है और न ही सड़क है। सभी चीजें टूटी-फूटी हालत में पड़ी हुई हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देने की मेहरबानी करे। मैं समझता हूं कि सरकार शहीदों की इस धरती का पूरा ध्यान रखेगी। यहां पर पार्क हैं जो कि शहीदों के नाम पर बने है। अंग्रेजों ने लाला हुक्म चन्द जैन को लोगों की भावनाओं को कुचलने के लिए दफनाया था और मिर्जा मुन्नीर बेग को जलाया था क्योंकि ये दोनों जंगे आजादी में लोगों के नेता थे। लोगों की भावनाओं को कुचलने के लिए जंगे आजादी के दोनों नेताओं के साथ उल्टा काम किया था। इनके नाम पर वहां पर पार्क बने हुए हैं। डण्डल में पार्क की बहुत

ही बुरी हालत कर दी गई है और उसका नाम भी नहीं दिखता है। मेरी यह धारणा है कि जितने भी पार्क हैं उनको सुन्दर बनाया जाए। यह मेरी मांग है कि वहां पर जितने भी पार्क हैं वे सभी शहर की सुन्दरता को एक रूप देते हैं, उनको सुन्दर बनाया जाना चाहिए। मुल्तान कॉलोनी में पार्क है, शहीद भगत सिंह के नाम पर पार्क है और शहीद सुखदेव के नाम पर पार्क है। स्पीकर सर, सारे पार्कों के नाम मैंने ही शहीदों के नाम पर रखवाए थे। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इन पार्कों को सुधारने के लिए इन्हें सुन्दर बनाने के लिए कमेटी को कोई फण्ड्ज़ ऐलोकेट करें ताकि हम इन पार्कों को सुधार सकें। इसके साथ ही साथ मेरे यहां पर और भी कई समस्याएं हैं जैसे कि पीने के पानी की समस्या है। पानी के बारे में मैंने एक अलग क्वैश्चन भी दिया था जिसका जवाब हमारे माननीय इरीगेशन मन्त्री जी ने दिया था। वहां पर आज ऐसी हालत है कि सारा शहर सूखा पड़ा है। दूसरे वाटर वर्क्स की स्कीम भेजी हुई है ताकि शहर को पूरा पानी मिल सके। शायद वह स्कीम भी सरकार के पास आई हुई है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उस स्कीम को जल्दी से पूरा करके उसको चालू करवाया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। आज शहर में पीने का पानी गन्दा मिलता है और लोग उस गन्दे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि साफ पानी बिल्कुल नहीं आता है। हमारे यहां पर पीने के पानी की कमी है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि पीने का पानी सबसे बड़ी जरूरत होती है इसलिए सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। अभी तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, उसकी वजह से कई कई दिनों तक लोग प्यासे रहते हैं और खेत सूख रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग पीछे से ही पाईप लगा लेते हैं और चोरी चोड़ी कर देते हैं। जिस कारण आगे पानी नहीं आ पाता है। इरीगेशन वाले भी मजबूर हैं, यह ठीक है कि वे चालान कर देते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ऐसी फोर्स बनाएं ताकि जो चोरी करने वाला है, उसके बारे में चैक करे। इस बारे में चैक करने की जरूरत है, अगर चैक रहेगा तो उस वजह से सभी को बराबर पानी मिलेगा। इसके साथ ही स्पीकर सर, मैं सड़कों के बारे में भी कहना चाहता हूं। हांसी में बहुत सी सड़के ऐसी हैं जिनका बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ये सड़कें गढ़ी से मेहदा, चोरखी से सीसर, गढ़ी से बटोना, जटान, हांसी से उमरा सुल्तानपुरा सड़कें है जिनकी हालत बहुत ही खराब है। इसके साथ ही हांसी से ढाणी कुतुबपुर और खरड़ तक की सड़क जो छत्तरपाल जी के हल्के से लगती हुई है इसकी भी बहुत ही बुरी हालत है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से प्रार्थना है कि उन सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा एजूकेशन मिनिस्टर महोदय, से निवेदन है कि हमारे हल्के में कई लड़कियों के स्कूल ऐसे हैं जिनको 10+2 करने की जरूरत है। हमारे यहां पर ढाना गांव है जहां पर स्कूल के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन वह स्कूल 10+2 नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में सहाय गांव में जो कि छत्तरपाल जी का हल्का है वहां पर 10+2 स्कूल पहले ही से था उसी को 10+2 स्कूल का दोबारा से दर्जा दिया गया था तो मेरा कहना है कि उसको बदल कर ढाने गांव के स्कूल को 10+2 स्कूल कर दिया जाए। इसके साथ ही स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि गढ़ी गांव में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें भी लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी और एजूकेशन मंत्री जी सदन में आश्वासन दें।

स्पीकर सर, अब मैं इन्डस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। इंडस्ट्री से स्टेट की आमदनी होती है और हमारे बच्चों को उसमें रोजगार मिलता है। पिछली सरकार के वक्त में इंडस्ट्री के

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

लिए कुछ नहीं किया गया है। उनकी दादागिरी की वजह से, उनके द्वारा इन्डस्टरी वालों से 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ की मांग करने की वजह से कई बड़ी-बड़ी और अच्छी अच्छी फैक्टरीज हमारे यहां से बंद होकर दूसरी जगहों पर चली गई हैं। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन हैं कि सरकार उद्योगों के लिए कोई ऐसी अच्छी नीति बनाए ताकि बड़े उद्योग हरियाणा में आकर लगें। अध्यक्ष महोदय, हांसी में एक स्पीनिंग मिल थी और वहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, उस मिल में जो धागा बनता था वह सारे हिन्दुस्तान में सप्लाई होता था और वह धागा बहुत ही मशहूर था। पिछली सरकार ने उस फैक्टरी को बंद कर दिया है और वहां पर काम करने वाले हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज वे लोग सड़कों पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, उस फैक्टरी को दोबारा से शुरू करने के बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ साहब आप वाईंड-अप करें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हांसी में दूसरे उद्योग भी लगाए जाएं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। स्पीकर सर, हांसी में कपास बहुत होता है और वहां पर एक कपड़े की फैक्टरी थी, वह भी बंद हो गई है। उसको भी दोबारा से शुरू करवाने का प्रबन्ध किया जाए। अगर ऐसा होगा तो जो लोगों का कपास है, उसकी खपत हो जाएगी और उससे वहां के किसानों को बहुत फायदा होगा तथा बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद मक्कड़ साहब। श्री परमवीर सिंह जी बोलें

सरदार परमवीर सिंह (टोहाना) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी को और वित्तमंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और इनको बधाई भी देना चाहूंगा कि आज इन्होंने किसानों के लिए एक हिस्टोरिक डिसिजन लिया है। इस डिसिजन में किसानों के उपर जो बिजली के बिलों का बोझ था उसको कम करने का काम किया गया है। स्पीकर सर, पिछली सरकार के गलत वायदों की वजह से किसानों के कंधों पर जो बोझ आ गया था उस बोझ को हटाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं मुबारिकबाद देना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इतना स्पीडी रिलीफ किसानों को पहुंचाया। अभी पिछले दिनों फतेहाबाद और सिरसा जिले में नैचुरल क्लैमिटी आयी थी लेकिन दो दिन के अंदर ही सी०एम०साहब ने लोगों को कम्पनसेशन चैक्स दे दिए। कहने का मतलब यह है कि इस सरकार ने बड़ी तेजी से काम किए हैं। इसी तरह से शगुन स्कीम के तहत 5100 रुपये की राशि को बढ़ाकर 15000 रुपये किया गया है। सरकार ने हरियाणा को क्राइम एवं क्रप्शन फ्री स्टेट बनाने के लिए स्टैप्स लिए हैं। इतने कम समय में सारे स्टैप्स तो नहीं लिए जा सकते लेकिन इन सौ दिनों में काफी काम किए गए हैं हालांकि टाईम बहुत कम था । सरकार ने बजट में लोगों पर टैक्स बर्डन नहीं डाला है इसके लिए मैं सी०एम० साहब को, वित्त मंत्री जी को और सबको मुबारिकबाद देता हूं । यह एक बिजनरी बजट है। स्पीकर सर, अब मैं अपने टोहाना हल्के के मुताल्लिक कुछ बातें रखना चाहता हूं। टोहाना शहर में सिवरेज बहुत पुराना पड़ा हुआ है। अब शहर काफी बढ़ गया है। इसलिए कुछ एरियाज में सिवरेज हमारे इस शहर का अभी अनकवर्ड है। इसी तरह से वहां पर पीने के पानी का वाटर वर्क्स जो लगा हुआ है वह भी बहुत पुराना हो गया है। वहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से

रिक्वैस्ट करूंगा कि या तो वहां पर ऐडीशनल वाटर वर्क्स लगाया जाए या उस पुराने वाटर वर्क्स की कैपेसिटी बढ़ायी जाए। वहां पर और ट्यूबवैल्ज भी लगवाएं जाएं क्योंकि गांवों में कई जगहों पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर और ट्यूबवैल्ज लगवाकर या कैनाल बैस्ड वाटर टोहाना हल्के के गांवों में दिया जाए। इसी तरह से आज गांवों में गरीब आदमियों को बहुत दिक्कत है। आज उनके परिवार बहुत बढ़ गये हैं इसलिए सरकार की तरफ से पंचायतों को इंस्ट्रक्शंज दी जानी चाहिए कि वे इन गरीब आदमियों को प्लाट्स काटकर दें। इसी प्रकार से मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा। टोहाना एक इंडस्ट्रियल बैकवर्ड इलाका डिक्लेयर हुआ है जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। टोहाना रेलवे लाईन से कनैक्टेड है इसलिए अगर यहां पर इंडस्ट्री लगे तो उसको बहुत बूस्ट मिल सकता है। सरकार को वहां पर जौब ओरिएन्टेड इंडस्ट्रीज लगवानी चाहिए। जो रैपिड इंडस्ट्रिलाईजेशन पोलिसी के तहत इंडस्ट्रिलाईजेशन होने जा रहा है। उसके लिए सरकार को बताना चाहिए कि इनके लिए बिजली कहां से आएगी क्योंकि इंडस्ट्री काफी बिजली कंज्यूम करती है। अगर इनको थोड़ी सी छिदायतें दी जाएं और यदि उनसे कहा जाए कि वे अपना बायलर प्लांट लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करें तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे हमारे गांवों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती रहेगी। टोहाना में एक फैक्ट्री लगी हुई है, वह अपनी बिजली खुद बनाती है। इसलिए सरकार के ओफिसर्ज को उस फैक्ट्री के सिस्टम को जाकर देखना चाहिए । उनके पास सरप्लस बिजली है और वह इसको देने के लिए भी तैयार हैं इसलिए इस बारे में देखा जाना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री लगे उसके लिए यह भी जरूरी होना चाहिए और सरकार को उनको बता देना चाहिए कि जो नोन टैक्नीकल स्टाफ होगा उसको आपको उसी एरियाज से लगाना पड़ेगा जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। टैक्नीकल स्टाफ लगाने को तो हम नहीं कह सकते लेकिन नोन टैक्नीकल स्टाफ तो वहीं का लगना चाहिए। यह उनके लिए कम्पलसरी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से टोहाना हल्के में रोडज और स्ट्रीट लाईटस की हालत भी अच्छी नहीं है। मैं इन रोडज के बारे में राईटिंग में सरकार को भिजवा दूंगा। ये रोडज जरूर बनवायी जानी चाहिएं। हमारा एरिया फ्लड प्रोन एरिया है घग्गर के द्वारा वहां पर फ्लड आती है। बारिश दूर नहीं है इसलिए वार फुटिंग पर रंगोई नालें को मजबूत किया जाना चाहिए और फ्लड को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। आज टोहाना के एरियाज में काफी लोग ढाणियों में आकर बस गए हैं क्योंकि गांवों में जगह कम है लेकिन इन ढाणियों में बिजली के कनैक्शंज नहीं हैं। यमुना वाटर के बारे में मेरा गवर्नमैंट से अनुरोध है कि यमुना का वाटर जो फ्लड करता है उसकी यदि स्टोरेज की फैसिलिटी बन जाए तो उससे पानी भी मिलेगा और फ्लड से भी बचा जा सकेगा। पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे पिताश्री हरपाल सिंह जी ने टोहाना में एक राइस शैलर मंजूर कराया था लेकिन जमीन ऐक्वायर होने में दिक्कत आई थी इसलिए वहां पर राइस शैलर नहीं बन सका था वह मंजूर पड़ा हुआ है हमारा पैडी एरिया है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उसको जरूर लगवाया जाए। पैडी एरिया करके बिजली का लोड भी टोहाना को ज्यादा मिलना चाहिए।

चौ० हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने विचारों की लाइन में सबसे पीछे मेरा नंबर तो लगाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने 9 जून को जो बजट पेश किया उसके बाद डिमांड आई और आज ऐप्रोप्रिएशन बिल पेश हुआ है। यह जो बजट है इसकी प्रशंसा व सराहना जिस तरह से हरियाणा की जनता ने की है उससे साफ जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर की नीयत, चरित्र व काबिलियत और वित्त मंत्री जी की नियत और

[चौ० हर्ष कुमार]

काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है। जहां तक मेरे इलाके की समस्याओं की बात है मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है और आज भारत को आजाद हुए भी 50 साल हो गए हैं लेकिन 50 साल की आजादी के बाद से उस इलाके की किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली। 1996 में उस इलाके को उम्मीद बंधी थी लेकिन 3 साल के बाद ऐसी शख्सियत के हाथ में सत्ता आ गई जिसने सारी व्यवस्था चौपट कर दी और उस इलाके को फिर से 50 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। जैसे कि उदय भान जी ने और कर्ण सिंह दलाल जी ने ध्यानाकर्षण का मसला उठाया था कि जो 25 किलोमीटर बांध उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है मेरा भी उसमें एक सुझाव है, कर्ण सिंह जी ने भी सुझाव रखे थे । 1998-99 में मेवात कैनाल की प्रपोजल शुरु हुई, उसका मॉडल तैयार हुआ, ऐस्टीमेट बना। 1998-99 के बीच 30 करोड़ रुपया मेवात कैनाल के लिए रखा गया। पलवल के पास धन्तरी गांव है वहां से दिल्ली की तरफ यमुना के पास 8 किलोमीटर तक दोनों तरफ हरियाणा है यहां से बैराज बनाकर 1200-1500 क्यूसिक पलवल से हथीन, नूंह में जो बांध बनाया है उस बांध का फायदा उठाते हुए कैनाल बना दी जाए क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है और खेतों के लिए पानी नहीं है यदि ऐसा कर दिया जाए तो मेवात एरिया अब जो उजड़ा हुआ इलाका बना हुआ है, दोबारा से खुशहाली वहां पर आ सकती है। आज तक मेवात में ज्यादातर हाकिमों ने नौकरशाहों के लिए काला पानी समझ रखा था जिस भी अधिकारी या कर्मचारी को सजा देनी हो तो सिरसा से उठाकर मेवात में लगा देते या फिर मेवात में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी रहे हैं जो भ्रष्ट हों। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर काबिल और ईमानदार कर्मचारी और अधिकारी लगाये जाएं। ताकि वहां के लिए जो भी परियोजनाएं सरकार दे उनका ठीक तरह से उपयोग हो। जैसा कि बजट में भी जिक्र किया गया और उसमें जल संसाधन का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है मेरे हल्के में दो ड्रेनें हैं एक उजीना और दूसरी गोच्छी, 1996-97 में जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी उस समय वहां पर क्रोसिंग रेगूलेटर लगाये थे जिसके कारण वहां के 50 गांवों की जमीन का जल स्तर 30 फुट ऊपर आ गया था। लेकिन जब चौटाला साहब की सरकार आई तो उन्होंने उस परियोजना को फेल कर दिया और सारा काम बीच में ही ठप्प हो गया मेरा सरकार से अनुरोध है कि डब्ल्यू०जे०सी० या दिल्ली ब्रान्च से पानी लेकर उन ड्रेनों का पानी बढाया जाये। दूसरे मेरे हल्के के 70 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जिनमें मास्टर नहीं है। जहां तक सड़कों की बात है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है। यह कहना कि हरियाणा में एक भी गांव सड़कों से अछूता नहीं है। लेकिन मेरे हल्के का उमरहेड़ा गांव ऐसा है जिसमें आज तक कोई सड़क नहीं है। 1998 में इस गांव की सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, उनका अर्थ वर्क कम्पलीट हो गया था। फिर वही बात कि चौटाला साहब ने आते ही उस काम को वहीं पर बन्द कर दिया और वह गांव दुर्भाग्य से फिर सड़क से वंचित रह गया। इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या इसलिए है क्योंकि पिछली सरकार ने वहां लॉ एण्ड आर्डर को बिल्कुल तहस-नहस करके रख दिया जिस कारण वहां पर माफिया लोगों ने पानी के कनैक्शन ले लिए कोई अपने खेत में पानी देता है तो कोई अपनी सब्जी में। जिसकी वजह से 70-80 गांवों में पीने का पानी नहीं जाता है। वहां की जनता पैसे से पानी लेती है। चौटाला साहब ने हथीन की म्यूनिसिपल कमेटी को बन्द करके वहां पर पंचायत बना दी थी जबकि हथीन जो पिछड़ा हुआ था वहां हुड्डा ने सैक्टर काटे हुए थे लेकिन जब से हथीन की म्यूनिसिपल कमेटी को पिछली सरकार ने पंचायत बनाया है तब से वहां से इण्डस्ट्रिज वापिस

जाने लग गई हैं और हुडा ने भी सैक्टर काटने भी बन्द कर दिये हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please wind up, no time is left.

चौ० हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन वाईड करने का तो अभी समय नहीं हुआ है क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए पांच मिनट दिए थे।

Mr. Speaker : Please wind up, no time is left. No question of five minutes. You will get time on Monday. डेढ़ बजे हाउस खत्म है, आप केवल एक मिनट में वाईड अप करें।

चौ० हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही है, इससे ज्यादा मैं वाईड अप नहीं कर सकता, लेकिन एक आध बात और कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देंगे तो कह दूंगा वरना बैठ जाऊंगा।

Mr. Speaker : Please go ahead.

चौ० हर्ष कुमार : स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के के स्कूलों में अध्यापकों की बहुत कमी है। मेरी शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे हल्के के स्कूलों में टीचर्स लगाए जाएं, इसके अलावा मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि 5-7 दिनों में मेरे हल्के के जोहड़ों में पानी नहीं आया और लोगों को पीने का पानी नहीं मिला तो लोग सस्ते दामों में अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर होगें। पीने के लिए लोग गांवों में 10-10 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टरों पर पानी भर रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो जन समस्याएं हैं उन पर तुरन्त प्रभाव से मुख्यमंत्री महोदय गौर करें और उन्हें पूरा करवाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मेरी अपील है कि इधर बैठे हुए और उधर बैठे हुए साथी ये अपनी अपनी पार्टियों की मर्यादा और अपनी पार्टी के आदेशों से बंधे हुए हैं लेकिन हम ही 10 ऐसे लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत बात कहने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो ये 10 इंडीपैंडट मैम्बर्ज हैं इनको जितना साथ देंगें उतने ही ज्यादा अपको सुझाव मिलेंगे। (विघ्न) हमारी बात का ही ज्यादा महत्व है। धन्यवाद।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया (बावल, एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो पेश हुआ है, यदि मैं इसे जनहितैषी बजट कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बजट में कई निर्णय इतने अच्छे लिए गए हैं कि जिनकी बहुत दिनों से इन्तजार थी पिछले 10 सालों से पूरा हरियाणा बाट जोह रहा था कि किसी तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस का राज आए और हमारे दुखों का निवारण हो और अब यह साबित हुआ है और वास्तव में उनके दुखों का निवारण होने की आशा जागी है। अध्यक्ष महोदय, आज का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है इससे किसान और मजदूर की इतने लम्बे समय की मांग को पूरा किया गया है। यह एक ऐतिहासिक डिसीजन है। मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी अधिवेशन में सोनिया गांधी जी बैठती थीं तो वह एक ही मांग करती थी कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए, मुझे इस बात के लिए खुशी है कि आज इन्होंने साबित करके दिखाया है कि उनकी इच्छा और मंशा को पूरा किया है कि वास्तव में कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। समय बहुत कम है इसलिए मैं अपने हल्के की बात कहना शुरू करती हूं। मेरे हल्के के अन्दर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का एक रीजनल सैन्टर हुआ करता था।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of this House may be extended for half an hour ?

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for half an hour.

विधान कार्य—

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2005 (पुनरारम्भ)

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, उस रिजनल सैन्टर की बिल्डिंग वर्ल्ड बैंक के फण्ड से बनी हुई है। वहां बेर, अमरूद और बेल पात्र काफी होते हैं। वहां ड्राई रिसर्च सैन्टर है। कृषि महाविद्यालय कालेज बनाया गया था कि बच्चे दाखिल हो जाया करते थे हिसार में और उनकी क्लासें बावल में लग जाया करती थी। बावल और उसके आस पास के बच्चे या तो हिसार में पढ़ने के लिए जाएं या लखनऊ या किसी और जगह एग्रीकल्चर शिक्षा लेने के लिए पढ़ने के लिए जाएं। पहले किसानों के बच्चों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए एक व्यवस्था कर दी गई थी कि वे बच्चे सूखी रोटी खा कर वहीं अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का राज जाते ही उसे उठा लिया गया। उसके लिए बजट में बहुत कम पैसे का प्रावधान करना पड़ेगा। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने नरेश भाई के प्रश्न के जवाब में ना कह दिया जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे उस समय एक्सप्लेन करने का अवसर नहीं मिला और नरेश भाई को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। अब मैं इस बारे में बताना चाह रही हूं कि वहां पर बिल्डिंग बनाने का खर्चा नहीं होगा। वहां पर किसानों के मेले हर साल लगते रहते हैं। उसमें सूखे पर खोज होती है इसलिए मैं चाहूंगी कि उसको लागू करें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त बावल में एक डिग्री कालेज है जिसमें बहुत बड़ा ग्रोथ सैन्टर है और उस डिग्री कालेज से पिछली सरकार ने साईंस फैकल्टी दूर कर दी। वहां के बारे में इनेलो वाले कहते थे कि यह उनका एरिया है, वहां की चौरासी उनकी है। अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कोई अपनों का विकास करता है या विनाश करता है। उन्होंने वहां के कालेज से साईंस फैकल्टी उठाकर यह साबित नहीं कर दिया कि वे वहां के बच्चों को विनाश की तरफ धकेलना चाहते थे। मेरी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनेलो पार्टी ने उस कालेज से साईंस फैकल्टी को दूर कर दिया था वह दोबारा से वहां शुरू करवाई जाये ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अफसर बन सकें। इसके अतिरिक्त बावल के अंदर YKK और ASAI इण्डिया जैसी बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। उनके वहां होते हुए छोटी फैक्ट्रीयां लगाने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि वहां पर 266 के०वी० का एक ही सब स्टेशन है जिससे गांवों को, बावल शहर को और फैक्ट्रियों को भी बिजली की सप्लाई दी जाती है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वहां पर फैक्ट्रियों के लिए बिजली की अलग से व्यवस्था की जाये ताकि छोटी इण्डस्ट्री भी वहां लग सके। जो बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं वे तो अपना बिजली यूनिट लगा लेती हैं लेकिन छोटी इण्डस्ट्री नहीं लगा सकती। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे वहां जितनी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उनके अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी और इण्डस्ट्री मंत्री जी यहां बुलाकर उनसे बात करें कि वहां पर एनसैलरी यूनिट लगाना शुरू करें। वहां सुढाणी गांव में एनसलरी यूनिट बना भी था। पंचायत की तरफ से 6 एकड़ जमीन उन बच्चों के लिए जो बच्चे छोटे-छोटे यूनिट लगाने में रूचि रखते हैं दी गई थी लेकिन अब

यह यूनिट बंद पड़ा है। यह यूनिट सरकार ने बनवाया था और पंचायत ने जमीन दी थी आज यह उखड़ा पड़ा है और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो कमरे बने थे वे खाली पड़े हैं। यदि वहां पर पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी तो बच्चे छोटी-छोटी यूनिट लगाने में सक्षम होंगे और अपना रोजगार कर सकेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि रिवाड़ी में जो हास्पिटल की बिल्डिंग है उसका बहन करतार देवी जी ने ही उद्घाटन किया था लेकिन आज उस बिल्डिंग की बहुत जर्जर हालत है। वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरा हाल है यदि किसी मरीज को दाखिल करवाया जाता है तो डाक्टर भी ठीक तरह से देखभाल नहीं करते। मरीजों की रोटियां तक कुत्ते अंदर जाकर उठा ले जाते हैं। उस बिल्डिंग के सभी शीशे तक टुटे हुए हैं उस ओर हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दें। इसके अलावा वहां की एक दर्दनाक घटना मैं सदन को विशेषकर हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन करतार देवी जी को बताना चाहूंगी कि एक सैनियों का लड़का कूएं में कूदकर मर गया था। दो-तीन दिन बाद जब पता लगा तो लोगों ने कुएं से उसकी लाश निकाली और उसका पोस्टमार्टम होने के लिए रिवाड़ी के सरकारी हॉस्पिटल में उसकी लाश आई। वह लाश काफी गल-सड़ गई थी। डाक्टरों की आपसी लड़ाई के कारण उस लाश का वहां पोस्टमार्टम नहीं हुआ और तीन दिन तक वह लाश वहां पड़ी रही। डाक्टर एक दूसरे को कहते कि मैं नहीं आप पोस्टमार्टम करोगे। मेरे कहने का मतलब वे एक दूसरे पर जवाबदारी डालते रहे। उसके बाद लोग सड़कों पर एजीटेशन के लिए आये तब जाकर यह लाश रोहतक भेजी गई। उसके बाद यह लाश रोहतक मैडीकल कालेज में पोस्टमार्टम के लिए गई तब तक वह पूरी तरह से गल चुकी थी और हड्डियां खाल से बाहर आ चुकी थी। लेकिन जिन डाक्टर्ज की वजह से उस लाश की यह हालत हुई, वे डाक्टर्ज अब भी रिवाड़ी में ही कार्यरत हैं इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी कि रिवाड़ी हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को बदल दिया जाये और नये स्टाफ की व्यवस्था की जाये।

Mr. Speaker : Thank you very much, Bahin ji, please wind up.

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर सर, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर लूंगी। कुण्ड मण्डी में स्लेट का पत्थर बनता है और वहां पर बहुत से लोग और मजदूर रहते हैं। कई बार वहां पर मजदूर पहाड़ से गिर जाते हैं या पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। गिरने के कारण कई बार उनको चोट लग जाती है। कुण्ड मण्डी इतनी बड़ी है और वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैं पिछले 10 साल से यह मांग कर रही हूं कि सरकार वहां पर अस्पताल बनाए। लोग वहां पर पत्थरों के बीच में रहते हैं और फिसल कर मजदूरों को चोट लग जाती है या पत्थर खिसकने के कारण वे नीचे दब जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए होस्पिटल में ले जाना होता है लेकिन वहां पर हॉस्पिटल न होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदया से प्रार्थना करती हूं कि वे मेरी बात जरूर मानें (विघ्न) स्पीकर सर, मुझे एक बात और कहनी है कि एम०एल०एज० के लिए विकास फण्ड का प्रावधान जरूर करवाएं। हम लोग गांवों में जाते हैं और लोगों की चाय पी कर आ जाते हैं। वहां जाने पर लोग हम से रिक्वैस्ट तो करेंगे ही टैन्ट लगा कर बालूशाही रखेंगे, बर्फी रखेंगे और हम लोग यह सब खा पी कर आ जाते हैं। हम लोग उनको एक धवन्नी भी न दे पाएं तो यह बात अखरती है और यह ठीक नहीं लगता (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह बात ठीक कह रही हूं। अगर एम०एल०ए० को विकास फण्ड दे दिया जाए तो इसके लिए हम सब आपके आभारी होंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you very much, Bahin ji. Please take your seat. Please listen to me. This is the first Budget Session of Haryana where 57 members have spoken. (Interruptions) Even then you are not satisfied. I am sorry to say.

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, एम०एल०ए० फण्ड के लिए कम से कम एक करोड़ रुपये का प्रावधान तो होना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker: Please Bahin ji, take your seat. Next speaker, Shri Randhir Singh.

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह (बरवाला) : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया। सबसे पहले तो कृषि के विकास के लिए जो नीति सरकार ने बनाई है और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए जाने की घोषणा की है। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं उसके बाद में मेरे अपने हल्के की कुछ समस्याएं हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उन समस्याओं का समाधान करे। सबसे पहले मैं सिंचाई के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे हल्के में लगभग 6 टेलें लगती हैं उन टेलों में पिछले 6-7 सालों से पानी नहीं आया है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा तथा उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी इन टेलों पर पानी आना चाहिए। स्पीकर सर, बरवाला शहर 50 हजार की आबादी का शहर है वहां पर म्यूनिसिपिल कमेटी तो है लेकिन सीवरेज सिस्टम नहीं है। मैं माननीय पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी को नोट करवाना चाहता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां की म्यूनिसिपिल कमेटी में पिछले करीब दो साल से न तो कोई सैक्रेटरी है और न ही कोई जे०ई० है जिससे शहर के लोगों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है, मेरे हल्के में अभी अभी 4-5 स्कूल अपग्रेड हुए हैं एक प्लस टू का और एक मैट्रिक का स्कूल है। वहां के स्कूलों में टीचर्ज की बड़ी समस्या है वहां पर टीचर्ज नहीं हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे हल्के के स्कूलों में स्टाफ की जो कमी है उसको दूर किया जाए और वहां पर टीचर्ज लगाए जाएं। इसके साथ ही बिजली की जो समस्या है उसके बारे मे मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार भी कहती आई है और अब हमारी सरकार भी कहती है कि किसानों के घरों के ऊपर से गांवों में जो बिजली की तारें गुजरती हैं वह ठीक नहीं हैं और इन तारों से हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई जगहों पर गांवों में जो तालाब हैं उनके अन्दर बिजली के पोल्ज लगे हुए हैं और उनके अन्दर से बिजली की तारें गुजरती हैं जिससे हर समय बहुत भारी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उकलाना शहर की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि वहां पर पैदल चलना भी दूभर है। वहां पर गाड़ी में चलने से तो बहुत ही दिक्कत होती है। इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि मेरे हल्के में दो माईनर्ज बनाई जाएं। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर एक चुनाव जनसभा में गए थे और इन माईनर्ज के लिए बस भी करके आये थे और कहा था कि हम इनको बनवाएंगे। इन माईनरों के नाम खेड़ी ज्वाला और मतलौडा माईनर्ज हैं। स्पीकर साहब इसके साथ ही साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : फौजी जी, आप बैठ जाएं। आपको भी समय मिलेगा । अब भरत सिंह जी बोलेंगे।

श्री भरत सिंह (समालखा) : स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले तो आनन्द सिंह डांगी जी ने बीरेन्द्र सिंह के बारे में वाक्य कहा था कि उन्होंने जाट होते हुए भी इतना बढ़िया बजट पेश किया है उसके लिए मैं इनकी सरहाना करता हूं। इस बात पर श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने ध्यान दिया था कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर। स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने इतना बढ़िया बजट लाकर यह साबित कर दिया है कि ये आने वाले समय में हरियाणा को हिन्दुस्तान में नम्बर वन की स्टेट बनाकर रहेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री को एक और बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों की भ्रान्ति और भ्रम दूर कर दिया कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोगों से पैसा इक्ट्ठा किया जाता है। स्पीकर सर, हुड्डा जी चाहते तो ये लाखों अरबों रुपए इक्ट्ठे कर सकते थे। मैं यह गारन्टी के साथ कहूंगा कि हुड्डा जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने इलैक्शन के दौरान किसी से भी पैसा नहीं लिया है। हमें आज एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। इस बात के लिए मैं सोनिया जी का भी धन्यवादी हूं। स्पीकर सर, मैं एक नया सदस्य होने के नाते से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा अगर आपकी सरकार इस तरह से काम करती रहेगी तो जिस तरह से बंगाल के अन्दर 27 सालों तक ज्योति बसु की सरकार राज करती रही थी उससे भी ज्यादा आपकी कांग्रेस सरकार हरियाणा में राज करेगी और उनका रिकार्ड तोड़ देगी।

स्पीकर सर, आज आम आदमी रिश्वतखोरी से तंग आ गया है। आज यह रिश्वतखोरी कैसे बंद की जाए, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है, उसी तरह से हम सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। स्पीकर सर, स्वर्गीय राजेश पायलट जी कहते थे कि अगर जिन्ना साफ करना है तो पहले ऊपर से सफाई शुरू करो। मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने गन्दगी को ऊपर से साफ करने का काम शुरू किया है। स्पीकर सर, माननीय सदस्य मुख्यमंत्री जी से कहते हैं हमारे यहां पर ईमानदार आफिसर भेजो। मेरा कहना है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं उसी तरह से स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायकों को एक सलाह देता हूं कि वे भी इतने ईमानदार हो जाएं और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो किसी आफिसर की हिम्मत नहीं कि वे किसी से एक पैसा ले सकें। अगर आप सभी इस का उदाहरण लेना चाहते हैं तो किसी भी आफिशर को समालखा में भेज दो मैं उसको ईमानदार साबित करके दिखा दूंगा, यह मेरी गारन्टी है।

स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि दादागिरी कैसे बंद होगी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी दादागिरी से तंग है। दादागिरी लोगों द्वारा फिरौती मांगी जाती है और लोगों के अपहरण किए जाते हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको पकड़ कर अन्दर कर दो। वैसे तो श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री जी बनते ही दादागिरी का ग्राफ नीचे आ गया है। मेरा वित्तमंत्री जी को भी सुझाव है कि यह जो जेलों के लिए 35-36 करोड़ रुपए के करीब बजट में रखे गए हैं, उस बजट को जीरो कर दीजिए।

श्री भरत सिंह]

स्पीकर सर, दादा लोग जेलों में क्यों जाता है, क्यों आज दादागिरी को बढ़ावा मिल रहा है, यह भी देखने वाली बात है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगार युवक है वह यह सोचता है कि वह बी०ए० करेगा, पुलिस में भर्ती होगा और उसको 8 हजार रुपए मासिक मिलेंगे, लेकिन सारी उम्र उसका वह पैसा भी पूरा नहीं होगा जो उसने उस नौकरी पर लगने के लिए रिश्वत में दिया होगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे भर्तियों के बारे में भी विचार करें। स्पीकर सर, आज जो भी बेरोजगार आदमी दादागिरी करता है और वह 2-3 साल जेल में रह आता है तो उसको दादागिरी का लाईसैंस मिल जाता है और वह खून भी करने लग जाता है और लोगों को धमकियां देने लग जाता है। स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि उससे हमारे अधिकारी भी डरने लग जाते हैं, हमारे सदस्य डरते हैं और हमारे नेतागण भी डरते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सब अपने मन से डर निकाल दो, ऐसे लोगों से डरना बंद कर दो और उनका इलाज करवाना शुरू कर दो। उनको सड़क पर गिरा कर लट्ठ मरवाओं और उनके उपर केस बनवाओ। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कोई आदमी जेल में जाता है तो उसको 100-100 आदमी जेल में मिलने के लिए जाते हैं। उसको पैसे और घी पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उनकी मिलाई बंद करवा दो और यह हिदायतें दे दो कोई भी कैदी को मिलने नहीं जाएगा।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री भरत सिंह : भाई, आप बैठ जाएं। मुझे बोलने दें। बड़ी मुश्किल से तो मुझे बोलने का समय मिला है।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने कहा है कि सदन में बैठा हर मैम्बर ऐसे लोगों से डरता है, यह ठीक बात नहीं है।

श्री भरत सिंह : आपको ऐसे लोगों से ज्यादा प्यार लगता है । स्पीकर सर, मुझे बोलने के लिए बड़ी मुश्किल से समय मिला है और वह भी मेरे यह भाई खराब कर देंगे।

Prof. Chhattar Pal Singh : Mr. Speaker Sir, I want to speak on point of order.

Mr. Speaker: What is your point of order ?

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने पूरे हाउस के अन्दर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं। के बारे में कहा है कि वे सभी गलत किस्म की प्रवृत्ति वाले लोगों से डरते हैं । मैंने यह क्लैरीफाई कहने के लिए कहा है कि सारे हाउस को एलिगेट करना कि वे ऐसे लोगों से डरते हैं, यह ठीक बात नहीं है। (विघ्न) अब इस बारे में मैं स्पष्ट करने के लिए आपकी परमिशन से खड़ा हुआ तो इन्होने मुझे ही कह दिया कि आप उनके सबसे बड़े शुभचिन्तक हैं।

श्री भरत सिंह : छत्तर पाल जी, आप बैठ जाएं मैं बहुत बढ़िया बात कहने लग रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हो गयी है आप उनके शुभचिन्तक नहीं हो।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रिएलाइज कर लिया है।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज ऐसे लोगो के प्रति क्यों मोह इतना बढ़ चुका है। आज हर आदमी दादा बनना चाहता है क्योंकि जब कोई आदमी दादा बनकर

जेल में दो तीन साल रहकर जेल से निकलकर बाहर आता है तो लोग उसका पूरा सम्मान करते हैं। जेल में भी उसको मिलाई मिलती है। लोगों द्वारा उसका स्टेटस बढ़ाया जाता है। और जेल के अंदर उसकी पूजा होती है। जेल के अंदर उसके पास मोबाइल होता है और देखने के लिए टी०वी० दिया होता है तथा जिस तरह से उसके कई कई चेले पैर बोचते हैं, उसकी सेवा करते हैं तड़का लगाते हैं तो इससे तो मोह बढ़ेगा ही। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जेल के अंदर कैदियों की मिलाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए। साथ ही उनको सुबह से लेकर शाम तक कस्सी देकर खुदाई करने के लिए कहा जाना चाहिए। बदमाशों के लिए कोई कानून नहीं है वह किसी का भी मर्डर कर देता है किसी पर भी डैकती डाल देता है फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है इसलिए जज उनको बरी कर देता है। मैं कहता हूं कि जब ऐसे लोग जेल के बाहर आये तो उससे कोई मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वे पंच, सरपंच, जिला परिषद के मैम्बर या चेयरमैन या एम०एल०ए० बन जाएंगे और आप यहां बैठे देखते रहना । जब वे जेल से बाहर आएं तो उनसे मोबाइल या कार जो उनके नाम नहीं होती है, को जब्त कर लेना चाहिए। अगर किसी ईम्पलाई को तनख्वाह के रूप में दस हजार रुपये मिलते हैं तो इन्कम टैक्स वाले उसका पूरा हिसाब रखते हैं और यदि कोई कमी होती है तो उसको दण्ड भी देते है जबकि ऐसे लोग करोड़ों रुपये का मकान, कार और कोठी रखते हैं और उनसे कोई हिसाब नहीं मांगा जाता। इसलिए उनसे यह हिसाब मांगा जाना चाहिए कि यह सम्पत्ति आपके पास कहां से आयी और कैसे आपने ये खर्च की ? अगर इस तरह से सख्ताई की जाएगी तथा ऐसे गलत लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा तो गांवों के अंदर कोई गलत किस्म का आदमी नहीं बनेगा और ईमानदारी का जमाना शुरू हो जाएगा तथा लोग भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार का गुणगान करेंगे। जिस तरह से बिजली के बिलों को माफ करने की आज घोषणा की गयी है तो उसके बाद कुछ आदमी मेरे पास मिलने के लिए आए और वे कहने लगे कि भरत सिंह जी, आप विधायक बनकर आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि अब सरकार बदल गयी है भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गया है तथा अब कांग्रेस की सरकार आ गयी है इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, वे मन सा मार रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बताओ तो सही क्या हो गया। वे बोले जी, सरकार पूरी कोई ना बदली अभी तो टांग टांग बदली है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि सरकार पूरी तरह बदल गयी, सब कुछ बदल गया। आपका धन्यवाद।

श्री रामकिशन फौजी (बवानी खेड़ा, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज किसान के लिए बेहद खुशी का दिन है। मैं उस दिन की याद दिलाऊं जिस दिन राम वनवास काटकर आये थे और लोगों ने खुशियां मनायी थी। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आज किसानों को इतनी राहत दी है वह काबिले तारीफ है पिछली सरकार ने किसानों पर बहुत ज्यादतियां की थी। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने खून की होली खेली थी किसानों की तरफ बिजली के बिल बकाया थे। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत खुशी का दिन है। जैसे दीवाली का त्यौहार मनाया जाता है तो आज वैसे ही मनाया जाना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस सदन में इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया जाए और इस कमेटी के सदस्यों, चेयरमैन एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई दी जाए तथा हिन्दुस्तान की सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा जाए कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए क्योंकि इन्होंने इतना सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया है।

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप समय का भी ख्याल रखें।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप मुझे समय कम दोगे। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं कि आखिरी वक्त में आपने मुझे समय दिया। मैं सिंचाई के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। पिछली सरकार ने मेरे हल्के बवानी खेड़ा में एक कौड़ी का काम भी नहीं किया और इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वे यह सोचते थे कि यह चौधरी बंसी लाल की पार्टी का विधायक है। मुख्यमंत्री जी भी उस दौरान मेरे साथ विपक्ष में थे। उस शासन काल में जिन हल्कों में काम नहीं हुए थे उनमें प्रायोरिटी बेस पर काम करवाए जाएं। मेरे हल्के का कोई आदमी चौटाला साहब के पास जाता था तो उसको कह दिया जाता था कि फौजी के पास जाओ। भगवान की कृपा से कांग्रेस की सरकार आई, श्रीमती सोनियां गांधी के आर्शीवाद से सरकार बनी। मेरे हल्के के लोगों को पिछले कई साल से पानी नहीं मिल रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि पीने का पानी नहीं है। कंवारी, पालावास, धमाना, खानक जैसे कई गांव हैं जिनमें 30 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी मंगाया जाता है एक घडा पीने का पानी 15 रुपये में मिलता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले हमारे वहां जो पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी से मैंने टाईम भी लिया है और मैं उनको मौके पर भी दिखाऊंगा। मेरे हल्के में बहुत सारी टेल पड़ती हैं बास माईनर है, मुंढाल माईनर, सिसरी माईनर, तालू हैड, सोरखी की माईनर, सुंदर डिस्ट्रीब्यूट्री, तालू सिवाड़ माईनर, बवानी खेड़ा माईनर, बलधाली माईनर, बुलटाना माईनर, खानक माईनर, नलवा टेल है। अध्यक्ष महोदय, सुंदर नहर पर पिछले 20-25 साल पहले जो कैपेसिटी थी वह 570 क्यूसिक पानी की थी, अब लगभग 600 क्यूसिक पानी मिलता है। पीने के पानी की मोरियां लगें, जो जमीन में पानी नहीं था उसके लिए भी मोरियां लगाएं। सुंदर नहर माईनर में टेल पर पानी नहीं गया, कुछ हद तक बंसी लाल जी के समय में गया था, उसके बाद चौटाला सरकार के वक्त में बिल्कुल पानी नहीं गया है। अब मुख्यमंत्री जी और इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने कोशिश तो की है लेकिन अभी तक वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वहां पर पीने के पानी का प्रबंध किया जाए। अब मैं बिजली के बारे में कहूंगा कि बिजली में कुछ हद तक सुधार हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक पूरा सुधार न हो जाए तब तक कम से कम सुबह और शाम को तो जरूर बिजली दी जाए। सुबह 5 से 7 बजे तक बच्चों के पढ़ने का समय होता है और महिलाएं घर के काम करती हैं। जैसे दूध बिलोना आदि सब काम बिजली पर आधारित हैं और शाम के समय खाने का समय होता है उस समय बिजली का कट न लगाया जाए। अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा, मेरे हलके में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो टूटी पड़ी हैं, पिछली सरकार ने एक दो सड़कें बनवाई थीं लेकिन उनमें तारकोल नहीं डाला गया। पता नहीं चौटाला साहब खा गये। एक रोड़ भिवानी से लौशाम बनाया गया था ऐसे तीन रोड़ बनाये थे वे सारे रोड़ टूट गये। तारकोल बिलकुल नहीं डाला गया ऊपर काली मिट्टी डाल दी गई। कुछ रोड़ तो बचे हैं, कुछ तो बनने से पहले ही टूट गये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वे खास तौर से इसकी इन्क्वायरी करवायें और जिस आदमी की जिम्मेदारी बनती है उसको दोषी करार दें। धन्यवाद।

चौ० भरत सिंह बैनिवाल (दड़बा कलां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरा हल्का राजस्थान के साथ लगता है वहां पर लाईट की बड़ी दिक्कत है मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाये। एक बात और कि मेरे

हल्के के जो भी कांग्रेस से जुड़े लोग थे उनके साथ ज्यादती की गई उन पर गलत केस बनाये गये थे, मुख्यमंत्री जी, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। वर्ष 2002 में केसपुरा गांव में एक काण्ड हुआ था लेकिन उस केस की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। उसमें तीन लड़कियां थीं एक हमारी बहन थी और दो लड़कियां जिनकी उम्र एक साढ़े ग्यारह साल और दूसरी की साढ़े तेरह साल थी और जो बड़ी थी उसकी उम्र 40 साल थी वे सभी खेत में गई हुई थी उनको वहां से उठाकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उन तीनों का बाद में कत्ल कर दिया गया और उन्हें नहर में डाल दिया गया लेकिन आज तक उनके केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे सभी लड़कियां बाजीगर बिरादरी से संबंध रखती थीं। जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया उनमें एक आदमी 85 साल का था, दूसरे को मरे हुए 7 साल हो गये थे और तीसरे को मरे हुए 16 साल हो गये थे उन सब पर केस दर्ज किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस केस की जांच सी०बी०आई० से करवायें और जो असली मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाये और जो हमारी बहन-बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है उनको न्याय दिलाया जाये। अगर उन बहन-बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होगी तो गरीब आदमी की बहन बेटियों का बाहर जाना ही मुश्किल हो जाएगा। चौटाला साहब ने सिरसा में तो काम किये होंगे लेकिन उनके शासन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व वाले मैम्बरों के खिलाफ बड़ी ज्यादती हुई है उनके खिलाफ गलत मुकदमें दर्ज कराये गये। खुद मेरे ऊपर सात साल पुराना 62 किलो अफीम का केस बनाया हुआ है। धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the sitting of the House may be extended till the conclusion of the reply of the Finance Minister ?

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The sitting of the House is extended till the conclusion of the reply of the Finance Minister.

विधान कार्य–

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2005 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now, I request Hon'ble Finance Minister to start his reply.

Dr. Sushil Indora: Speaker Sir, * * * ** *

Mr. Speaker : Please take your seat. Please do not waste the time of the House. Nothing is to be recorded. Whatever he is saying is not to be recorded. It was decided by me कि जो मैम्बर बोल लिए हैं उनको दुबारा बोलने के लिए समय नहीं मिल पायेगा। 5-7 मैम्बर्ज बजट पर बोल चुके हैं। बजट के बाद भी कई सदस्य बोले हैं। आपने जिसकी भी चिट भेजी उस सदस्य को बोलने का समय दिया गया है बल्कि एक को तो एडीशनल समय दिया गया है। आपने यह कैसे सोच लिया कि हर एक बात पर बोलना है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

14.00 बजे **डॉ० सुशील इन्दौरा** : अध्यक्ष महोदय, सदन में परम्पराओं का निर्वाह होना जरूरी है। *****

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नरेश शर्मा जी आप बैठें।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, नरेश शर्मा जी हमारे नौजवान साथी हैं, मैं वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि एक मिनट बोलने का समय हमारे नौजवान साथी को दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : वे बोल चुके हैं।

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, समय को बांट दिया जाए। इनको मर्जी का टाइम चाहिए और मर्जी का टाइम न मिले तो ये भाग खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप बैठ जाएं।

डा० सुशील इन्दौरा : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल हाउस में रखा गया है यह सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेवारी थी क्योंकि वर्ष 2005-2006 में 17 हजार 620 करोड़ रुपये का जो खर्चा आने वाले समय में होगा जिसका प्रावधान इसने जब बजट पेश किया था उसमें किया था, उस खर्चे को विधान सभा की स्वीकृति के लिए जो हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी थी आर्टिकल 204 क्लाज 1 में पूरा करने के लिए सदन में मैंने रखा। आज शायद ही यह पहला मौका था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए लगभग 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें से बहुत से सदस्य ऐसे थे जिन को पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे भरत सिंह छोकर जैसे माननीय सदस्य को बीच बीच में बोलने का मौका देना चाहिए ताकि सदन का माहौल थोड़ा खुशगवार रहे। जब आपने मुझे बोलने के लिए कहा तो मैं यह सोच रहा था कि जो सदन में ये 3 बड़े खम्भे हैं इन पर जो लिखा हुआ है उसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है। इसमें लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए यदि प्रवेश किया जाए तो इसमें स्पष्ट और साफ बात कही जाए क्योंकि न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है, इसमें मैं जो सुधार चाहता हूं, यहां आने के बाद तो हो सकता है अपने आप में कोई सुधार कर ले लेकिन यहां आने से पहले जो असत्य बात बोली जाती है, सदन में प्रवेश करने के लिए जो व्यूह रचना राजनैतिक दलों द्वारा या राजनेताओं द्वारा रची जाती है वह सभी को पता है। गलत बात की शुरुआत तो वहीं से होती है। उस पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक सदन में सच बोलने की

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

आदत नहीं बन सकती । गलत बात की प्रकाष्ठा इनेलो के नेताओं ने जिस प्रकार व्यवहार में की मैं भी 35 साल से राजनीति में सक्रिय हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि एस०वाई०एल० मुद्दे पर हमेशा ये लोग राजनैतिक लाभ उठाते रहे हैं। आज देवी लाल जी दुनिया में नहीं हैं यह मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने एस०वाई०एल० के मुद्दे को जब भी वोट लेने का समय आया उसी समय भुनाने की कोशिश की। चौटाला साहब चुनावों के समय जनता से कहते थे कि यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो बिजली के बिल माफ कर दूंगा और आगे के लिए बिजली किसानों को मुफ्त देने की बात कहते थे। वे मुख्यमंत्री भी बने लेकिन किया कुछ नहीं। फिर हम यह कहें कि सदन में आकर सच बोलो गजब की बात है। इंदौरा साहब और बलवंत सिंह सढौरा साहब फिर कहेंगे कि ऐसा हमने तो कभी घोषणा पत्र में नहीं लिखा। अध्यक्ष महोदय, यही तो गलत है कि लोगों के सामने कुछ कहें, घोषणा पत्र में कुछ लिखें और यहां आकर कुछ बोलें और इन्हीं विसंगतियों के कारण राजनीति का स्तर गिरा है। आज मैं यहां गलत बात बोलने के लिए नहीं आया । मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसे राजनैतिक दलों या ऐसे राजनेताओं को जो लोगों के बीच में कुछ वायदे करते हैं, घोषणा पत्र में कुछ लिखते हैं और यहां आकर एकदम मुकर जाते हैं उन पर इलैक्शन लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए तभी इस स्थिति में सुधार हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब हमने अपने घोषणा पत्र की कमेटी बनाई थी उस समय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें खास निर्देश दिए थे कि कोई ऐसा वायदा नहीं करना जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। हमने उनके निर्देशों के अनुसार अपने घोषणा पत्र में वही वायदे किए जिनको हम निभा सकने में अपने को सक्षम समझते थे। आज हम 17,642 करोड़ रुपये की बजट अनुदानों की स्वीकृति के लिए यहां खड़े हुए हैं। मुझे यह भी पता है कि 1600 करोड़ रुपये का इजाफा खर्चे में होगा लेकिन हम हरियाणा के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा की किसानों की व्यथा को समझते हुए ही यह सब कुछ कर रहे हैं जिन लोगों ने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ गलत वायदे किए उन लोगों को चौराहे पर नंगा किया जाना चाहिए तभी मैं समझता हूं कि राजनीति में सुधार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो अपने घोषणा पत्र से आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि 1600 करोड़ रुपये की राशि माफ की जाये। मैं बहुत से ऐसे राज्यों के बारे में जानता हूं जहां राजनैतिक दलों ने सत्ता में आने के लिए कह दिया कि किसान को बिजली मुफ्त दी जायेगी। ये कुछ दिनों के लिए कर भी देते हैं और फिर रिवर्ट कर जाते हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बेशक हमें बजट के अंदर कर्जा उठाना पड़े, अपने दूसरे खर्चे कम करने पड़े लेकिन जिस बात के लिए हरियाणा की राजनीति को गंदा किया गया था उसको सुधारें और उसको सुधारने की एक ही बात है कि जनता से गलत बोलने वालों को हम उनके घर तक छोड़कर आयें। आज चौटाला साहब सदन में उपस्थित नहीं हैं वे इसलिए सदन में नहीं आये क्योंकि यहां पर उनकी गलत बातों पर पर्दाफाश होगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी मानवता की बात का जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। (विघ्न)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

Mr. Speaker : Indora ji, have patience please.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह कहना चाहता हूं कि ये मेहरबानी करके मेरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये (विघ्न एवं शोर)।

Mr. Speaker : This is not the way, (Interruptions) you are behaving like when Lok Dal was in power.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये । (विघ्न एवं शोर)। स्पीकर साहब, यह मानवता की बात है (विघ्न एवं शोर)।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, माननीय साथी इन्दौरा साहब मानवता की दुहाई देते हैं। चौटाला साहब जब चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे तभी उनकी टांग में प्रॉब्लम थी लेकिन उस समय वोट चाहिएं थे इसलिए उनमें उस कष्ट को सहने की भी क्षमता थी। स्पीकर सर, आज भी अगर उनको यह पता होता कि हरियाणा की कांग्रेस की सरकार भूपेन्द्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर और उनके साथियों को बिजली के बिलों की अदायगी करने के मामले में पीछे हटना पड़ेगा, वे यह बिजली के बिल मुआफ नहीं कर सकेंगे तो चाहे वे कितने भी कष्ट में होते आज वे चल कर यहां विधान सभा में आते और इसके कारण चाहे उनकी पीड़ा और अधिक हो जाती वे आते जरूर । लेकिन उनको वास्तविकता का पता था आज कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं है। आज तो वे इस बात का इन्तजार करते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब कोई गलती करे तब हम सदन में आएं। स्पीकर सर, मैं कहता हूं कि आने वाले पांच सालों की हमारी जो प्राथमिकताएं हैं हमारी जो परफोरमैंस है वह हर साल बढ़ेगी और उनको पांच साल तक यहां पर हाउस में आने का मौका नहीं मिल सकता है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, आज ये यह बात कह रहे हैं कि हम अशोभनीय बात करते हैं। मैंने कौन सा ऐसा अशोभनीय काम कर दिया, जो यह अशोभनीय बात का जिक्र कर रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, मैंने कोई अशोभनीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैं कहता हूं कि मैंने पार्लियामैंट और असैम्बली के अन्दर भी ऐसी प्रोसीडिंगज़ देखी हैं जिनमें अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ है लेकिन मैंने कोई अशोभनीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसान और गरीब के भाग्य के निर्णय के लिए आज हमने किसानों के बिजली के बिल माफ करने की बात की है। मैंने पार्लियामैंट के अन्दर भी ऐसे वाक्य देखें हैं और इस सदन में भी देखे हैं कि पी०जी०आई० में ऑक्सीजन के मास्क लगे होते थे, ड्रिप लगी होती थी तो लोग वोट डालने के लिए जाते थे कि कहीं एक वोट से हार न जाएं। वे यहां पर आते तो यह भी मानवता की बात होती। स्पीकर सर, मानवता की बात तो यह भी है कि आज यहां पर सवा दो करोड़ लोगों की जिन्दगी का सवाल था (विघ्न एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Please take your seat. (Interruptions) I will not allow you. (Interruptions) I will request you to behave like a gentleman. (interruptions) What are you doing Mr. Indora. Whatever Mr. Indora is saying that is not to be recorded.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब गलत बातों से घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा छलक जाता है तो उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होता। आज इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की जनता को धोखा क्यों दिया ? इन लोगों ने हरियाणा की राजनीति में गलत बातों की गन्दगी क्यों फैलाई ? इन लोगों ने प्रजातन्त्र की मान्यताओं को तोड़ा है और ये लोग पाप के भागीदार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डा० सीता राम : स्पीकर सर, इन्होंने जो पापी शब्द कहें हैं वह कार्यवाही से निकाले जाए।

Mr. Speaker : He has not called "Papi" to a specific person. उन्होंने किसी भी स्पैसिफिक को नहीं कहा है। आप बैठ जाएं। बीरेन्द्र सिंह जी आप कन्टीन्यू करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, ये जो घर में बैठ कर इन्तजार कर रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए और उनको विधान सभा में तशरीफ लाने का मौका मिले। मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि यह मौका नहीं मिलेगा। स्पीकर सर, मेरे भाई भरत सिंह जी ने जो बात कही है, वह बहुत ही मार्के की बात कही है कि हम हरियाणा की राजनीति में ऐसी परम्परा पैदा कर देंगे, सच्चाई और ईमानदारी की परम्परा पैदा कर देंगे कि बंगाल में तो 27 साल तक सी०पी०एम० का राज रहा है और हरियाणा में उससे ज्यादा कांग्रेस का राज रहेगा। आने वाले समय में इन लोगों की हरियाणा में कोई जगह नहीं रहेगी। (विघ्न) स्पीकर सर, मेरे माननीय साथियों ने सदन में अपने बहुत से ख्यालातों का इजहार किया है और अपने सुझाव भी दिए हैं। स्पीकर सर, राधे श्याम जी ने आज सबसे पहले एप्रोप्रिएशन पर बोलना आरम्भ किया था। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि 70 गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। स्पीकर सर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले विधान सभा के चुनावों में वहां के गांव वालों ने चुनावों का बहिष्कार किया था और कहा था कि न तो हम किसी को और किसी भी राजनीति पार्टी को वोट देने देंगे और न ही देंगे। स्पीकर सर, हमें आज इस बात का एहसास है। यह जो 260 करोड़ रुपए से नहर बनाने की बात की गई है तो इस नहर से 2000 क्यूसिक पानी साऊथ हरियाणा में जाएगा। स्पीकर सर, आज हमारे सिंचाई मिनिस्टर और मुख्य मंत्री जी की बढ़िया सोच है जिसमें हम भी शामिल हैं। यह जो बरसातों के मौसम में यमुना का 6-6 लाख क्यूसिक पानी यूं ही बह जाता है उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किस तरह से उस पानी को रोक कर उन किसान लोगों को दिया जाए जहां पर किसानों को पानी की जरूरत है, जहां पर ऊपर वाले की तरफ से भी पानी बरसाने से इन्कार हो जाता है और उस वजह से किसान की फसल भी बर्बाद हो जाती है। स्पीकर सर, आज उन गांवों में ऐसी स्थिति आ गयी है कि लोग उन गांवों को छोड़कर पलायन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथी हबीबउर रहमान जी ने मेवात के बारे में भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि कोटला झील को इस तरह से डिवैल्प किया जाए कि वहां पर पीने के पानी की ही नहीं बल्कि इरीगेशन की जो व्यवस्था है उसको भी सुधारा जा सकता है और बहुत से किसानों को सिंचाई के लिए झील से पानी का इन्तजाम किया जा सकता है। स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन सारी बातों पर गौर करना, चिन्तन करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस बात का कोई न कोई वायबल सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। स्पीकर सर, हर्ष भाई ने कहा है कि मेवात कैनाल के लिए 1991 में 30 करोड़ रुपए रखे गए थे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि मेवात क्षेत्र जो कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मेवात कैनाल उस क्षेत्र के लिए लाईफ लाईन होगी। स्पीकर सर, हम इसको बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम इस समस्या के परमानैंट सोल्यूशन के लिए काम करेंगे ताकि पक्के तौर पर इसका समाधान हो सके। इसके साथ ही सदन में सुभाष चौधरी जी ने भी एक मार्के की बात कही है। जिसका पिछले भाषण में डाक्टर कृष्ण पण्डित जी ने भी जिक्र किया था कि यमुना नगर में जो प्लाईवुड की इण्डस्ट्री है, आज वह देश की सबसे प्रमुख इण्डस्ट्री है। अगर किसान को पोपुलर और सफेदा का न्यूनतम समर्थन मूल्य

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

नहीं मिलता तो किसान को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जिस तरह से गेहूं का न्यूनतम मूल्य, गन्ने का न्यूनतम मूल्य होता है तो पोपुलर और सफेदा भी कृषि का ही एक उत्पाद है क्योंकि किसान अपने खेत में इसको पैदा करता है जंगल में नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मद्देनजर चाहते हैं कि भारत सरकार भी इस बात का अहसास करे कि पोपुलर की खेती और यूकेलिप्टस की खेती अब फोरेस्ट की खेती नहीं है बल्कि यह किसान की खेती है इसलिए उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2002 के बाद जो फैक्ट्री खुली हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे और उनका केस भारत सरकार तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि जगाधरी की म्यूनिसिपल कमेटी के हरियाणा के होम डिपार्टमैंट की तरफ एक करोड़ 80 लाख रुपये डिवैल्पमैंट चार्जिज के बकाया हैं। अध्यक्ष महोदय, यह उनका मानना सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर यह पैसा उस म्यूनिसिपल कमेटी को मिलेगा तो उसकी हालत में सुधार होगा। इसी तरह से ए०सी० चौधरी जो अब चले गए हैं, ने कहा कि एल०ए०डी०टी० का जो शेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन फरीदाबाद का है, वह उसको नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह बात कही है कि अब की बार म्यूनिसिपल कमेटीज का या कारपोरेशन का जितने धन का प्रावधान हमने अपने बजट में किया है उतना कभी नहीं हुआ है। यह ऐसा पैसा है जो उनके पुराने हिसाब किताब तय करने के लिए, कैपीटल असैटस को मेनटेन करने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा भी हम यह समझते हैं कि शहरों के विकास के लिए हमें और काम करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि पुरानी सरकार की अपनी प्राथमिकताएं रही हों। मैं उनका यहां पर ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय तो चौटाला साहब यह भी कहते थे कि व्यापारी को और नीबू को जितना निचौड़ो उतना ही ठीक रहता है लेकिन हमारी यह नीति नहीं है। (विघ्न) मैं यहां पर ए०सी० चौधरी साहब को यह बताना चाहूंगा कि उनको अब इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से इनैलो के विधायक ईश्वर सिंह पलाका ने भी कुछ सुझाव रखे हैं। उन्होंने अनएम्प्लायमैंट एलाउंस के बारे में कहा है कि इसको बंद कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं हैरान हूं कि चौटाला साहब ने लाऊ देवीलाल के जन्म दिन पर यह ऐलान किया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनकी इस स्कीम की एनाउंसमैंट के बाद भी जब तक उनका राज रहा, वे तीन करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा नहीं बांट सके जबकि हमने 105 करोड़ रुपये का इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। कौन कहता है कि हमने यह बंद कर दिया है। हम आपकी तरह सौ रुपये देकर उनको बेइज्जत नहीं करना चाहते हैं। (विघ्न)

डा० सुशील इंदौरा : आप यह बताएं कि आपने इसके लिए कितना प्रावधान किया है। आप इसको क्लीयर कर के बता दें। आप बता दें कि आप बेरोजगार को सौ रुपये दे रहे हैं या पांच सौ रुपये दे रहे हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा आपने किया है। आप ही बता दें। हम आपकी बात मान लेंगे। आपने फिर सौ रुपये क्यों दिया आप ही बता दें कि कितना देना चाहिए ?

डा० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से कहा, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवकों को खासकर माननीय संसदीय कार्यमंत्री बैठे हैं उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिन 27000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था उनको वापस लिया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आई०जी० शेर सिंह जी ने कहा कि पुलिस की भर्ती में हाइट बढ़ा दी गई थी उसको रिव्यू करने के लिए कहा है, जो सही बात होगी उस पर हम जरूर विचार करेंगे। इसी तरह नरेश मलिक ने भी यह बात कही है कि जो जैविक खाद है उसको सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह सही है कि कृषि क्षेत्र में नये प्रयोग करने की, नयी तकनीक, नये बीज की और इन सबको मिलाकर उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है मेरा अपना मानना है कि जब तक कृषि के अंदर उत्पादन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, Sir, I confes that the increase in agricultural production, if it is found below 2%, then we are going to face a crisis in future. इसके लिए हमारे को कुछ ऐसे स्टैप्स लेने पड़ेंगे। जिनकी हमारे को जरूरत है। कौशिक साहब राई से हमारे विधायक हैं, इन्होंने भी यह कहा है कि मिनिमम वेजिज को 2200 रुपये से बढ़ाना चाहिए। यह सही है कि हरियाणा के अंदर आज इसकी बहुत जरूरत है हमारे जो वर्कर हैं, जो गरीब हैं, जिनका गांव में काम छूट गया है और शहर में 2200 रुपये महीने में काम करके उनका गुजारा नहीं चल सकता, इसके लिए हमने मिनिमम वेजिज बोर्ड गठित करने की कार्यवाही शुरू की है। हम यह चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं, हरियाणा में उनको अच्छा पैसा मिले एवं सम्मान से मिले। जब मैं पहली बार विधान सभा में आया था तो पिम्परी के अंदर एक दवाईयों का कारखाना था, was surprised to see that every worker of Pimpri of that industry, had the scooter whether he was Class-IV or the other. मुझे बड़ा अचरज हुआ था उस कारखाने में सबको एक नजर से देखा जाता था चाहे वह फोर्थ क्लास हो चाहे क्लास वन हो सबके पास स्कूटर था मिनिमम वेजिज बोर्ड का महकमा मेरा है, मुझे इसकी चिन्ता है। It is my baby. I am very much concerned of this. कौशिक जी की बात बिल्कुल सही है। इसके साथ-साथ मैट्रो रेल की बात भी आई है। उसके बारे में हमने बजट स्पीच में स्पष्ट किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी बात स्पष्ट की है कि दिल्ली के 3-4 रास्तों पर सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव में मैट्रो की सेवा उपलब्ध हो। अमीर चंद मक्कड़ ने अपनी कुछ समस्याओं का जिक्र किया है और छत्तर पाल सिंह के साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है और मंत्री जी ने इसका नोटिस भी लिया है। इसी तरह से परमवीर सिंह जी ने ड्रेनवाटर की कुछ प्रौब्लम है, उसके बारे में बात की है। हर्ष कुमार की बात का मैं जवाब दे चुका हूँ शकुंतला भगवाड़िया जी के इलाके में जो साइंस फैकल्टी थी उसको विदड्रा कर लिया। हम तो हिस्ट्री और पौलिटिकल साइंस पढ़कर वकील बने लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षा की नई पद्धति और नई तकनीक जिससे कि काम मिल सके जब तक यह तकनीक हम अपनायेंगे नहीं हरियाणा तरक्की नहीं कर सकता, यह हकीकत है। इसके साथ-साथ स्पीकर महोदय, एक बात सर्वसम्मति से कही गई जिसका मैं तो जवाब नहीं दे सकता, हां मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात जरूर ले आऊंगा कि सभी एम०एल०एज़ कहते हैं कि हमें भी कुछ दो वरना मामला गड़बड़ा जायेगा । ये सभी सम्मानित साथियों ने विचार व्यक्त किए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी की सलाह लूंगा कि आगे कुछ देंगे या नहीं देंगे। ये यहां कुछ कहते हैं और वहां कुछ कहते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं यह समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि अन्दाजे से ऊपर ही देंगे बीच में काम नहीं छोड़ेंगे। वाटर कोर्सिस जो टूटे हैं उनको नये बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि पिछली

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

सरकार एच०आर०डी०एफ० का पैसा किसानों के हर काम पर लगाती थी लेकिन पिछली सरकार ने जाते समय यह प्रावधान बन्द कर दिया था। पिछले 8 वीक से यह पैसा बन्द पड़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस को ठीक करें और जहां पर चैनल टूटे हुए हैं उनको काडा के माध्यम से बनायें क्योंकि इसका 50 प्रतिशत पैसा तो केन्द्र सरकार से मिलता है। मैं एक बार फिर सदन के साथियों से यह कहूंगा कि राजनीति साफ करें, गन्दी राजनीति को छोड़िये जो इसमें गलत काम है , जो इसमें पाप हैं, उसके भागीदार मत बनें। सच्चाई की राजनीति करके तो जनता कभी माफ भी कर देगी वरना कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Spkeer : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 2.00 p.m. on Monday the 20th June, 2005.

14.35 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 20th June, 2005).

40708—H.V.S.—H.G.P., Chd.